वैश्विक संवाद

6.4

17 भाषाओं में एक वर्ष में 4 अंक

पत्रिका

International Sociological Association

समाजशास्त्र, राजनीति एवं शक्ति

एंथोनी गिडिन्स

ग्रीस की आर्थिक मंदी

वसीलस के फोसकास,
मारिया मरकन्तोन्ताओ,
जॉन मिलियोस,
स्पाइरोस सकेलारोपोलास,
स्त्रातोस जियोरगुलास

लेटिन अमेरिका में गर्भपात

जूलिया मैक रेनाल्ड्स–पेरेज,
सुसान लर्नर, लूसिया मेलगर
एग्नेस गिल्यूम,
इरिका बूस

अरब जगत में समाज विज्ञान

मोहम्मद ए. बेमयेह,
सेतेनी शमी,
इदरिस जेबारी

विशिष्ट कॉलम

> मेकडानल्डाईजेशन और प्रोस्मपशन पर जार्ज रित्ज़र

> अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र के साथ 40 वर्ष से अधिक

> द्वितीय जापानी संपादकीय दल का परिचय

GD
अंक 6 / क्रमांक 4 / दिसम्बर 2016
www.isa-sociology.org/global-dialogue/

> सम्पादकीय

पीछे देखते हुए, आगे देखते हुए

यह अंक वैश्विक संवाद के पिछले छः वर्षों और चमकदार सामाजिक आंदोलन – इंडिगनाडोस, कब्जा करो, अरब स्प्रिंग इत्यादि से लेकर दक्षिण पंथी आंदोलन जिन्होंने मिस्र, तुर्की, हंगरी, फिलीपीन्स, अर्जन्टीना और ब्राजील में सत्तावादी शासनों को स्थापित किया के उतार चढाव पर विचारते हुए लगातार पीछे और आगे देखता है। यह वैश्विक रूझान आंशिक रूप से राष्ट्र–राज्यों पर अनावश्यक दवाब डालने वाले अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के तूफान में देखा जा सकता है। यह तूफान सरकारी स्वायत्तता को खत्म कर अधिकारिक चुनावी राजनीति को बदनाम कर दोनों, दक्षिणपंथी और वामपंथीयों के, यद्यपि दक्षिणपंथियों का अधिक, लोकलुभावनवाद को अग्रेषित करता है।

अतः यह सही है कि हम इस अंक को एंथोनी गिडिन्स, सिद्धान्तकार और जिसे उन्होंने एक बार ''वैश्वीकरण का वाहन'' कहा था के प्रचारक, के साक्षात्कार से प्रारम्भ करते हैं। अपने राजनैतिक गणवेश में, हाउस ऑफ लार्ड्स के सदस्य के रूप में, वे उन मुद्दों की लगातार हिमायत करते हैं जो उन्हें समाजशास्त्री के रूप में चिंतित करते थे–जलवायु परिवर्तन और डिजीटल युग के परिणाम जैसे मामले।

वैश्वीकरण का दूसरा पक्ष सीरिजा के भाग में अभिव्यक्त दिखाई देता है। वह आंदोलन जिसने इ. यू. को लगभग घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था लेकिन अंत में सत्ता के पलटने से, ग्रीस को घुटने पर ला दिया। यहाँ हम पाँच लेख प्रकाशित करते हैं जो ग्रीस पर यूरोपीय संघ द्वारा थोपी गई मित्तव्यत्तता के विनाशकारी परिणामों का वृतान्त बताते हैं। वे ग्रीस के लिए अनकही गरीबी लेकिन उसके उच्च वर्ग के लिए अनकही धन सम्पदा का निर्माण करते हैं। लेतिन अमरीका में, एक दशक या उससे अधिक सामाजिक लोकतंत्र के प्रतिक्रिया के रूप में–तथा कथित पिंक लहर–देश दर देश दक्षिणपंथी झुकाव के आग हार रहे हैं, देखी जा रही है। यहाँ हम परिवर्तन की हवा, पर तीन लेख का प्रकाशन कर रहे हैं जो गर्भपात के आसपास के संघर्ष में दिखाई देते हैं। अर्जन्टीना, मेक्सिको और पेरू में नवाचारी प्रतिरोध ने राज्य के साथ मुठभेड़ की है। गर्भाधान को रोकने या व्यवधान डालने वाली समान दवाई पर और उसके इस्तेमाल पर झगड़ा विशेष रूप से रोचक है।

अरब सामाजिक विज्ञान के भविष्य पर हमारे पास तीन परिप्रेक्ष्य हैं। चर्चा मोहम्मद बामयेह द्वारा विषय की अवस्था पर लिखित पहली रिपोर्ट से प्रारम्भ होती है। वे परिचर्चा को एक सारांश निबन्ध से प्रारम्भ करते हैं जो सेतेने शामी द्वारा सामाजिक विज्ञान अवसंरचना के परिवर्तन के महत्व पर बल देने वाले लेख से अनुसरित होता है। इदरिस जेबारी अरब स्प्रिंग और उसके समाप्ति के विवक्षा पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं और इस बात की संभावना कि अरब स्प्रिंग समाज विज्ञान को चेतनत्व और नई दिशा प्रदान करता रहेगा, को बढ़ाते हैं।

हम विख्यात समाजशास्त्री जार्ज रित्जर के साथ साक्षात्कार का एक अंश प्रकाशित कर रहे हैं जो कोसोवो से एक युवा और उद्यमी समाजशास्त्री लेबिनोत कुनुशेव्की द्वारा लिया गया था। एडवर्ड तिरयाकियान हमें आई एस ए की 1974 से होने वाली कांग्रेस की अपनी यादों से हमें अतीत की झलक दिखलाते हैं। हम सतोमी यमामोतो के नेतृत्व में जापानी संपादकीय दल के परिचय के साथ अंत करते हैं। सतोमी अपने विद्यार्थियों को अनुवाद की ललक को समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस संदर्भ में, मुझे वैश्विक संवाद का 17 वीं भाषा–बंगाली में अनुवाद की घोषणा करने में खुशी महसूस हो रही है। बंगाली भाषा में अनुवाद ढाका (बंगलादेश) में स्थित एक उत्साही टीम हो हबीबुल खोंडकर की अगुआई में कार्य करेगी, द्वारा किया जायेगा।

> ***वैश्विक संवाद*** को आईएसए वैबसाइट पर 17 भाषाओं में देखा जा सकता है।
> प्रस्तुतियां (Submissions) burawoy@berkeley.edu पर प्रेषित की जा सकती हैं।

एंथोनी गिडिन्स, *अग्रणी ब्रिटिश समाजशास्त्री एवं विचारक, अब हाउस आफ लॉर्ड्स में राजनेता, राजनीति में एक समाजशास्त्री होने की चुनौतियाँ बताते हैं।*

ग्रीस की आर्थिक मंदी।
पाँच लेख इ.यू. में ग्रीस की निरंतर सदस्यता की शर्तों पर उच्च स्तरीय यूरोपीय वार्ता के परिणाम का वर्णन करते हैं।

लेटिन अमेरिका में गर्भपात।
अर्जेन्टीना, मेक्सिको और पेरू में गर्भपात पर संघर्ष का वर्णन करते तीन लेख।

GD

Global Dialogue is made possible by a generous grant from **SAGE Publications.**

> Editorial Board

Editor: Michael Burawoy.

Associate Editor: Gay Seidman.

Managing Editors: Lola Busuttil, August Bagà.

Consulting Editors:
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamín Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

Regional Editors

Arab World:
Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Argentina:
Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

Bangladesh:
Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Eashrat Jahan Eyemoon.

Brazil:
Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral, Benno Alves, Julio Davies.

India:
Ishwar Modi, Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

Indonesia:
Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana.

Iran:
Reyhaneh Javadi, Abdolkarim Bastani, Niayesh Dolati, Marjan Namazi, Vahid Lenjanzade.

Japan:
Satomi Yamamoto, Yutaro Shimokawa, Shinsha Kameo, Mizuki Ichikawa, Hayato Ishihara, Hiroki Kawabata, Hiromi Murakami, Kenta Kajitani, Kento Kusudo, Hirotaka Tanaka, Chiye Yamada.

Kazakhstan:
Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Gani Madi.

Poland:
Jakub Barszczewski, Adrianna Drozdrowska, Krzysztof Gubański, Justyna Kościńska, Kamil Lipiński, Mikołaj Mierzejewski, Karolina Mikołajewska-Zając, Adam Müller, Zofia Penza, Teresa Teleżyńska, Anna Wandzel, Justyna Zielińska, Jacek Zych.

Romania:
Cosima Rughiniş, Corina Brăgaru, Nicoleta-Mădălina Ailincăi, Costinel Anuţa, Adriana Bondor, Alexandra Ciocănel, Tatiana Cojocari, Andrei Dobre, Iulian Gabor, Ştefania Cristina Ghiocanu, Alexandra Isbăşoiu, Rodica Liseanu, Mădălina Manea, Anca Mihai, Andreea Elena Moldoveanu, Rareş-Mihai Muşat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Ion Daniel Popa, Ioana Silistraru, Eliza Soare, Adriana Sohodoleanu, Diana Tihan, Elena Tudor, Carmen Voinea, Raisa-Gabriela Zamfirescu.

Russia:
Elena Zdravomyslova, Anna Kadnikova, Asja Voronkova.

Taiwan:
Jing-Mao Ho.

Turkey:
Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

Media Consultants: Gustavo Taniguti.

> इस अंक में In This Issue

सम्पादकीय : पीछे देखते हुए, आगे देखते हुए **2**

समाजशास्त्र, राजनीति और सत्ता : एंथोनी गिडिन्स के साथ एक साक्षात्कार
पीटर कोलार्ज, यू. के. **4**

> ग्रीस की आर्थिक मंदी

ग्रीस : भू–राजनीति और दिवालियापन का इतिहास
वसीलस के फोसकास, यू. के. **7**

ग्रीस में राज्य द्वारा थोपी गई मित्तव्यत्तता
मारिया मरकन्तोन्ताओ, ग्रीस **10**

सीरिजा : विनाश से व्यवहारिकता की तरफ
जॉन मिलियोस, ग्रीस **12**

यूनानी वित्तीय संकट में विजयी और पराजित
स्पाइरोस सकेलारोपोलास, ग्रीस **15**

राज्य–कार्पोरेट अपराध के रूप में ग्रीक बेल आउट
स्त्रातोस जियोरगुलास, ग्रीस **17**

> लेटिन अमेरिका में गर्भपात के लिए संघर्ष

माइसोप्रोस्टॉल के युग में अर्जेंटीना का गर्भपात आंदोलन
जूलिया मैक रेनाल्ड्स–पेरेज, अमेरिका **19**

मैक्सिको के गर्भपात अधिकारों में परिवर्तन
सुसान लर्नर, मेक्सिको, लूसिया मेलगर, मेक्सिको एवं
एग्नेस गिल्यूम, फ्रांस **22**

हिंसा के रूप में गर्भपात : पेरू का संघर्ष
इरिका बूस, पेरू **24**

> अरब जगत में समाज विज्ञान

अरब जगत में समाज विज्ञान
मोहम्मद ए. बेमयेह, यू.एस.ए. **26**

अरब क्षेत्र में समाज विज्ञान की नई अवसंरचनायें
सेतेनी शमी, लेबनान **28**

अरब समाज विज्ञान : बसन्त से पहले एवं परे
इदरिस जेबारी, लेबनान **31**

> विशिष्ट स्तम्भ

मेकडानल्डाईजेशन और प्रोस्मपशन पर जार्ज रित्जर
लेबिनोत कुनुशेव्की, कोसोवो **34**

अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र के साथ 40 वर्ष से अधिक
एडवर्ड. ए. तिरयाकियान, यू.एस.ए. **36**

द्वितीय जापानी संपादकीय दल का परिचय **38**

> समाजशास्त्र, राजनीति और सत्ता

एंथोनी गिडिन्स के साथ एक साक्षात्कार

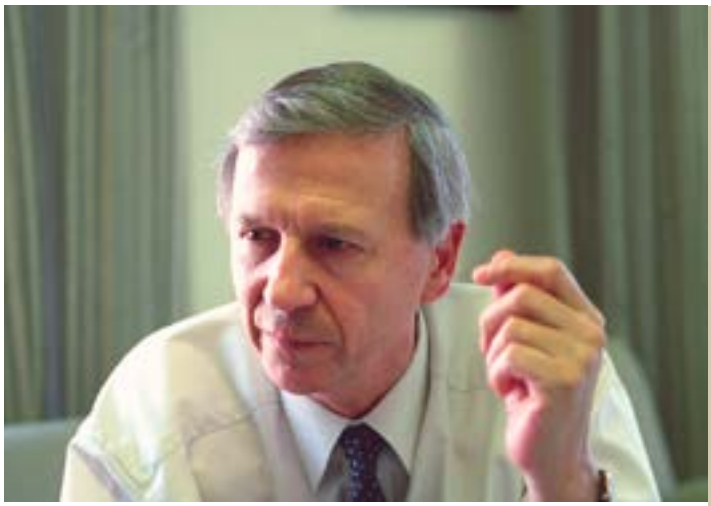

एंथोनी गिडिन्स

1970 के दशक में **एंथोनी गिडिन्स** ने सामाजिक सिद्धान्त पर अगुआ पुस्तकों, जिन्होंने शास्त्रीय कृतियों की आधुनिक काल में पुर्नव्याख्या की, के लेखन के साथ ब्रिटिश समाजशास्त्र के पुर्नजन्म का नेतृत्व किया। उन्होंने संरचित विश्व में एजेन्सी, सूक्ष्म प्रक्रियाओं को वृहद शक्तियों से जोड़ना और दैनिक जीवन में वैश्वीकरण की प्रासंगिकता के प्रश्न का विच्छेदन किया। हाल ही में उन्होंने डिजीटल क्रांति के परिणामों और मानवीय अस्तित्व को जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों को भी संबोधित किया है। वे 30 से भी अधिक पुस्तकों के लेखक, लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के पूर्व निदेशक एवं एमेरिटस प्रोफेसर और 2004 से हाउस ऑफ लार्ड्स के सदस्य हैं। नीचे वर्णित साक्षात्कार में वे राजनीति में समाजशास्त्र के स्थान पर प्रकाश डालते हैं।

पीटर कोलार्ज ने ससेक्स विश्वविद्यालय (यू. के.) से समाजशास्त्र में पी. एच. डी. की डिग्री अर्जित की है। वे टेकनोपोलिस समूह में नीति अनुसंधान सलाहकार हैं और उन्होंने यू. के. के कई मंत्रालयों और यूरोपीय संघ के साथ अन्य के लिए कई नीति अध्ययनों और मूल्यांकन रिपोर्ट का लेखन किया है। उनकी पुस्तक गिडिन्स एण्ड पॉलिटिक्स बियोन्ड द थर्ड वे : यूरोपियन रियलिज्म इन द लेट माडर्न एज (2016) का प्रकाशन पालग्रेव मेकमिलन द्वारा किया गया है। यह साक्षात्कार 8 जून 2016 को हाउस ऑफ लार्ड्स (यू. के.) में सम्पन्न हुआ।

पी.के. : आपने विषयों की विस्तृत श्रंखला : संरचनात्मक सिद्धान्त, ऐतिहासिक भौतिकवाद, पछेती आधुनिकता और वैश्वीकरण निजी जीवन और कामुकता में बदलाव, तृतीय मार्ग, जलवायु परिवर्तन, इ. यू. के भविष्य पर लिखा है और हाल ही में आपने डिजीटल क्रांति के बारे में बोलना प्रारम्भ किया है। क्या आप कहेंगे कि आपके कार्यों के इस पुंज में या इनमें से अधिकांश में किसी प्रकार का कोई विद्यमान है?

ए.जी. : मेरा सम्पूर्ण एजेण्डा आधुनिकता की प्रकृति – औद्योगिक व्यवस्था के उद्भव और विश्व में उसका विस्तार, अब तक का सबसे क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी काल, का अध्ययन करना है। मेरे लिये इतिहास काफी असंतत है : इतिहास कोई भी उदविकासीय मॉडल नहीं है जो कार्य करता है। लोग हमेशा विशिष्ट पर्यावरण सामाजिक और भौगोलिक संदर्भों में काम करते हुए जो उनके कार्य को निर्धारित करते हैं, स्थित होते हैं, लेकिन जिनको वे प्रत्युत्तर देते हैं और कई तरीकों से पुनः आकारित करते हैं। मैं दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक विज्ञानों के परिदृश्य, जहाँ हम जानकार व्यक्ति जो हम हैं, के बजाय निष्क्रिय एजेन्ट अधिक प्रतीत होते हैं, को नहीं मानता हूँ। इरविंग गॉफमैन, मेरी समझ में समाजशास्त्रियों में सबसे महान, दैन्य जीवन में लोग क्या करते हैं, आवश्यक रूप से यह बिना जाने कि वे ऐसा कर रहे हैं, की कुशल/दक्ष प्रकृति पर जोर डालते हैं। मेरी आकांक्षा इस परिप्रेक्ष्य को अधिक वृहद संरचनात्मक प्रक्रियाओं से सम्बद्ध करने की रही है। ऐसा करना आसान नहीं है लेकिन मुझे यह महत्वपूर्ण लगता है : पुराने दिनों के समाजशास्त्र के काफी हिस्से ने ऐसा प्रतीत कराया जैसे कि हम बड़े सामाजिक कारकों के सिर्फ खिलौने थे। मैं इनके मध्य के सम्बन्धों की गूढ़ता को उजागर करना चाहता था। यह एक कारण है कि मेरी रूचि हमेशा ही संचार और संपर्क में होने वाले परिवर्तनों में रही है। रोजमर्रा की जिंदगी और पहचान में बदलाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी वृहद स्तरीय व्यवस्थाएँ और समस्याएँ, जिनसे हम निपटने का प्रयास करते हैं।

पी.के. : तो यदि आप के कार्य पुंज में कोई एक तत्व है जिसे आप सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का अध्ययन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वह क्या होगा?

ए.जी. : वह, हम जिस फार्मेट की बात कर रहे हैं, होगा : एक वृहद संरचना के सदस्य होने के साथ ही लोग अपनी जिंदगी का क्या करते हैं, के मध्य अंतक्रिया की अपरिमित गूढ़ता। यह जितना अन्य क्षेत्रों में सच है उतना ही राजनीति में भी है। नेकनीयत नीतियाँ कभी भी पर्याप्त नहीं होती और अक्सर पलटा खा सकती हैं।

> >

पी.के. : 2016 की मेरी पुस्तक गिडिन्स एण्ड पॉलिटिक्स बियोण्ड द थर्ड वे में, मैं आपके काल्पनिक यथार्थवाद की अवधारणा को महत्वपूर्ण मानता हूँ। क्या इस अवधारणा को आप आज भी मानते हैं?

ए.जी. : काल्पनिक यथार्थवाद की अवधारणा को मैं आज भी काम में लेता हूँ। सबसे बड़ी चुनौती दो विपरीत चेहरों, काल्पनिक यथार्थवाद को व्यवहारिक राजनीति के साथ जोड़ना है। आदर्शों से विहीन राजनीति निर्देश उद्देश्य के बिना होगी। हमें किसी भी प्रदत्त समय में यथास्थिति के दूसरे तरफ के मामलों की भी परिकल्पना करनी होगी। उसी समय, आदर्श अकेले खाली होते है। काल्पनिक यथार्थवाद की अवधारणा, मुझे, आदर्शों की भूमिका के प्रति हमें संवेदनशील बनाने का एक अच्छा तरीका प्रतीत होती है। एक तरफ इधर उधर के आगे ले जाना लेकिन उसी समय दूसरी तरफ यह दिखाना कि उनकी यथार्थ पर पकड़ है। राजनीति और विश्व के बारे में सोचना एक संवेदनशील तंत्र है। लोकतांत्रिक राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतने पर ध्यान केन्द्रित करने वाली पार्टी वास्तव में कोई चुनाव नहीं जीतती; और न ही वे जिनके पास उदाप्त आदर्श हैं लेकिन वे यह बताने में असमर्थ हैं कि लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं की वास्तविकता से वे कैसे सम्बंधित हैं। हम सब जानते हैं कि इस गोले को चौकोर करना कठिन है।

पी.के. : 1990 के दशक में वैश्वीकरण एवं तृतीय मार्ग पर आपके राजनीतिक कार्य के सम्बन्ध में, यदि आप आज के राजनैतिक और नीति परिदृश्य को देखेंगे तो आपका क्या फैसला होगा? क्या बहस में से कोई ऐसी चीज है जिसे आप अभी भी महत्वपूर्ण मानते हैं और जिसे पर्याप्त रूप से देखा नहीं गया है?

ए.जी. : यह अब स्मरण करना कठिन है लेकिन उस समय वैश्वीकरण की धारणा–अर्थात दुनिया भर के व्यक्तियों संगठनों और राज्यों के मध्य बढ़ती अन्योन्याश्रयता काफी नवीन थी, विशेष तौर पर राजनैतिक संदर्भ में। राजनैतिक नेताओं को इसे गंभीरता से लेने के प्रयास प्रारम्भ में मुश्किल थे। वे मुझे सपाट नजरों से देखते थे। फिर लगभग रातोंरात सब कुछ बदल गया। आप उन्हें इस बारे में बात करने से रोक नहीं सकते थे चाहे वो काफी अशिष्ट स्तर पर हो। दुर्भाग्यवश, अधिकांश राजनेता और कई समाज वैज्ञानिकों ने इस धारणा को वैश्विक बाजारों के विस्तार को आंशिक या पूर्ण रूप से संदर्भित करने के लिए प्रयोग में लिया है। डिजीटल क्रांति के अभूतपूर्व विकास के साथ, वैश्वीकरण की प्रेरक शक्ति सबसे उपर संचार, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक संचार था।

मैंने ''तृतीय मार्ग'' शब्द को कुछ संकोच से प्रयोग में लिया है। मेरे लिये इसका अर्थ लेफ्ट या राइट के मध्य, एक तरह का मध्यम मार्ग, राजनैतिक स्थान विकसित करना नहीं था। मैंने इसे नवउदारवाद के एक संस्करण, आजाद बाजारों की असीमित बुद्धिमत्ता के रूप में भी नहीं देखा। जैसा कि 1998 में अपनी पुस्तक द थई वे में मैंने लिखा, ''वित्तीय बाजारों का नियमन विश्व अर्थव्यवस्था का अकेला सबसे अहम् मुद्दा है।'' मैं तब भी और आज भी सक्रिय सरकार, जिसे हालांकि सिर्फ राज्य के रूप में नहीं देखना चाहिए और यह अन्य एजेन्सियों की श्रंखला से भी आ सकती है, के प्रमाणिक महत्व में विश्वास करता हूँ। मैं तब और आज भी वैश्विक शासन प्रणाली के तंत्र को विकसित करने, यद्यपि यह अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है, में विश्वास करता हूँ।

मेरे लिए असमानता एक प्रमुख मुद्दा था। मैंने जो लिखा है उसको देखने की जहमत उठाने वाला आसानी से यह देख सकता है। धन पिरामिड के शीर्ष पर चरम असमानताओं के उभरने से और उत्पादकता बढ़ाने में विफलता और अतः न्यून वेतन रोजगार में संलग्न लोगों के वेतन वृद्धि में असफलता के कारण यह और भी विशाल हो गया है। थामस पिकेटी की पुस्तक कैपिटल इन द टवेन्टी फर्स्ट सेन्चूरी विश्व–व्यापी रूप से प्रसिद्ध इसलिए हुई क्योंकि यह इन प्रकट विषमताओं को उत्पन्न करने वाले संरचनात्मक कारकों और साथ ही उन्हें कम करने की कुछ संभावी रणनीतियों का सशक्त विवेचन करती हैं।

लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति राष्ट्रीय है और दुनिया वैश्विक है। इसलिए एक मुख्य बात रह जाती है : हमारे पास यह मुद्दा कि हम कैसे राष्ट्रीय राजनीति का एक अंतर्निहित/निहायत वैश्विक दुनिया के साथ सामंजस्य कर सकते हैं। लोकलुभावनवाद के काफी स्त्रोत इस कठिनाई से और इस तथ्य से कि सभी जानते हैं राष्ट्रीय नेताओं के पास वह ताकत नहीं जिसका वे दावा करते हैं, से निकलते हैं।

पी.के. : राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक बदलावों एवं असमानताओं के मध्य इस असम्बद्धता को तोड़ने का आपको कोई तरीका दिखाई देता है?

ए.जी. : हाँ, कोई तरीका होना चाहिए और यूरोप[1] पर मेरी पुस्तक में, मैंनक कर मुक्त देशों के मुद्दे पर संगठित हो कर आक्रमण करने की आवश्यकता और पश्चिमी अर्थव्यवस्था में वि–औद्योगीकरण को उलटने की कोशिशें, जो उत्पादन के पुर्ननिर्माण को अग्रेषित करता है, यद्यपि पूर्व से काफी भिन्न, पर बात की है। यह डिजीटल क्रांति के साथ एक ही समय में होता है क्योंकि एक बार धन इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, उसे दुनिया में कहीं भी तुरन्त स्थानान्तरित किया जा सकता है–यह एक ऐसा कारक है जो कर मुक्त देशों का सामान्य बनाता है। हालांकि इसी तर्क से भ्रष्ट धन के विशाल भंवर को छुपाना पूर्व से अधिक मुश्किल है। मुझे लगता है कि वैश्विक जनमत भी इस विचार के सख्त खिलाफ है कि आप वैश्विक स्तर पर विशाल धन सम्पदा को छुपा सकते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं कि कोई इसकी परवाह न करे।

अभी तक, प्रभावी (लोकतांत्रिक को छोडिये) वैश्विक प्रशासन एक स्वप्न है लेकिन हमारे पास एजेन्सियों की श्रंखला, राष्ट्रों के समूह और अंतराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम रहे हैं। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौतों का परिणाम क्या होगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा : क्या वे निष्फल रहेंगे या नहीं? हम इस समय नहीं जानते लेकिन निश्चित तौर पर वे पूर्व में किये किसी भी लिखित समझौतों से काफी भिन्न हैं। आप उन्हें अभी से ही उनके स्टॉक की कीमतों में गिरावट के साथ जीवाष्म–ईंधन उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हुए देख सकते हैं। निम्न कार्बन उर्जा में एक सच्ची वैश्विक क्रांति होने की संभावना नजर आती है और एक मूल प्रश्न है कि यह कितनी शीघ्र या अन्यथा आगे बढ़ेगा। मार्क्स ने कहा था, ''जो ठोस है वह वायु में पिघल जाता है'' और हम देखेंगे शायद यह उस नियम का एक संस्करण होगा। डिजीटल क्रांति के विकास की रफ्तार, विषय क्षेत्र और तेज गति द्वारा अग्रेषित वैश्वीकरण की नई लहर यहाँ एक मुख्य प्रभाव है।

पी.के. : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा अग्रेषित समय और स्थान के संकुचन के रूप में वैश्वीकरण और उसकी सहयोगी जोखिम और अवसर आपकी कृतियों में बहुधा आने वाले विषय हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन घटनाओं या ''वैश्वीकरण के विशालकाय वाहन की सवारी'' करना संभव है, जैसा कि आपने एक बार, कुछ हद तक रचनात्मक ढंग से, कहा था या हमें ''उसके साथ जाना'' होगा और क्या होता है देखना होगा।

ए.जी. : अपने प्रभाव के संदर्भ में इन्टरनेट एक असाधारण प्रघटना है। यह हमारे द्वारा प्रत्याशित किसी से भी अधिक वैश्विक है। यह आत्म की अतरंगता को वैश्विक से जोड़ता है। हालांकि यह डिजीटल क्रांति का एक ही तत्व है जिसे पूरी तरह से समझा गया है। दूसरे सुपर

>>

कम्प्यूटरस और रोबोटिक्स हैं। मेरे अनुसार सुपर कम्प्यूटरस जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है। आपकी जेब में रखा स्मार्टफोन कुछ दशकों पूर्व के सुपर कम्प्यूटर से अधिक शक्तिशाली है। यह विशाल एलगोरिथम शक्ति सामान्य उपभोगकर्ता को भी उसी प्रकार उपलब्ध है जैसे कि संगठनों, कारोबारियों और राज्यों को। विश्व समाज का लगभग हर पक्ष प्रभावित है और परिवर्तित हो रहा है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ लगभग सब कुछ सबको दृष्टिगोचर समाजों में भी प्रसारित हो गये हैं। उत्पीड़ित क्षेत्रों को छोड़कर अन्यत्र शरण तलाशने वाले प्रवासी अपने वांछित रूट को ट्रेक करने के लिए स्मार्टफोन और जी. पी. एस. का उपयोग कर रहे हैं। यह 21वीं सदी का प्रवास है, वैसे ही जैसे डिजीटल प्रौद्योगिकी में महारत के साथ हिंसा के मध्यकालीन स्तरों का मिश्रण कर 21वीं सदी का आतंकवाद का निर्माण करता है।

कई लोग डिजीटल दुनिया को एक खंडित दुनिया का निर्माण करते हुए देखते हैं लेकिन अधिकांश नवाचार राज्य हस्तक्षेप, अक्सर अर्ध–सैन्य उद्देश्यों के साथ, द्वारा अग्रगामी है। इन्टरनेट क्षणभंगुर/अल्पकालिक प्रतीत होता है लेकिन महासागर में नीचे केबलों के रूप में और आकाश में उपग्रहों के द्वारा इसकी शारीरिक उपस्थिति है। ये चीजें अंततः राज्यों और राज्य शक्ति द्वारा गारण्टी की जाती हैं। इसलिए मेरे अनुसार भू–राजनीति का पुनरूत्थान उतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना सब सोचते हैं। विशालकाय कार्पोरेशन और सर्वव्यापी विज्ञापन भी इसकी चालक शक्तियाँ हैं। यह एक नवीन माहौल है और हमें सबसे अधिक प्रभावित करने वाले परिवर्तन राजनैतिक प्रक्रियाओं से नहीं अपितु राज्य या विशालकाय कार्पोरेशन की ताकतों से प्रभावित होते हैं। किसी ने ऐसी दुनिया के लिए वोट नहीं किया जहाँ अश्लीलता मुक्त भाव से, ''मुक्त'' के दोनों अर्थों में, उपलब्ध हो। यह अहानिकर हो सकता और नहीं भी। हम यह नहीं जानते क्योंकि यह सब काफी नया है।

पी.के. : तो चलिये वर्तमान की राजनीति के बारे में बात करते हैं : क्या आप को इस समय वामपंथ के भविष्य के बारे में कोई रचनात्मक बहस होती हुई दिखाई दे रही है?

ए.जी. : हमें अभी वर्णित रोजमर्रा के जीवन में और विश्व समाज में होने वाले परिवर्तनों से प्रारम्भ होने वाले मध्य वामपंथ के नये संस्करण को प्रारम्भ करने के प्रयास करने होंगे। तृतीय मार्ग की बहस उस समय हमारे जीवन का रूपांतरण करने वाले मुख्य परिवर्तनों के विश्लेषण से उभरी और हमें आज उसी तरह की कवायद से गुजरना होगा। हमें दुनिया में होने वाले बड़े परिवर्तनों इनसे राजनैतिक रूप से क्या कर्षण मिल सकता है, और ये राष्ट्रीय और ट्रांसनेशनल राजनीति के फ्रेमवर्क में कैसे सही बैठते हैं, को अवश्य देखना चाहिए। जेरेमी कोरबयन के आगमन से लेबर पार्टी के भीतर क्या हुआ, यह मेरे लिए एक डिजीटल युवा पीढ़ी प्रत्यक्ष रूप से भागीदार लेकिन विचार जो कुछ भागों में वर्षों पूर्व से निकले हैं, के साथ मिश्रित है।

हम वामपंथियों को भविष्य की तरफ बढ़ना है। हम तथाकथित तृतीय मार्ग की बहस से काफी आगे आ गये हैं, और नये विचारों की तत्काल आवश्यकता है। मैं इस विचार के भी खिलाफ हूँ कि किसी तरह सबकुछ विखण्डित हो गया है – मुझे नहीं लगता कि यह सच है। आप अभी भी शक्ति की राजनीति से व्यवहार कर रहे हो, आप अभी भी वृहद मुद्दों पर बात कर रहे हो, जैसे हम वैश्विक कार्पोरेशन के संदर्भ में अधिक समतावादी समाज कैसे पा सकते हैं, कर मुक्त देशों में जमा बेइमानी के लाभ को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए शक्ति अभी भी काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रों के मध्य सहयोग और अतः राष्ट्रों के मध्य इ. यू. के मध्य लोकतांत्रिक राजनीति, काफी महत्वपूर्ण है।

पी.के. : यह मुझे मेरे आखिरी प्रश्न की तरफ ले जाता है। अधिकांश से अधिक सफलतापूर्वक, आप शैक्षणिक जगत से औपचारिक राजनीति में चले गये। राजनीति में एक समाजशास्त्री होने पर आपके विचार क्या हैं, इसके बारे में जानने की मेरी इच्छा हैं और इसी संबंध में, क्या आपके पास उन समाज वैज्ञानिकों के लिए कोई विशिष्ट सलाह है जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके कार्यों का राजनैतिक कर्षण हो, जो इस तरह की जगहों में होने वाली चीजों को प्रभावित करने में रूचि रखते हैं।

ए.जी. : मैं राजनीति में हूँ लेकिन राजनीति का नहीं हूँ। मैं एक शिक्षाविद् था और शिक्षाविद् ही रहूँगा। मेरे लिए सबसे अच्छा परिवेश विश्वविद्यालय है चूँकि यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा घर जैसा आराम महसूस करता हूँ और जैसा कि मैंने बल देने का प्रयास किया है, विचार और सर्वजनोपयोगी अनुसंधान राजनैतिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीति में संलग्न किसी शिक्षाविद के लिए एक मुख्य समस्या है कि आप अपने दोनों क्षेत्रों से सम्पर्क खो देते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में आपने अपनी शैक्षणिक तटस्थता को धोखा दिया है जबकि राजनेताओं के लिए आप वह हैं जिन्हें दैन्य राजनैतिक जीवन की माँगों का कोई अनुभव नहीं हैं। दोनों दुनिया के मध्य आप बहुत आसानी से फँस सकते हैं।

शैक्षणिक जगत और राजनैतिक दुनिया बहुत अलग हैं और बहुत कम लोग उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पाटने की कोशिश करते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र और राजनीति के बीच थिंक टैंक एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे विश्वविद्यालयों में होने वाले अनुसंधानों पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। वे अकादमिक शोध को व्यावहारिक नीति प्रस्तावों में बदलने का कार्य करते हैं और सामान्य तौर पर शिक्षाविदों से अधिक मीडिया से निकट संपर्क होते हैं। शीर्ष संस्थान अक्सर तत्कालीन सरकारों के या फिर राजनेताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के निकट संपर्क में होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यही एक मार्ग है, लेकिन 1990 के दशक के मध्य में जब मैंने अधिक सीधी तौर पर राजनीति के साथ जुड़ने का निर्णय लिया, मैंने इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पोलिसी रिसर्च (IPPR) – एक या शिक्षाविद जिनके बारे में मुझे पहले ही पता था कि वे उसके साथ जुड़े हुए हैं, को संपर्क किया। वहाँ से, मुझे राजनैतिक क्षेत्र के लोगों के व्यापक नेटवर्क को विकसित करना संभव लगा। IPPR और उसके ईर्द गिर्द व्यापक नेटवर्क के अमरीका सहित अन्य देशों में अच्छे संबंध थे। यद्यपि मैं किसी का भी औपचारिक राजनैतिक सलाहकार नहीं बना और मैंने अपने आप को प्राथमिक रूप से शिक्षाविद के रूप में देखना जारी रखा। ■

एंथोनी गिडिन्स से पत्र व्यवहार हेतु पता <Ax.Giddens@lse.ac.uk>

पीटर कोलार्ज से पत्र व्यवहार हेतु पता <kolarz.peter@gmail.com>

[1] Giddens, A. (2014) *Turbulent and Mighty Continent* (second edition). Cambridge: Polity.

> ग्रीस : भू–राजनीति और दिवालियापन का इतिहास

वसीलस के फोसकास, ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय, यू. के.

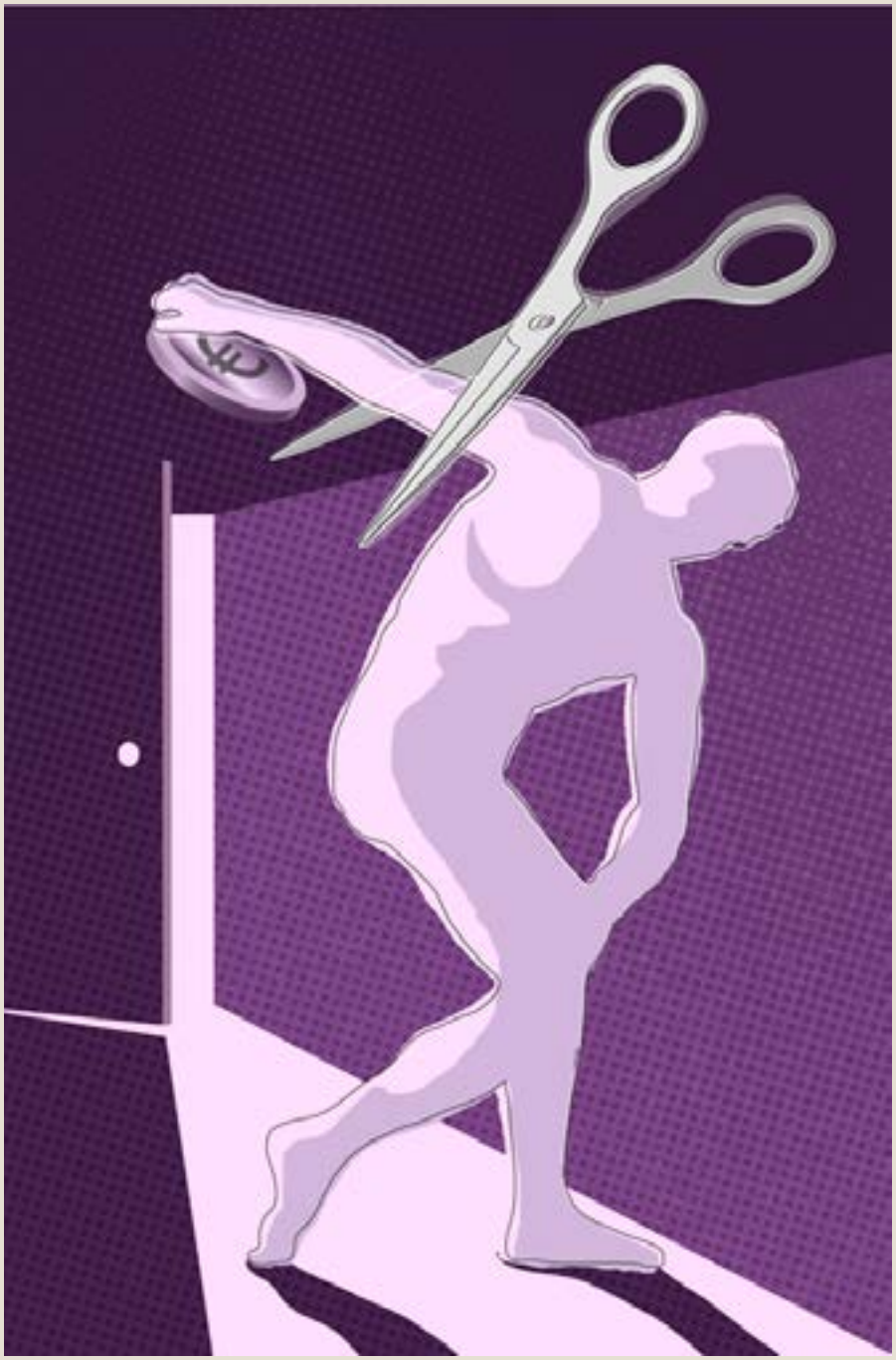

डिस्कस के बजाय दिवालियापन यूनानी इतिहास का प्रतीक। अर्बु द्वारा चित्रण

पेलोपानिस, दक्षिण रूमेलिया, युबोइआ, और साइक्लेडस द्वीप के संकुल के साथ मिलकर बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी शंकु में 1830 में स्थापित, ग्रीक राज्य एक आर्थिक रूप से विस्तृत होती राष्ट्रीय औद्योगिक बुर्जुआ के बजाय एक साम्राज्यवादी भू–राजनैतिक दुर्घटना का परिणाम है। उत्पादन के सामन्ती तरीकों के खिलाफ औद्योगिक पूंजी द्वारा अग्रेषित राष्ट्रीय–क्रांतिकारी प्रक्रियाओं का परावर्तित करने के बजाय–उदाहरण के लिए जैसा प्रशियन जकर्स या इटली का पीदमोण्ट का मामला था – पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा सीमित ग्रीक राज्य को एक भू–सामरिक आवश्यकता के रूप में देखा गया। यह पूर्वी भूमध्यसागर में रूस और मिस्र के क्षेत्रीय विस्तार को रेकने के प्रयासों का हिस्सा था। ग्रीस की उत्पत्ति में भू–राजनैतिक कारक सर्वोपरि थे, और आज, भू–राजनैतिक/भू–सामरिक प्रश्न ग्रीक कर्ज संकट की ऐतिहासिक उत्पत्ति को समझने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक ग्रीक राज्य की स्थापना के बाद से, ग्रीस की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति को पश्चिम ने ग्रीक समाज की भलाई के लिए नहीं अपितु अपने स्वयं के लाभ के लिए काम में लिया।

> >

> वैश्विक वित्त से उन्नीसवीं सदी के संबंध

ऑटोमोन के खिलाफ आजादी की लडाई का संचालन करने के लिए, ग्रीक श्रेष्ठि ने पश्चिम से बड़ी मात्रा में राशि उधार ली। 1820 के दशक में ग्रीस ने यूरो 800,000 और 2 मिलियन के दो ऋण लिये। एक आदिम ग्रीक राज्य तंत्र ने अपना पहला दिवालियापन 1824–25 में अनुभव किया जब वह फ्राँस और इंग्लैंड से लिये गये कर्ज को चुका नहीं पाया। 1832–33 में 60 मिलियन (गोल्डन फ्रेंक में) का एक और ऋण अनुबंधित किया गया और उसे पूरी तरह से राजशाही के खर्चों और सेना के रखरखाव के लिए काम में लिया। इस कर्ज की वजह से 1843 में पुनः ग्रीक दिवालियापन की स्थिति बनी।

1827 और 1877–78 के मध्य, ग्रीस को पश्चिमी वित्त बाजारों से दूर रखा गया। इन पाँच दशकों में और इसके बाद, सरकारों ने धनढ़य प्रवासी ग्रीक जिनकी कम्प्रदार पूंजी, यहूदी और आर्मिनाई व्यापारी वर्ग के साथ ऑटोमोन साम्राज्य में प्रमुख थी, को निवेश प्रोजेक्ट के लिए प्रोत्साहित करते हुए आंतरिक उधार (यद्यपि असफलता से) का सहारा लिया। औद्योगिक विकास के न्यून स्तरों और अपने लघु आकार के कारण बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में भाग लेने में असमर्थता के साथ, उन्नीसवीं सदी के दौरान ग्रीस पिछड़ी परिधीय अर्थव्यवस्था और गहन रूप से निर्भर राजनीति के रूप में चिन्हित था। 1893 में ग्रीस ने फिर दिवालिया होने की घोषणा की।

तथापि, अपने कमतर वित्तीय संसाधनों और अपरिष्कृत बैंकिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बावजूद, ग्रीस हमेशा पश्चिमी ताकतों द्वारा उनके साम्राज्यवादी भू–राजनैतिक हितों के चश्में से देखा गया। आस्ट्रो–हंगरियन और ऑटोमोन साम्राज्यों के पीछे हटने के साथ रूस एवं पश्चिमी यूरोपीय साम्राज्यवाद के लिए नये स्थान खुले, जो अब नये देश, जैसे जर्मनी और इटली द्वारा पुनः प्राप्त किये गये। ईसाई बाल्कन सूक्ष्म राज्यों ने पश्चिम को शानदार अवसर प्रदान किये। ऐसा उन्होंने ऑटोमोन तुर्की से खिलाफ चल रहे युद्ध में प्राक्सी प्रदान कर के किया। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक, ऑटोमोन यूरोप के बाहर खदेड़ दिये गये और बाल्कन/पूर्वी यूरोप और पास/मध्य–पूर्व की सीमाओं को पुनः आकारित किया गया।

भूमि पर विजय प्राप्त कर और आबादी–जिसमें सब ग्रीक नहीं थे, को समाविष्ट कर, ग्रीस ने बीसवीं सदी की पहले दो दशकों में एलेफ्थेरियोस वेनिजेलोस के उदार–राष्ट्रवादी नेतृत्व में पर्याप्त औद्योगिक गतिविधी को देखा। ब्रिटिश समर्थन के तहत वेनिजोलस ने एशिया माइनर में केमलिस्ट–राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ हारा हुआ छदम् युद्ध का नेतृत्व किया। इसका परिणाम ग्रीस और तुर्की दोनों के लिए भयानक था। यद्यपि ग्रीस ने लगभग 1.4 मिलियन ईसाई शरणार्थियों के आगमन के प्रवाह को देखा, इसने अपने इतिहास में पहली बार नस्लीय एकरूपता को अर्जित किया। जबकि अपनी सबसे अधिक उद्यमी व्यापारी वर्ग को खोने के बाद, तुर्की ने राज्य द्वारा अग्रेषित आर्थिक विकास के स्वरूप पर काफी ज्यादा भरोसा किया और नस्लीय या धार्मिक समरूपता प्राप्त करने में विफलता पाई।

स्वस्थ आर्थिक आधार के बिना और अपने सत्तारूढ़ राजनैतिक कुलीन के साम्राज्यवादी हितों के साथ निकटता के जुड़े ग्रीस अपने भू–सामरिक लाभों को भुना नहीं पाया। अतः इसकी भौगोलिक स्थिति एक बनने की बजाय स्थाई दायित्व बन गई। यह स्थिति सीधी तौर पर भुगतान संतुलन की समस्या जिसने एक ग्राहकीय एवं भ्रष्ट राज्य तंत्र को फंड करने हेतु लगातार आन्तरिक उधारी के साथ जुड़कर बारंबार अरक्षणीय उधार का उत्पादन किया।

> 1929 का वित्तीय संकट और उसके परिणाम

1929 के वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप, ग्रीस ने स्वयं को 1932 में चौथी बार दिवालिया घोषित किया। उसके पश्चात, तानाशाह आयोनिस मेताक्सास ने आयात–प्रतिस्थापन औद्योगीकरण की नीति अपनाई जिसने देश के भुगतान संतुलन में सुधार किया। इसके अलावा, साम्राज्यवाद की मशाल जैसे ही नये वैश्विक प्राधान्य यू एस ए को प्रदान की गई, शीत युद्ध ने लाभांश प्रदान किये : ग्रीस के भू–राजनैतिक महत्व ने बड़ी मात्रा में अमरीकी पूंजी और लोन की गारण्टी दी और 'पूंजीवाद के स्वर्णिम युग' में ग्रीस के घरेलू वाम साम्यवादी शक्तियों को हाशिये पर कर दिया।

फिर भी, एक बार फिर ग्रीस हाशिये पर और गहन रूप से निर्भर रहा। विशेष तौर पर 1960 के दशक में जब बैंक ऑफ ग्रीस के गर्वनर, जेनोफोन जोलाटास एथेन्स में अमरीकी राजदूत से लोन माँगने गये, राजदूत ने भू–राजनैतिक संघर्ष की तरफ संकेत कर जवाब दिया। प्रभावी रूप से, राजदूत ने कहा कि यदि ग्रीस को लोन चाहिए तो उसे डीन अचेसन की साइप्रस के लिए योजना को स्वीकार करना होगा। यह योजना NATO शक्तियों के मध्य गुपचुप रूप से तैयार की गई थी जिसमें ग्रीस एवं तुर्की के मध्य द्वीप के विभाजन का प्रस्ताव था। इस तरह आर्कबिशप मकारियोस जो उस समय साइप्रस के निर्वाचित नेता और निर्गुट आंदोलन के संस्थापक थे, से मुक्ति पाने की योजना थी। अतः भू–राजनैतिक मामला और कर्ज की समस्या को एक सीधी अदला बदली से निपटाया गया। साइप्रस NATO और पश्चिम के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि CIA के माध्यम से अमेरीका ने ग्रीस में सैन्य तानाशाही को भड़काया; लोकतंत्र, 1974 में साइप्रस के विभाजन के बाद ही बहाल हुआ।

1950 के दशक से 1970 के दशक के मध्य तक, ग्रीस पश्चिमी केन्द्र के बराबर पहुँचने में सफल नहीं हुआ। तथापि, इस अवधि के दौरान, और पश्चिम की कीन्स की माँग–अग्रेषित नीतियों की तुलना में ग्रीस ने उन नीतियों का अनुसरण किया जो बाद में नवउदारवादी कहलाई। उसका आर्थिक विकास मुख्यतः आपूर्ति अग्रेषित और मुद्रा–समर्थक शीत युद्ध राजनीति के कारण था। यद्यपि सोवियत समर्थक साम्यवादी वाम गृह युद्ध (1944–49) में पराजित हुआ था, उसे अभी भी व्यापक लोकप्रिय समर्थन प्राप्त था जिसका अर्थ था कि रूढिवादी सरकार नागरिक समाज में राजनीति के अवसर खोलने के प्रयास करने से डर रही थी। राजनैतिक भागीदारी और माँग अग्रेषित आर्थिक नीतियाँ दोनों ही 1974 तक अवरूद्ध रहीं।

लेकिन 1974 के बाद, दक्षिण पंथी कोन्सटेन्टिन करामनालिस (1974–81) और समाजवादी एन्ड्रियास. जी. पपांद्रयू (1981–89, 1993–96) के नेतृत्व में क्रमिक ग्रीक मंत्रीमंडलों ने ग्रीक नीति निर्माण को माँग चक्र की तरफ धकेला। ऐसा उन्होंने रज्य तंत्र को उनके पार्टी–राजनैतिक कार्मिकों से भर, मुख्य निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण और विशेष रूप से 1980 के दशक में, ग्रीस कल्याण राज्य को कराधान की अपेक्षा अनैतिक उधारी (आंतरिक और बाह्य दोनों) से फंड किया। 1981 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) में प्रवेश के दौरान थी, ग्रीस ने एक ऐसे समय में माँग–अग्रेषित नीतियों का अनुसरण जारी रखा, जब अधिकांश पश्चिम नवउदारवादी वैश्वीकरण/

>>

खंडहर में यूनानी अर्थव्यवस्था

वित्तीयकरण को अंगीकार करने की तरफ जा रहा था।

बार–बार, भू–राजनैतिक चिन्ता मुख्य रूप से उभरी : ग्रीस EEC में पुर्तगाल और स्पेन से पाँच वर्ष पूर्व शामिल किया गया। ऐसा NATO की दक्षिणी कमान को स्थिरता प्रदान करने, की रणनीति के हिस्से के रूप में, ऐसे समय पर किया गया जब ग्रीस में अमरीकी अचल पूंजी निवेश खत्म हो रहा था। 1980 के दशक में जर्मन और फ्रेंच पूँजी का ज्यादातर ग्रीक अर्थव्यवस्था में वर्चस्व था और इसने देश पर एक नवउदारवादी एजेण्डा को अपनाने के लिए जोर डाला ताकि यह बाल्कन में वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीस को लॉंच पैड के रूप में इस्तेमाल कर सके।

> यूरोजोन में बिगड़ती आर्थिक स्थिति

आने वाले दो दशकों में और विशेष तौर पर, 2001 में ग्रीस का यूरोजोन में प्रवेश के बाद, उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में तेजी से गिरावट आई। पारंपरिक लाभ अर्जित करने वाले उद्योग जैसे कि कपड़ा उद्योग गायब हो गये। वित्तीय और बैंकिंग सेवाएँ ग्रीस की अर्थव्यवस्था में प्रभुत्वशाली हो कर बाल्कन एवं नियर ईस्ट तक फैल गई। सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का एक के बाद एक निजीकरण हुआ। बाह्य और घरेलू उधारी पर देश की निर्भरता इस डिग्री तक बढ़ गई कि सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को विदेशी पूंजी ग्रहण के लिए खोलना और मौद्रिक संप्रभुता की हानि को देखकर हम सोचते हैं कि क्या ''निर्भरता'' शब्द देश की वैश्विक आर्थिक स्थिति को पर्याप्त रूप से वर्णित कर सकता है।

जब वैश्विक वित्तीय संकट यूरोजोन तक पहुँचा, ग्रीस ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया क्योंकि यह पूंजी संचय की नव–साम्राज्यवादी वित्तीय चेन की सबसे कमजोर कड़ी थी और है। बीस वर्षों के नवउदारवादी वित्तीयकरण जो मित्तव्यत्तता के कठोर उपाय और बेल आउट समझौतों से अनुसरित थे, ने ग्रीस की किसी भी ऐतिहासिक आर्थिक समस्या : औद्योगिक पिछड़ापन; संस्थागत कमजोर; विशाल चालू खाता घाटा और उच्च कर्ज से GDP का अनुपात; विशाल बजट घाटा एवं राजकोषीय समस्याएँ, का समाधान नहीं किया है। एक स्वस्थ लोक निवेश, आला उत्पादन जैसे सौर उर्जा और हरित वृद्धि पर आधारित नये औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की आवश्यकता है। उसी समय, एक स्वतन्त्र विदेशी नीति देश की भू–सामरिक स्थिति एवं अशांत, बाल्कन एवं नियर ईस्ट में अपने शांति स्थापित करने के मिशन का लाभ उठा सकती है। यूरोजोन जैसो वर्तमान में संरचित है, के अन्तर्गत यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर यह ग्रीस की नहीं अपितु यूरोजोन की समस्या है। ■

वसीलस फोसकास से पत्र व्यवहार हेतु पता <v.fouskas@uel.ac.uk>

> ग्रीस में राज्य द्वारा थोपी गई मित्तव्यत्तता

मध्य एथेन्स में दुकान के शटर के बाहर अपने कपड़े एकत्रित करते हुए सड़क विक्रेता। पेत्रोस गियानाकोरिस। एपी फोटो

अपनी स्थापना के बाद से, यूरोजोन ने महान उदारवादी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेक से प्रभावित प्रस्तावों, विशेष कर राष्ट्रीय नीतियों से मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को बचाने और इस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं नियंत्रण से बचाने, का अनुसरण किया है। यह प्रोजेक्ट तथाकथित स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक और एक संस्थागत ढाँचा जो विषम अर्थव्यवस्थाओं को कठोर मुद्रा नियमों का पालन करने की माँग करता है, के द्वारा सिद्ध हुआ है। इस स्वर्ण मानक युग में यद्यपि ये नियम सभी देशों के फायदे के लिए समान रूप से कार्य नहीं करते हैं। वैश्विक संकट के प्रारम्भ से यूरोजोन का बाजारी अभिमुखन काफी अधिक स्पष्ट हो गया है। आर्थिक एकीकरण के प्रोजेक्ट के तहत चाहे कुछ राजनैतिक शक्तियाँ शुरू में सामाजिक कल्याण के पक्ष में रही हों, 2010 से विशेष कर ग्रीस के सम्बन्ध में, संकट के प्रबंधन ने एक ''सामाजिक यूरोप'' की परिकल्पना की हार का संकेत दिया है।

2010 के बाद से, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बहिष्कार से प्रारम्भ हो, ग्रीस पर एक कठोर आर्थिक उदारवाद लागू किया गया। पिछले छः वर्षों के दौरान, विभिन्न राजनैतिक झुकाव (सोशल डेमोक्रेटिक, दक्षिण पंथी, वामपंथी, टेकनोक्रेट, अस्थायी और गठबंधन) वाली सरकारों ने जल्दबाजी में ग्रीस और उसके अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों के मध्य समझौतों की श्रंखला तथाकथित समझौता ज्ञापन (MOU) के फ्रेमवर्क के अंतर्गत दर्जनों नये कानून और नियमों को लागू किया है। अपने भुगतान एवं ऋण दायित्वों का पूरा करने के लिए ग्रीस द्वारा लोन प्राप्त करने के लिए व्यापार अनुकूल विधान, निजीकरण और ग्रीक कल्याण राज्य का और सिकुड़ना – 1990 के दशक के मध्य से पहले ही सिकुडा, के साथ मित्तव्यत्ता के उपाय लागू किये गये हैं।

मेमोरेण्डम । के प्रारम्भ से लेकर आज के मेमोरेण्डम III तक राजकोषीय अनुशासन नया सिद्धान्त बन गया है। एक संभावी ग्रेक्सिट (यूरोपीय संघ से ग्रीस का बाहर निकलना) के प्रभावों के सम्बन्ध में लेनदारों की धमकियाँ, दबाब और कम–ज्यादा मनौवैज्ञानिक आतंकवाद, तीव्र प्रतिरोध जिसमें सैंकड़ों हड़तालें, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन एवं रोजगार और नये सामाजिक आंदोलन एवं मित्तव्यत्तता समझौतों का विरोध करते राजनैतिक दलों, के बावजूद कायम रही हैं।

मित्तव्यत्तता नीतियों के परिणाम स्वरूप, 2010 के बाद से ग्रीस की GDP 27% से अधिक गिर गई। यह गिरावट 1930 के दशक में अमरीका की GDP में आई गिरावट के बराबर थी। जीवन स्तर नाटकीय रूप से गिरा है; आपातकालीन कराधान में वृद्धि के साथ वेतन और पेंशन में 20% से 50% तक कटौती हुई है; आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी में धकेल दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में खर्चों

>>

को तेजी से कम किया गया, हजारों को बर्खास्त किया गया और भर्तियों को रोक दिया गया; उसी समय द्रुत–गामी प्रक्रियाओं ने सरकार को बची हुई राज्य सम्पत्तियों के निजीकरण की अनुमति प्रदान की। सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्यमों से लेकर विद्यालयों, अस्पतालों यहाँ तक कि पागलखाने जैसे लोक संगठन बंद या बिना सोचे समझे विलय कर दिये गये। शेष संस्थान अतिभारित थे और इसलिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ थे जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण सहित सार्वजनिक सेवाओं में आमूलचूल पतन हुआ।

2006 में 9% से 2014 में 27% तक बेरोजगार में वृद्धि के साथ, ग्रीस के कामगार वर्गों को अब एक बेहतर भविष्य की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी : यह स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था जल्दी सुधरेगी नहीं। ग्रीस के आधे से भी अधिक युवा बेरोजगारों के साथ और कार्य की परिस्थितियों में तीव्र अनिश्चितताओं के साथ श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले नवागन्तुक गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। पेंशन एवं वेतन में कटौती के कारण परिवार बच्चों और बुजुर्गों की सहायता करने में कम समर्थ हैं। यह ग्रीक पारिवारिक मॉडल और अवशिष्ट पूंजीवाद जो उत्तरी यूरोप जैसा पूर्ण विकसित कभी भी नहीं था, को चुनौती देता है। हालाँकि यह पारिवारिक मॉडल कभी कभी अविकसित पूंजीवाद का लक्षण माना जाता है–एक ऐसी दृष्टि जो इ. यू. मेमोरेण्डा के द्वारा चलाये गये ''आधुनिक'' सुधारों में परिलक्षित होती है। वर्तमान में कोई सबूत नहीं है कि ग्रीस किसी प्रकार के यूरोपीय कल्याण राज्य की तरफ जा रहा है। यह मान कर कि ग्रीस के पारिवारिक मॉडल और अवशिष्ट कल्याणकारी राज्य में 'सुधार' की आवश्यकता है, लेनदारों ने विनियमन और बाजारी मॉडल की तरफ झुकाव पर जोर दिया है अर्थात् आज सामाजिक सुरक्षा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो उसे वहन करने योग्य हैं।

यह विनियमन सामाजिक कर्त्ताओं के मध्य किसी संवाद या किसी सामाजिक मतैक्य का परिणाम नहीं है। गैर पारदर्शी ढंग से 'आपातकालीन प्रक्रियाओं' द्वारा लिए गये राष्ट्रीय और सुपरा–राष्ट्रीय निर्णय–लेनदारों और घरेलू श्रेष्ठि वर्ग दोनों की प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, इस संकट के दौरान मिल गये और उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक कर्ताओं के समरूपी कार्यों और उत्तरदायित्वों के मध्य की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। संसदीय कार्यों को यूरोसमूह और आर्थिक एवं वित्तीय मामलें संघ की संगोष्ठी से बदलकर ग्रीक मतदाताओं को राजनैतिक निर्णयों से बाहर रखा गया। 2011 में टेक्नोक्रेटिक सरकार के अधिरोपण जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है, इस प्रक्रिया का सुनहरा क्षण है। इस बीच जनमत संग्रह के रद्द होने या इस संकट काल के दौरान रद्द माने जाने से लोकतांत्रिक साधन निष्प्रभावी हो गये।

कार्ल पोलानयी का यह विचार कि अर्थव्यवस्था और समाज में वियोजन बाजार उदारवाद में अन्तर्निहित है, आज ग्रीस से ज्यादा कहीं भी अधिक पहचान योग्य नहीं है। यह वियोजन राज्य हस्तक्षेप द्वारा प्रोत्साहित उदारीकरण के एक स्वरूप का निर्माण करता है। जैसा कि पोलानयी के समझाया, विरोधाभास होने से परे, बाजार हमेशा से सुविचारित राज्य हस्तक्षेप का परिणाम रहा है। यह पैटर्न मेमोरेण्डम समझौतों, जो यूरोपीय संघ के इतिहास में शायद सबसे व्यापक और सर्वाधिक विस्तृत राजनैतिक हस्तक्षेप का निर्माण करते हैं, में भी दिखाई देता है। पोलानयी के उन्नीसवीं सदी के पूंजीवाद के बखान में, उदारवादियों ने स्व–विनियमित बाजार के असम्यककार्यता या संकट के लिए विशिष्ट सामाजिक समूहों पर दोषारोपण किया। इसी तरह, समकालीन ग्रीस में प्रचलित वृत्तान्त ने देश की स्थिति : मजदूरों को अत्यधिक उच्च मजदूरी मिल रही थी, बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी थे, सामाजिक लाभ काफी उदार थे, निजी सम्पत्तियाँ काफी बड़ी थी, के लिए समाज को दोषी माना। अतः निरिक्षित मित्तव्यत्ता को एक वैध दण्ड के रूप में प्रस्तुत किया जो बाजार की बहाली में मदद करने के लिए सामान्य लम्पद व्यवहार को समाप्त करने के लिए निर्मित किया गया है।

ग्रीस का संकट प्रबंधन पूरे यूरोजोन में मित्तव्यत्ता के संस्थानीकरण की रणनीति का एक हिस्सा है। फिस्कल काम्पैक्ट जो कथित रूप से गैर यूरोपीय अधिकारियों को राष्ट्रीय बजट की अधिक निगरानी करने देता है, इसका एक उपकरण रहा है। लेकिन संकट ने यूरोपीय मौद्रिक संघ की संरचनात्मक कमियों और निर्बलता को उजागर किया है। जैसे जैसे यूरोजोन की अर्थव्यवस्थाएँ प्रतिस्पर्धी नव–वणिकवाद की तरह पुनर्विन्यसित हुई हैं, कट्टर दक्षिणपंथी और नव–फासीवादी ताकतों ने अपने चुनावी प्रभाव को बढाया है। यूरोपीय एकीकरण के बारे में आशावद ने धीरे धीरे अधिक राष्ट्रीय और राज्य संप्रभुता अवधारणाएँ जो कुछ ही वर्षों पर पुरानी मानी जाती थीं, के लिए राजनैतिक अपीलों के लिए स्थान बनाया। ''अधिक यूरोप'' और ''अधिक राजनैतिक एकीकरण'' के कैम्प से आये प्रस्ताव अब बयानबाजी लगते हैं; यूरोजोन के अभिजन आर्थिक उदारवाद को मजबूत करने के बारे में अधिक चिंतित हैं। ऐसा वे संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमों के तहत देशों हेतु मित्तव्यत्तता या राजकोषीय अनुशासन में ढील, या श्रम एवं सार्वजनिक निवेश हेतु कोष में वृद्धि न कि कर राहत, के प्रयसों का विरोध कर के कर रहे हैं।

दंडात्मक मित्तव्यत्तता, संवैधानिक राजकोषीय अनुशासक एवं नव उदारवादी अंतः यूरोपीय उपनिवेशवाद ने श्रम की स्थितियों को बदतर किया है और अधिक अस्थिरता को जन्म दिया है जिसने ग्रीस और अन्य जगहों पर सामाजिक विनियमन और राजनैतिक अस्थिरता को गहरा किया है। जब तक कोई ठोस योजना मित्तव्यत्तता से बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिखाती है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में और वर्ग असमानताओं के मध्य विषमताओं में वृद्धि होगी। यह विभिन्न देशों के आम नागरिकों में इस भावना को मजबूत करेगी कि मुख्य निर्णय कहीं और जगह, किन्हीं अवैयक्तिक अंतर्राष्ट्रीय अभिजन द्वारा लिए जायेंगे; इस वातावरण में यूरोसंदेहवाद (यूरोस्केपटिसिज्म), वैश्वीकरण विरोधी माँगें और यूरोजोन को तोड़ने की दलीलें व्यापक दर्शकों को आकर्षित करेंगी। प्रश्न यह है कि ये माँगे और दलीलें कैसा राजनैतिक प्रभुत्वशाली होंगी। क्या लोकतांत्रीकरण के लिए संघर्ष करने वाले और नवउदारवाद से नाता तोड़ने वाले प्रबल होंगे? या क्या यूरोप के कट्टर दक्षिण पंथी एक गहरे राष्ट्रवादी झुकाव को बढ़ावा देने में सफल होंगे? अब तक, पोलानयी का ''दुगुने आंदोलन'' का पेंडुलम सुझाता है कि बाजारी ताकतें और उनके राजनैतिक प्रतिनिधि, लोकतंत्र को घायल कर अंधकारमय भविष्य के परिदृष्य की संभावना को बढ़ा, विजयी उभरे हैं। ■

मारिया मरकन्तोन्ताओं से पत्र व्यवहार हेतु पता <mmarkant@soc.aegean.gr>

> सीरिजा
विनाश से व्यवहारिकता की तरफ

जॉन मिलियोस, राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय, एथेन्स, ग्रीस

एथेन्स में सीरिजा रैली

10 भिन्न वाम धाराओं और राजनैतिक समूहों को शामिल कर, एक काफी ढीले गठबंधन के रूप में, 2004 में सीरिजा का गठन हुआ। इसका गठन 2000 से प्रारम्भ एक प्रक्रिया जब सीरिजा को गठन करने वाले अधिकांश राजनैतिक समूह ग्रीक और यूरोपीय वैश्वीकरण–विकल्प आंदोलन में साथ साथ मौजूद थे। 2001 में कई हजारों ग्रीक वामपंथियों ने जिनोवा G-8 शिखर सम्मेलन विरोध प्रदर्शन, अब तक का शायद सबसे बड़ा वैश्वीकरण विरोधी यूरोपीय प्रदर्शन, में भाग लिया; इन में भाग लेने वाले कई लोग उन राजनैतिक संगठनों से थे, जिन्होंने बाद में सीरिजा, एक गठबंधन जो राजनैतिक परिदृश्य और ग्रीक संसद में मुखर वाम केन्द्र के रूप में उभरा, का निर्माण किया था।

> >

ऐतिहासिक रूप से, सीरिजा चार मुख्य परम्पराओ : एक साम्यवादी परम्परा (पूर्व सोवियत समर्थक और यूरो–कम्युनिस्ट समूहों के बीच तनाव द्वारा चिन्हित); एक अतिरिक्त–संसदीय वामपंथी परम्परा (अपने स्वयं के तनाव, मुख्य रूप से ट्रोट स्कीईस्ट, माओवादी और कट्टरपंथी यूरो–कम्यूनिस्ट उप–परंपराओं के मध्य, के द्वारा चिन्हित); 2000 के दशक के प्रारम्भ के ''वैश्वीकरण–विकल्प आंदोलन''; और ग्रीस के सुधारवादी सामाजिक लोकतांत्रिक परम्परा, विशेष रूप से 2012 के महत्वपूर्ण चुनावों के पश्चात्, जब ग्रीक सोशल डेमोक्रेटिक दल (पेनहेलेनिक समाजवादी आंदोलन–PASOK) विघटित हुई, से उभरा। 2009 राष्ट्रीय चुनावाअें में 4.6% से सीरिजा 2012 में लगभग 27% तक पहुँच गई। इस बीच, पासोक (PASOK) 2009 में लगभग 44% से 2012 में 13.8% तक गिर गई। 1974 में सैन्य शासन की समाप्ति के बाद से पासोक ने दक्षिणपंथी निया डेमोक्रेटिका के साथ सत्ता को बारी बारी से साझा किया था लेकिन जनवरी 2015 में PASOK जहाँ मात्र 4.6% तक रह गई, सीरिजा 36% से भी अधिक वोटों के साथ सत्तारूढ़ पार्टी बन गई।

सीरिजा लगातार बढ़ती रही। 2012 से जब सीरिजा देश का प्रमुख विपक्षी दल बन गया, इसने धीरे धीरे सुधारवादी रूख अपनाया और व्यावहारिकता की तरफ बदलाव किया एवं ''4% वाली पुरानी सीरिजा'' और ''27% वाली नई सीरिजा'' के मध्य भेद किया। इस अवधि में PASOK के कई पूर्व सदस्य सीरिजा में शामिल हो गये। 2014 के यूरोपीय संसदीय चुनावों में सीरिजा 26.5% के साथ अग्रणी रही और आने वाले राष्ट्रीय चुनावों में एक अग्रणी भागीदार के रूप में सरकार बनाने के लिए तैयार लग रही थी। प्रभावकारिता पर विचार रखने के लिए और ''चुनावी जीत की सुरक्षा'' के लिए पार्टी के सदस्यों का आह्वान कर, कई सीरिजा नेताओं ने मध्य–वामपंथी नेताओं और छोटे मध्य–वामपंथी राजनैतिक संरचनाओं के साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी।

जन संचार, नारों और इसके पूर्व निशानों में पार्टी की आधिकारिक भाषा बदलने लगी। 'वामपंथी सरकार के लिए' का उसका नारा धीरे धीरे ''राष्ट्रीय मुक्ति की सरकार'' वाले आत्म–विवरण द्वारा बदल गया; ''सत्ता, धन और श्रम के लाभ के लिए आय का पुनर्वितरण'' ''देश का उत्पादक पुनर्निर्माण'' द्वारा बदल दिया गया। लोगों द्वारा समाज और अर्थव्यवस्था का लोकतांत्रिक नियन्त्रण, आत्म निर्देशित सहकारी उत्पादक योजनाओं और एक गैर–बाजार सामाजिक अर्थव्यवस्था सहित प्रोग्राम के पद अलग रख दिये गये।

सीरिजा के चुनाव–पूर्व कार्यक्रम ने मित्तव्यतता नीतियों के अंत और यूनानी सार्वजनिक क्षेत्र को धन देने के लिए देश के लेनदारों के साथ सौदा करने का वादा किया था। सीरिजा के सत्ता में आने के कुछ सप्ताह बाद, इन वादों ने एक नरम मेमोरेण्डम की सौदेबाजी का मार्ग दिया और फरवरी 2015 में वित्त मंत्री वाई. वाराओफकिस द्वारा एक प्रारंभिक समझौता हस्ताक्षरित हुआ। वाराओफकिस कभी भी सीरिजा के सदस्य या किसी वामपंथी धारा के समर्थक नहीं रहे थे; मंत्री के रूप में नियुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने अपने आप को सीरिजा के प्रोग्राम संबंधी मोर्चे से दूर कर लिया। उन्होंने संकट को सभी सामाजिक वर्गों को समान रूप से पीड़ित करने वाला बता एक निर्यात केन्द्रित मॉडल का आह्वान किया और वेतन वृद्धि को प्रतिस्पर्धा को कमतर करने के रूप में खारिज किया। अतः उनके द्वारा बार बार दोहराया गया सार्वजनिक दावा कि मेमोरेण्डम के 70% उपाय ग्रीस के लिए लाभदायक होंगे, कोई संयोग नहीं था।

हालाँकि, सीरिजा मेमोरेण्डम के 70% उपायों को बढ़ावा देने के वादे के कारण सत्ता में नहीं आई थी। यदि ऐसा होता तो, सीरिजा आज संभवतः ग्रीक संसदीय नक्शे में सम्मिलित नहीं होती। महत्व पूर्ण भूमिका निभाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वराओफकीस के बयानों में परिलक्षित दृष्टि ने सीरिजा के जनादेश को पुनर्परिभाषित किया। व्यावहारिक रूप से ऐसा सामाजिक गठबंधन जिसने अब तक ग्रीस में वामपंथी सरकार के ऐतिहासिक प्रयोग का समर्थन किया था, को पुनः आकारित कर के किया गया।

फरवरी 2015 के समझौते ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ग्रीक सरकार यूरोपीय नवउदारवादी मित्तव्यत्तता ढाँचे के अन्तर्गत बातचीत कर अपने समझौतों को छुपाने के लिए कोई मार्ग ढूँढ रही थी। इस मार्ग में, एक तरफ तो ''मानवीय संकट को समाप्त'' करने का हल्का कार्यक्रम (उर्जा अनुदान, अत्यधिक निर्धन को फूड स्टेम्प आदि प्रदान कर के) और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर छँटनी और कुछ बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए निम्न वैट गुणांक के संबंध में पूर्व–निर्देशों को बनाये रखते हुए वेतन और पेंशन में प्रत्यक्ष नाम–मात्र कटौती को खारिज करना सम्मिलित था। सरकार ने अपने चुनाव–पूर्व कार्यक्रम को छोड़ दिया; इसके बजाय उसने एक ऐसे समझौते की माँग की जो ग्रीस के नव उदारवादी संस्थागत और आर्थिक ढाँचे को अछूता छोड़ेगी, इस उम्मीद में कि ऐसा करने से कम और मध्यम आय के बारे में मित्तव्यत्तता उपायों से बचाव होगा।

हालाँकि, लेनदारों ने कभी भी इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ग्रीस के वित्तपोषण के लिए एक योजना जिसमें वेतन और पेंशन में कटौती (जंकर प्लान) सहित गहन नवउदारवादी नीतियों की पेशकश की। पाँच महीनों की वार्ता के बाद सरकार को अपने लेनदारों द्वारा वादा किया गया कोई भी अंश प्राप्त नहीं हुआ, यद्यपि ग्रीस यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ECB) और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को अपने सभी सार्वजनिक कोष के खत्म होने तक, ऋण दायित्वों का भुगतान करना जारी रखा। जून 2015 में, जब सरकार के पास नकदी बिल्कुल खत्म हो गई तो एक IMF के भुगतान में देरी हुई। उस सप्ताह, प्रधानमंत्री ए. तसिप्रास ने ''जंकर प्लान'' पर जनमत संग्रह का आह्वान किया। परेशान जमाकर्ताओं द्वारा अपनी बचत को वापिस लेने के स्थिति में ECB के द्वारा बैंकों को अतिरिक्त नकदी देने से इंकार करने के बाद, वोट की आशा में, ग्रीस को बैंकों से निकासी की सीमा (''बैंक अवकाश'' और ''पूंजी नियंत्रण'') तय करनी पड़ी।

जनमत संग्रह अभियान ने दशकों से अनदेखे वर्ग और सामाजिक विभाजन को उजागर किया। दो ग्रीस ने एक दूसरे से लड़ाई की : निर्धन, वेतनभोगी, बेरोजगार और कई छोटे उद्यमियों ने 'नहीं' के मत की माँग की, जबकि उच्च वर्ग ने 'हाँ' के लिए प्रदर्शन किया। बैंकों के बंद होने से, जनसंचार प्रचार ने चेतावनी दी कि ''नहीं'' का मत विनाशकारी होगा। जहाँ नियोक्ताओं ने कामगारों को ''हाँ'' के लिए मत डालने के लिए दबाब डाला, फिर भी लगभग दो–तिहाई यूनानियों (61.3%) ने ''नहीं'' के लिए मतदान किया। लेकिन संसद में सरकार ने रूढ़िवादी विपक्ष के साथ काम करके ''नहीं'' को ''हाँ'' में बदल दिया। जुलाई 2015 में जब सीरिजा ने एक नया मेमोरेण्डम जो पूर्ण रूप से ''जंकर प्लान'' का समरूप था, और जिसे ब्लैकमेल का परिणाम के रूप में वर्णित किया था, पर हस्ताक्षर किये तो ग्रीस, उसके लेनदार और सिद्धान्तवादी यूरोपीय श्रेष्ठि वर्ग के बीच संघर्ष की हार हुई।

यह व्याख्या सीरिजा के भीतर आवाजें, जो मेमोरेण्डम को या तो एक आर्थिक त्रुटि जो वृद्धि को बढ़ावा नहीं देगी या ''विदेशी हितों'' द्वारा ग्रीस पर आक्रमण के रूप में देखती हैं, की प्रतिध्वनि को दर्शाती है। अतः सीरिजा का अंतिम संधिपत्र इस रूप में प्रस्तुत

>>

एलेक्सिस त्सीप्रास, एक समय में यूरोप के मितव्यत्तता विरोधी वामपंथ का चहेता।

किया, जिसे कुछ पार्टी सदस्य ''असमान युद्ध में विरोचित पछाड़'' के रूप में वर्णित करते हैं। इसे भविष्य में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और राज्य संरचनाओं के आधुनिकीकरण के प्रयासों जैसे समान सरकारी उपायों द्वारा पलटा जा सकता है। हालांकि, मित्तव्यत्तता सिर्फ एक ''छद्म नीति'' नहीं है अपितु कामगारों, बेरोजगारों, पेंशन भोगी और आर्थिक रूप से कमजोर के हितों की बजाय पूंजी के हितों को प्रोत्साहन करने वाली वर्ग रणनीति है। यह श्रमिकों के लिए कम अधिकार, कमजोर सामाजिक सुरक्षा और कम लचीली मजदूरी और सार्थक सौदेबाजी की शक्ति बिल्कुल नहीं, की पेशकश करता है।

कुछ सीमा के परे, सामाजिक जीवन के सभी अंगों की निखुंश बाजार के अन्तर्गत परतंत्रता नवउदारवादी संस्थापन के लिए राजनैतिक जोखिम का निर्माण कर सकती है, चूंकि यह सामाजिक विरोध के अनियंत्रित प्रकोप को ट्रिगर कर सकती है। यह राजनैतिक जोखिम ग्रीक कामगार वर्ग और सीरिजा के मित्तव्यत्तता को रोकने के प्रयासों में मजबूत हथियार था। लेकिन यह हथियार एक पूर्व–शर्त पर टिका था : कि सीरिजा लोगों को लाभ से पहले रख, अपने कार्यक्रम पर कायम रहेगी और अपनी प्राथमिकताओं को बनाये रखेगी।

हालांकि, 2014 में विजयी यूरोपीय संसदीय चुनावों के बाद से, जब सीरिजा ''वृद्धि और स्थिरीकरण'' की पूर्व–आवश्यकता के रूप में सुधारवादी नवउदारवादी मार्ग की तरफ मुड़ गई, इस रणनीति को छोड़ दिया गया। इस बदलाव की जड़े, सीरिजा के सत्तारूढ़ दल बनने से उभरी चुनौतियों में ही नहीं, बल्कि ग्रीस के स्तालिन वादी–वामपंथ पश्चात की राजनैतिक परंपरा में भी थी। उसका देशभक्त सुधारवाद सरकारवाद–अर्थात यह विचार कि वामपंथी सरकार बनाना राजनैतिक परिवर्तन के लिए पर्याप्त और यथेष्ट शर्त है – और अर्थवाद–जो सामाजिक उद्विकास को उत्पादक शक्तियों, जिनके बारे में विश्वास है कि वे उत्पादन के संबंधों का अपरिहार्य रूपांतरण कर देंगी, के विकास के रूप में देखता है, द्वारा चित्रित था।

नये मेमोरेण्डम पर हस्ताक्षर करने से, सीरिजा ने ग्रीक संस्थानिक और श्रम बाजार ढाँचे की कठोरता को हटाने के लिए स्वीकृति दी। इसने कामगारों की पिछली विजय को परिलक्षित किया। सीरजा ग्रीक राजनैतिक परिदृश्य में प्रभावी है लेकिन आज पार्टी कट्टरवादी वामपंथ के आंदोलन के अपितु मुख्यधाराई सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में अधिक जानी जाती है। ■

जॉन मिलियोस से पत्र व्यवहार हेतु पता <john.milios@gmail.com>

> यूनानी वित्तीय संकट में विजयी और पराजित

स्पाइरोस सकेलारोपोलास, पेन्टियोन विश्वविद्यालय, ग्रीस

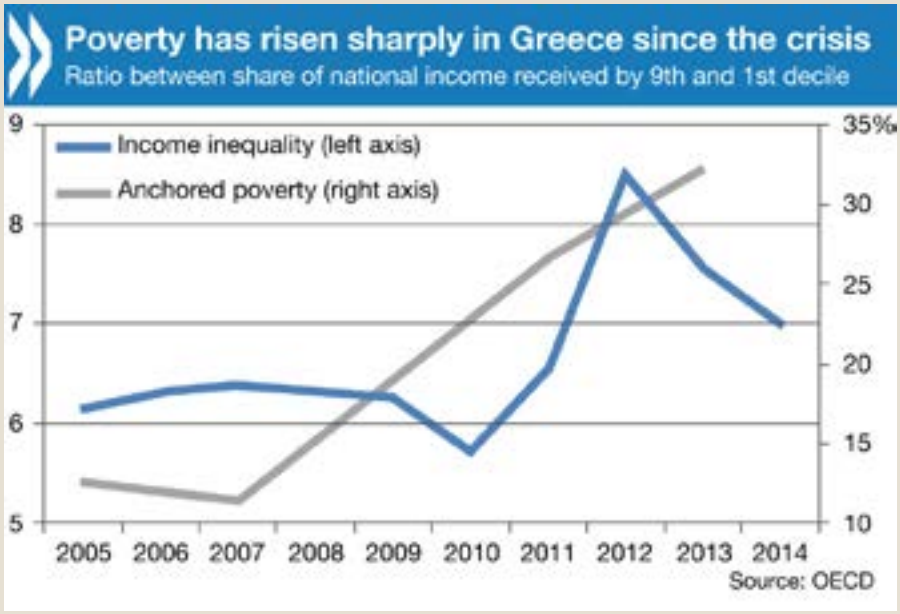

ग्रीक संकट के प्रारम्भ से बढ़ती गरीबी और आय असमानता दर्शाता ग्राफ

सन् 2010 के प्रारम्भ में, तत्कालीन प्रधानमंत्री जार्ज पपांद्रयू ने स्वीकारा कि यूनानी सरकारी वित्त की स्थिति इतनी नाजुक है कि देश वैश्विक बाजारों से उधार मिलने की आशा नहीं करता और इस तरह वह अपने सार्वजनिक ऋण को चुकता नहीं कर सकता।

प्रचलित धारणाओं के विपरीत, ग्रीस की समस्याएँ उच्च आय प्राप्त ग्रीक कामगारों से नहीं उपजी और न ही वे एक फिजूलखर्च राज्य का परिणाम थीं। ग्रीक वेतन EU15 (अर्थात् 2004 के विस्तार के पूर्व यूरोपीय संघ के सदस्य) में प्रचलित स्तर का सिर्फ 85% हैं, जबकि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में, प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय इस ब्लॉक के लिए तकरीबन औसतन ही है। काफी हद तक, ग्रीक वित्तीय संकट राष्ट्रीय सत्ताधारी वर्ग की रणनीति और जिस तरह वह, विशेष रूप से 1981 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) में और 2002 में यूरोपीय मुद्रा संघ में ग्रीस के प्रवेश से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के साथ एकीकृत हुआ है, से उपजा है। एकल मुद्रा द्वारा तय की गई शर्तों के साथ स्पर्धा करने में ग्रीक पूंजीवाद की असमर्थता के कारण GDP में गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप ऋण से GDP अनुपात में वृद्धि हुई।

बहरहाल, 2010 के प्रारम्भ में, फ्रेंच एवं जर्मन बैंकों, जहाँ अधिकांश ग्रीक बाण्ड जमा थे, को ऋण भुगतान करने की आशा में और दिवालियापन, जो ग्रीस की समस्या को यूरोपीय अर्थव्यवस्था के केन्द्र में स्थानान्तरित कर देता, से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि ग्रीस यूरोपीय संघ, यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेगा।

लेकिन कर्ज लेने से पूर्व, ग्रीस को पहले मित्तव्यत्तता के उपाय अपनाने पड़ेंगे। 2010 और 2016 के मध्य आर्थिक सहयोग के तीन पत्रक लागू किये गये। इसमें मध्यम अवधि का एक प्रोग्राम और विशिष्ट उपायों के आठ पैकेज जिसमें अन्य उपायों के साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती, बुजुर्गों की पेंशन में कटौती, न्यूनतम मजदूरी स्तर में कमी (अधिकांश ग्रीक कामगारों के लिए 751 यूरो से 586, और 25 वर्ष से कम उम्र के लिए 490), VAT में 19% से 24% की वृद्धि, रियल एस्टेट में विस्तृत कराधान, रोजगार के नये लचीले स्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में प्रमुख कटौती, प्रतिगामी कर में वृद्धि और ऐसे कई अन्य सम्मिलित हैं।

ये नीतियाँ कितनी प्रभावी थीं? शुरूआत के लिए, सार्वजनिक ऋण–जिस कारण से ये सभी उपाय अपनाये गये थे, में दोनों निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

> >

2009 के अंत तक यूरो 300 खरब से ग्रीक कर्ज 2015 के अंत तक यूरो 314.4 खरब तक बढ़ गया; वास्तव में चूंकि इस काल के दौरान ग्रीक अर्थव्यवस्था सिकुड़ी, GDP के प्रतिशत के रूप में राष्ट्रीय 126.7% से 179% हो कर आसमान छूने लगा। इस बीच, बेरोजगारी 2009 में 9% से मई 2016 में 23.5% तक बढ़ गई, जबकि GDP 2009 में यूरो 237.4 अरब से 2015 में यूरो 179 अरब तक गिर गई।

ये आँकड़े अपनाये गये सभी उपायों की विफलता को दर्शाते हैं। लेकिन करीब से देखने से पता चलता है कि नीति ने विजेता और हारने वालों का उत्पन्न किया है। हारने वाली तरफ कामगार वर्ग (वेतनभोगी) और लघु एवं मध्यम आकार के कृषि उत्पादक हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आज बेरोजगारों में से केवल 15% को बेरोजगारी लाभ मिलते हैं; संकट के पहले 40% ग्रीक बेरोजगार लाभ के लिए दावा कर सकते थे। अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ लोगों का प्रतिशत 11% से 20% बढ़ गया; आज एक दस लाख से भी अधिक यूनानी ऐसे परिवारों में रहते हैं जहाँ कोई काम नहीं करता या जहाँ रोजगार प्राप्त वर्ष में तीन माह से कम कार्य करते हैं। पेंशनरों के 50% को यूरो 500 यूरो प्रति माह से कम पेंशन मिलती है। 2009 से 2015 तक राष्ट्रीय गरीबी दर 27.6% से 35.7% हो गई।

जो लोग नौकरियों में बने रहे, उन्होंने भी आय को खोया। GDP में वेतन की हिस्सेदारी 64% से 54% तक गिर गई और कुल मिलाकर, वेतनभोगियों ने अपनी क्रय शक्ति का एक–तिहाई भाग खो दिया है। EU15 की औसत क्रय शक्ति 84% से 65% तक गिर गई। 2008 और 2015 के मध्य, 427,000 यूनानियों ने प्रवास किया जिसमें एक बड़ा बहुमत विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त का था। 2008 में सक्रिय 849,289 व्यापारों में से सिर्फ 692,286 2014 में भी सक्रिय थे। और असमानता बढ़ गई : सबसे अमीर 20% और निर्धनतम 20% की आय के मध्य का अनुपात 5.6/1 से 6.6/1 हो गया।

जीवन स्तर में गिरावट ग्रीक जनसांख्यकीय आँकड़ों में भी स्पष्ट दिखाई देता है। स्वास्थ्य व्यय 25% गिर गया। 2011 और 2014 के मध्य, सबसे हाल ही का वर्ष जिसके आँकड़े उपलब्ध हैं, मृत्यु की तुलना में जन्म कम हुए थे। शिशु मृत्यु दर 51% तक बढ़ गई।

लेकिन विजेता कौन हैं? सबसे बड़े विजेताओं में विदेशी बैंक हैं जिन्होंने अपने आप को संकट के प्रारम्भ में ग्रीक कर्ज का एक बड़ा हिस्सा पकड़े हुए पाया था। जून 2010 में सार्वजनिक और निजी ऋण, दोनों मिलाकर विदेशी बैंकों का कर्ज $252.1 अरब था जिसमें कुल का 75.1% फ्रेंच ($83.1 अरब), जर्मन ($65.4 अरब) और अमरीकी ($36.2 अरब) बैंकों का बकाया था। दिसम्बर 2010 तक, विदेशी बैंकों की बकाया राशि $145.7 खरब ($56.7 अरब फ्रेंच बैंकों की, $34 अरब जर्मन बैंकों की, $7.3 अरब अमरीकी बैंकों की) तक रह 42% की कमी आई। पहले पत्रक के अन्तर्गत बैंकों को ग्रीक कर्ज के एक बड़े हिस्से को बेचने का समय मिल गया। यह एक ऐसा पैटर्न था जो दिसम्बर 2011 में और अधिक स्पष्ट दिखाई देगा, जब तक विदेशी बैंकों ने उनके ग्रीक कर्ज को $35 अरब तक कम कर लिया था। 2012 के चुनावों तक, विदेशी बैंक लगभग पूर्ण रूप से ग्रीक कर्ज से मुक्त थे।

ग्रीस के अन्दर विजेताओं के संदर्भ में: 2010 में देश की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कम्पनियों ने यूरो 2.2 अरब के सामान पर लाभ कमाया; 2014 तक यह बढ़ कर 10.2 अरब हो गया था। सर्वाधिक बिक्री वाली 300 कम्पनियों (वित्तीय क्षेत्र को छोड़कर) ने 2009 और 2014 के मध्य अपने टर्न ओवर को कुल के 53.6% से 59.8% तक और अपनी परिसम्पत्तियों को 42.2% से 44.0 तक बढ़ा लिया।

अंतिम परन्तु कम नहीं : 2011 में, ग्रीस के 445 लोगों के पास यूरो 30 करोड़ से अधिक धन सम्पत्ति थी, जो कुल का यूरो 50 अरब और GDP का लगभग 24% थी। 2014 तक, यह विशेषाधिकार प्राप्त समूह थोड़ा बड़ा हो गया : 565 लोगों के पास कुल यूरो 70 अरब या उस वर्ष की GDP का 39.5% था। 2014 में इस कुलीन समूह में यूरो 18 अरब की कुल परिसम्पत्तियों के साथ 11 ग्रीक अरबपति थे। यह आंकड़ा 2013 में यूरो 16 अरब की परिसम्पत्तियों के साथ 9 से अधिक था।

ये विकास क्रम देश के सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों में प्रतिबिंबित होते हैं। हाल ही के एक सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रीक बुर्जुआ आज GDP का 2.8% (2009 में 3.2% से नीचे) हैं; धनाढ्य ग्रामीण तबका 0.6% (0.7% से नीचे); पारंपरिक छोटे बुर्जुआ 7.0% (7.3% से नीचे); नये छोटे बुर्जुआ 21.9% (29.5% से नीचे); मध्यम ग्रामीण तबका 1.2% (1.9% से नीचे); निर्धन ग्रामीण तबका 7.3% (7.4% से नीचे); और कामगार वर्ग 59.2% (49.1% से उपर) हैं।

इन नीतियों के चाहे कोई भी कारण रहे हों, परिणाम पर एक स्पष्ट सामाजिक छाप है। अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों एवं उनके गृह देशों के संरक्षण में बड़े विदेशी बैंकों ने अपने हितों का ध्यान रखा। कुछ क्षेत्रों के आर्थिक दिवालियापन के साथ जुड़ी हानि के बावजूद, देश की आर्थिक अभिजनों ने अपनी धन सम्पदा का विस्तार किया है और स्थानीय कामगार वर्ग के तीव्र शोषण और लघु से मध्यम व्यापारों में सिकुड़न से अपने लाभ में वृद्धि की है। ■

स्पाइरोस सकेलारोपोलास से पत्र व्यवहार हेतु पता <sakellaropouloss@gmail.com>

> राज्य–कार्पोरेट अपराध के रूप में ग्रीक बेल आउट

स्त्रातोस जियोरगुलास, एजियन विश्वविद्यालय, ग्रीस

बेल आउट से किसका लाभ होता है?

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक समुदाय ने ''राज्य–कार्पोरेट अपराध'' अर्थात प्रशासन की राजनैतिक संस्थाओं और आर्थिक उत्पादन एवं वितरण के मध्य अंतक्रिया द्वारा निर्मित अवैध या सामाजिक रूप से क्षतिपूर्ण कार्यवाही को हाल ही में परिभाषित करने का प्रयास किया है।

राजनैतिक और शोध के दृष्टिकोण से यह शब्द 'भ्रष्टाचार' से मेल खाता प्रतीत होता है लेकिन इनमें दो मुख्य अंतर हैं। पहला, इन कृत्यों को गैर–कानूनी घोषित करने के प्रयास मानवाधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक क्षति को रोकना चाहते हैं; इन कृत्यों में सामान्य तौर पर ज्ञात आपराधिक गतिविधियाँ जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी इत्यादि से कहीं अधिक जीवन, शारीरिक या अन्य नुकसान, और सम्पत्ति या धन की हानि शामिल हैं। दूसरा, इस अपराध की जड़े साधारण राजनैतिक एवं सामाजिक क्रियाओं : राज्य एवं पूंजी के मध्य अनन्योश्रितता – से या तो सार्वजनिक धन को सीधे निजी अनुबंधों में परिवर्तित कर के या सुविधाएँ देकर और विशिष्ट नीतियों को प्रोत्साहित कर, हमारे पूंजीवादी समाज के केन्द्र में हैं।

इसके अतिरिक्त, इन राज्य–कार्पोरेट अपराधों के साथ एक और आयाम जुड़ा है। इस प्रकार, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी सुपरा नेशनल संस्थाएँ सम्पूर्ण आबादी को वास्तविक सामाजिक हानि पहुँचाती हैं, तो ''वैश्वीकरण के अपराध'' एक रोचक आयाम को जोड़ते हैं। शक्तिशाली देशों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों के साथ मेल खाती टाप–डाउन नीतियों एवं आर्थिक कार्यक्रमों का मुख्यतः ''विकासशील देशों'' में मानव जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऐसा तब होता है, जब ''ऋण–चुकौती'' जैसे–कार्यक्रम राजनैतिक अस्थिरता को पैदा करते हैं और फिर शासन के पैतृक या ग्राहकीय व्यवस्थाओं को जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, सत्तावाद, राज्य दमन, यंत्रण का प्रयोग और यहां तक कि नरसंहार की संभावना को भी पैदा करते हैं।

ग्रीस में, जहाँ हम सरकारी समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों जैसी सुपरा नेशनल संस्थाओं द्वारा परिभाषित नीति पत्रक के अमलीकरण के तहत रह रहे हैं, हमने मानवाधिकार उल्लंघन और व्यापक सामाजिक क्षति को देखा हैं। बेल आउट कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जाने वाले उपायों ने प्रत्यक्ष तौर पर जीवनयापन की स्थितियों को प्रभावित किया है। ऐसा उन मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण हुआ है जिन्हें ग्रीस घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सम्मानित, करने, रक्षा करने और प्रोत्साहित करने के लिए बाध्य है। ग्रीक अर्थव्यवस्था और समाज पर थोपे गये कठोर समायोजनों ने जीवन स्तर में तीव्र गिरावट दर्ज कराई है और वे

> >

सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, लोकतंत्र या मानवाधिकारों के साथ असंगत हैं। कौन से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है? चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं।

कार्य का अधिकार/पत्रक द्वारा थोपे गये श्रम बाजार सुधारों ने ग्रीस में कार्य के अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर किया है जिसके कारण गंभीर संस्थागत टूटन आई है। लम्बे समय से चल रहे सामूहिक सौदेबाजी के समझौतों को नष्ट कर एवं श्रम मध्यस्थता ने रोजगार की स्थितियों में वैयक्तिक रोजगार समझौतों को मुख्य निर्धारक के रूप में पुनर्जीवित किया है। क्रमिक वेतन कटौतियों और कर में वृद्धि ने बड़े पैमाने पर छँटनी, श्रम मानकों में क्षय, रोजगार असुरक्षा में वृद्धि को बढाया है एवं महिलाओं और युवा कामगारों को अधिक लचीली कम वेतन वाली नौकरियों में धकेल व्यापक अनिश्चितता का निर्माण किया ह। न्यूनतम मजदूरी ग्रीस के गरीबी के स्तर से भी निचले स्तर पर चली गई है।

स्वास्थ्य का अधिकार/आर्थिक समायोजन कार्यक्रम 2010 ने जन स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6% तक सीमित किया। 2012 के कार्यक्रम में अस्पताल परिचालन की लागत में 8% तक की कटौती की माँग थी। औषधीय खर्च को 2010 में यूरो 4.37 अरब से 2014 तक यूरो 2 अरब तक लाने के प्रयासों के दौरान अस्पतालों और आर्मेसियों ने व्यापक कमी को अनुभव किया।

शिक्षा का अधिकार/पत्रक में वर्णित विशिष्ट उपायों ने शिक्षकों की भर्ती में कटौती, श्रम गतिशीलता स्कीम के तहत शिक्षकों के बलात् स्थानान्तरण, शिक्षकों के वेतन में कटौती, विद्यालयों का विलय और बंद करना, प्रति कक्षा छात्रों की संख्या में वृद्धि और साप्ताहिक शिक्षण घंटों में वृद्धि की। शैक्षणिक पदों को रिक्त छोड़ दिया गया, 1053 विद्यालय बंद किये गये और 2008 एवं 2012 के मध्य 1933 विद्यालयों का विलय कर दिया गया। बजट में कटौती ने कई विद्यालयों को हिटिंग की सुविधा के बिना ही छोड़ दिया।

सामाजिक सुरक्षा का अधिकार/पत्रक द्वारा लागू खर्चों में कटौती ने सामाजिक लाभों जिसमें पेंशन, बेरोजगारी लाभ एवं पारिवारिक लाभ सम्मिलित थे, में कमी की। 2010 से पेंशन में औसतन 40% की कटौती की गई है जिससे 45% पेंशनर गरीबी की रेखा के नीचे आ गये हैं।

आवास का अधिकार। 120,000 परिवारों को किराया अनुदान और बुजुर्गों को आवासीय लाभ देने की पेशकश की ''पूर्व कार्यवाही'' के रूप में ग्रीस ने 2012 में सामाजिक आवास को समाप्त कर दिया। नये कानून और नियम बिना न्यायिक परीक्षण के तीव्र बेदखली की प्रक्रियाओं की अनुमति देते हैं। 2014 में ग्रीस में 500,000 लोगों से अधिक या तो बेघर थे या असुरक्षित या अपर्याप्त आवास में रह रहे थे।

आत्मनिर्णय का अधिकार/राज्य सम्पत्तियों का थोक में निजीकरण, विशेष रूप से ''फास्ट ट्रैक'' प्रक्रियाओं के द्वारा, संवैधानिक अधिकारों और लोकप्रिय संप्रभुता, सम्पत्ति एवं पर्यावरण संरक्षण की गारण्टी देने वाले नियमों की अवहेलना करता है।

न्याय का अधिकार/लेनदार द्वारा थोपे गये उपाय ग्रीस पर अपनी न्यायिक व्यवस्था में सुधार, जिसमें बड़ी मात्रा में शुष्क वृद्धि सम्मिलित हैं, की माँग करते हैं। नागरिकों के लिए न्यायालय की शरण लेना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है विशेष तौर पर तब जब उन्होंने वेतन एवं पेंशन में भारी कटौती को अनुभव किया हो।

स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का अधिकार। 2010 के बाद से विधायी और प्रशासनिक उपायों ने अभिव्यक्तिये और सभा करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया है। स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के अधिकार को व्यवस्थित और प्रभावी रूप से चुनौती दी है और सभा करने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। पत्रक द्वारा चालित नीतियों के विरूद्ध वैध विरोध प्रदर्शन को अधिकारियों ने सार्वजनिक बैठकों को प्रतिबंधित कर, नाबालिगों से पूछताछ और फासीवादी विरोधी प्रदर्शनकारियों को यंत्रणा दे कर रोका है। ऐसा अक्सर प्रोटो–फासीवादी गोल्डन डॉन पार्टी के चौकस व्यक्तियों के सहयोग से हुआ है।

आज, ग्रीक आबादी का 23.1% गरीबी की रेखा के नीचे रहता है; 2009 और 2012 के मध्य सापेक्षिक गरीबी दर लगभग दुगुनी हो गई और मित्तव्यत्तता नीतियों के परिणामस्वरूप लगभग दो–तिहाई दरिद्र हैं। भौतिक सुविधाओं का गंभीर वचन 2009 में 11% आबाद से 2014 में 21.5%; 2013 में 34% से अधिक बच्चे गरीबी या सामाजिक वंचना के जोखिम से ग्रस्त थे। आबादी के निर्धनतम में से 10% द्वारा अपनी आय का 56.5% खो कर, इन उपयों ने नाटकीय रूप से असमानताओं को बदतर किया है।

उसी समय, जब ग्रीक समाज मानवाधिकारों के उल्लंघन और व्यापक सामाजिक क्षति को अनुभव कर रहा था, विधायी अभिकरणों ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढावा देते हुए ''विशेषाधिकारों की नीति'' का सृजन किया। यह विधायी पहल बहुमुखी है और आपराधिक प्रतिरक्षा शासन की ओर ले जाती है। ऐसा चाहे विशिष्ट व्यक्तियों या समूहों जैसे सीमेन्स, आयुध कार्यक्रम एवं निजीकरण के अभियोजन के बचावों निवारक विशेष रूप से अनुबंधों या सार्वजनिक रियायतों में–या फिर पहले से ही लंबित आपराधिक अभियोजनों में दमनात्मक विधायी हस्तक्षेप जिसमें लंबित अभियोजन का प्रतिबंधन, निलंबन या समाप्ति सम्मिलित हैं। विडंबना है कि, जहाँ लेनदार ग्रीस को कर–परिहार पर प्रहार करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, वे सीमापार के लेनदेन पर 26% कर को समाप्त करना चाहते हैं।

राज्य–कार्पोरेट अपराध अपवाद नहीं अपितु नियम बन कर वैयक्तिक अपराधी या विचलन के कार्य के कहीं आगे जाते हैं। यह उस युग का मुख्य लक्षण हैं जहाँ मानकशून्यता व्याप्त है अर्थात् जहाँ उपलब्ध सामूहिक अभ्यावेदन और सामूहिक चेतना कमजोर हुई हैं। ऐसी राज्य कार्पोरेट मिलीभगत हमारे आधुनिक युग की ''समय की आत्मा'' का प्रतिनिधित्व करती है।

हम एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहे हैं; अनियन्त्रित राज्य–कार्पोरेट अपराध से निपटने के लिए, एक ऐसे समय में जब प्रारंभिक बीसवीं सदी के फासीवादी काल की तरह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, आधुनिक संस्थाएँ और वैज्ञानिक विमर्श प्रशासन, उत्पादन और नागरिक समाज की मौजूदा संरचनाओं से विकृत हो रहे हैं, क्या किया जा सकता है?

हमारे लिए बेहतर दुनिया का सपना देखना जारी रखना महत्व पूर्ण है। इसके अलावा, यद्यपि राज्य और व्यापार का यह सहजीवन लंबे अर्से से अस्तित्व में है, इसे पूरी तरह से कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है और वैज्ञानिकों एवं नागरिकों के रूप में हमें इस पर लगातार प्रश्न उठाने और इसे बेनकाब करना चाहिए। ■

स्त्रातोस जियोरगुलास से पत्र व्यवहार हेतु पता <s.georgoulas@soc.aegean.gr>

> माइसोप्रोस्टॉल के युग में अर्जेंटीना का गर्भपात आंदोलन

जूलिया मैक रेनाल्ड्स–पेरेज, विस्कॉन्सिन–ला क्रॉस विश्वविद्यालय, अमेरिका

वर्जिन की मूर्ति पर, वुमन आन वेव्स अपने संदेश ''आपका निर्णय, सुरक्षित गर्भपात'' का प्रचार और हॉटलाइन परामर्श हेतु फोन नंबर की पेशकश करते हुए।

लेटिन अमेरिका में गर्भपात की बहस ने भूकंप उत्पन्न कर दिया और इस भूकंप का केन्द्र एक छोटी सफेद गोली (दवा) है। क्षेत्र में माइसोप्रोस्टॉल (गर्भपात की दवा) की उपलब्धता ने दूरगामी प्रभावों के साथ गैर–कानूनी गर्भपात की परिपाटी को परिवर्तित कर दिया है। नये स्वयं–सहायता कार्यकर्त्ताओं ने–जिनमें कुछ नारीवादी एवं पेशेवर स्वास्थ्य कर्मी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं–गर्भपात संबंधी राजनीतिक बहस को परिवर्तित कर दिया, कार्यकर्त्ताओं के रूप में उन्होंने गर्भपात के वैधताकरा के निरंतर विरोध के बावजूद इसे अधिक सुगम और अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयास किया।

संपूर्ण लेटिन अमेरिका, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण कैथोलिक क्षेत्र, में गर्भपात लंबे समय से गैर–कानूनी था, फिर भी यह परिपाटी व्यापक रूप से फैली थी। लेटिन अमेरिका में सर्वत्र अमीर महिलाओं को निजी चिकित्सालयों में प्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा सुरक्षित, मंहगे, अवैध गर्भपात के साधन गुपचुप ढंग से प्राप्त हो जाते थे, जबकि निर्धन महिलाएं ऐसी गलियों में अवैध गर्भपात करवाने के लिए बाध्य है जहॉ उचित चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध न होने से उनकी जान का खतरा बना रहता है।

अवैध गर्भपातों की यह दोहरी प्रणाली अपनी अवैधता की प्रक्रिया व इसके विषय में उत्पन्न राजनीतिक बहस को जनता की नजरों से दूर रखती है, परंतु 1990 के दशक के प्रारम्भ से गर्भपात व्यवसाय का स्थान और राजनीति का स्थान बदल गया। माइसोप्रोस्टॉल एक कृत्रिम प्रोस्टाग्लैंडीन है जिसे अल्सर के उपचार के लिए अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा अनुमोदन प्राप्त है, तब से संपूर्ण लेटिन अमेरिका में इस उद्देश्य से फार्मेसी कंपनी इन दवाओं को बेचती है। परंतु माइसोप्रोस्टॉल को गर्भाश्य के सिकुड़ने का कारण भी माना जाता है जो अवैध गर्भपात के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनता है। उन देशों में जहॉ गर्भपात वैध है, माइसोप्रोस्टॉल अक्सर मिफेप्रिस्टोन नामक एक अन्य औषधि के साथ संयोजन करके प्रथम तिमाही में चिकित्सकीय गर्भपात के लिए ली जाती है। आवश्यक रूप से, जब यह दवा स्वयं द्वारा अथवा बिना किसी चिकित्सकीय निरीक्षण के ले ली जाती है तब भी माइसोप्रोस्टॉल असुरक्षित तरीके से गर्भपात कराने की प्राचीन विधियों–Wire-Coat method अथवा Knitting Niddles विधि से अधिक सुरक्षित है।

वर्ष 2012 व 2015 के बीच, मैंने यह समझने के लिए कि कैसे यह नयी औषधीय प्रोद्योगिकी गर्भपात की राजनीति एवं परिपाटी को परिवर्तित कर रही है, अर्जेंटीना में नृजातीशास्त्रीय अनुसंधान आयोजित किया था। अर्जेंटीना में–वास्तव में समग्र लेटिन अमेरिका

> >

माइसोप्रोस्टॉल–गर्भपात करने हेतु व्यापक रूप से वितरित दवा

में–माइसोप्रोस्टॉल की सापेक्षिक रूप से सहज उपलब्धता ने नवाचारी सक्रिय रणनीतियों के अवसर उत्पन्न किये। गर्भपात संबंधी अनेक सक्रिय समूह कार्य करने के लिए अंतराष्ट्रीय अभियानों से प्रेरित थे। वर्ष 2001 में डॉ. रेबेका गेमपर्टस् ने 'लहरों पर महिलाएं' (Women of Waves) नामक चिकित्सकीय सुविधाओं से सुसज्जित जहाज को राष्ट्रों में गर्भपात को प्रतिबंधित कर रखा था वहाँ सुरक्षित गर्भपात के लिए महिलाओं को उस जहाज पर सवार होने के लिए आमंत्रित किया। इस अभियान के बाद, उन्होंने 'वेब पर महिलाएं' शुरू किया, जहाँ संपूर्ण विश्व के लोग औषधिपूर्ण गर्भपात संबंधी आहार संबंधी नियमों के लिए आवेदन कर सकते हैं, संगठन महिलाओं को सीधे ही अचिन्हित पैकेज भेज सकता है जो ऐसे देशों में रहती है जहाँ गर्भपात गैर–कानूनी है। गेमपर्ट्स का संगठन भी संपूर्ण विश्व में गर्भपात से संबंधित हॉटलाइनों का समर्थन करता है, ताकि महिलाएं आवश्यकता होने पर गर्भपात के लिए माइसोप्रोस्टॉल के प्रयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन/संपर्क कर सकती हैं।

जबकि डॉ. गेमपर्ट्स के अंतराष्ट्रीय प्रयासों ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को प्रभावित किया, स्थानीय स्तर पर सक्रिय रणनीतियों पर कम ध्यान दिया गया जो इन नवीन संभावनाओं के जवाब में तेजी से बढ़ी। समग्र लेटिन अमेरिका में युवा नारीवादी कार्यकर्त्ता निर्धन महिलाओं को माइसोप्रोस्टॉल के प्रयोग को सुरक्षित गर्भपात के लिए अधिक सुगम बना रहे थे : कुछ समूह सूचनाएं प्रदान कर रहे थे, अन्य औषधीय गर्भपात सेवाएं उपलब्ध करवाते तथा कुछ पेशेवर चिकित्सकों के समूहों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर एक क्रियाशील भूमिका का निर्वाह करना शुरू कर दिया।

'गर्भपात को गैर–कानूनी बनाने के लिए समलैंगिक एवं नारीवादी अथवा LFDA नामक समूह अर्जेंटीना के बहुत महत्वपूर्ण गर्भपात के लिए सक्रिय समूहों में से एक हैं जो पिछले 7 सालों में उभरा है। LFDA ने 'वेब पर महिलाएं' कार्यक्रम की सहायता से एक सुरक्षित गर्भपात हॉटलाइन शुरू की ओर अब समग्र अर्जेंटीना से महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के विषय में सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, 2013 में प्रारम्भ, LFDA ने ब्यूनस आर्यस के समग्र शहर में गर्भपात संबंधी आमने–सामने के परामर्श हेतु क्लीनिक/चिकित्सालय खोले, जहाँ कार्यकर्त्ता सरल गैर तकनीकी भाषा में सुरक्षित गर्भपात करवाने से संबंधित संपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। ग्राहक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं या तो स्थानीय औषधालय से अथवा काला बाजारी से माइसोप्रोस्टॉल को प्राप्त करें।

दूसरे सक्रिय समूहों की तरह LFDA भी समान सेवाएं उपलब्ध करवाते हुए अपने काम का वर्णन 'सूचना की स्वतंत्रता' द्वारा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की न्यूनतम हानि के आदेश द्वारा सुरक्षित के रूप में करता है, पूर्व का दावा इस तथ्य पर आधारित है कि वे केवल सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं जिन्हें अन्य अनेक साधनों द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वे गोलियां उपलब्ध नहीं कराते, ये कार्यकर्त्ता चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध नहीं करवाते, केवल सूचना देते हैं। 'न्यूनतम हानि' सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे आवश्यकता रहित विनिमय कार्यक्रमों से भाषा उधार लेने का दावा करता है, अवैध गतिविधियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक सामाजिक दायित्व का दावा करता है।

यहाँ तक कि दूसरे कार्यकर्त्ता आगे बढ़ गये। लगभग वर्ष 2014 से, स्थानीय सक्रिय समूहों के एक खुले मंच 'First Responders online' ने एक अंतराष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किया। यह ऑनलाइन नेटवर्क केवल सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाता, अपितु माइसोप्रोस्टॉल उपलब्ध कराना अथवा औषधीय गर्भपात की दवाओं का पूरा कोर्स (अंतराष्ट्रीय सक्रिय संपर्कों द्वारा प्राप्त), साथ ही घर में गर्भपात की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान फोन के माध्यम से सहयोग जारी रखते हैं, जिसे वे 'साथ' होना कहकर पुकारते हैं। क्योंकि ये समूह गर्भपात की दवाएं उपलब्ध कराते हैं और केवल सूचनाएं नहीं, अधिकांश लोग इसे निम्न स्तर पर रखते हैं। ब्यूनस आर्यस की उदार राजधानी शहर के समूहों में सापेक्षिक रूप से खुले में संचालित होती है, परंतु अधिक रूढ़िवादी प्रांतों में, कार्यकर्त्ताओं को अभियोग से बचने के लिए अपने ग्राहकों की बुद्धि पर निर्भर रहना पड़ता है।

अंततः स्वास्थ्य के कुछ पेशेवर लोगों ने अर्जेंटीना सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में 'पूर्व एवं उत्तर–गर्भपात संबंधी सलाह' देके परिवर्तन की शुरूआत की। LFDA कार्यकर्त्ताओं की भांति, ये सेवाएं माइसोप्रोस्टॉल के प्रयोग द्वारा गर्भपात करवाने से संबंधित सूचनाएं विस्तार से उपलब्ध करवाती हैं, माइसोप्रोस्टॉल प्राप्त करने के निर्णय को महिलाओं पर छोड़ कर वैधानिकता के मुद्दे को टाल

>>

देती हैं तथा उनके घरों पर वास्तविक गर्भपात को करने का बीड़ा उठाती है। एक मुठ्ठी पर चिकित्सालयों में, इन सक्रिय पेशेवरों को नगर निगम स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा समर्थन प्राप्त था अथवा ये अपने तात्कालिक निरीक्षकों (सुपरवाइजर) द्वारा वांछित उपेक्षा के शिकार थे। वास्तव में केवल कुछ चिकित्सालय ही सभी गर्भपातों को ''कानूनी संकेतों पर आधारित वैधानिक गर्भावस्था समापन'' की प्रक्रिया के रूप में कर रहे हैं, उनका मानना था कि एक अनचाही गर्भावस्था में स्वास्थ्य खतरा निहित रहता है–इसलिए दण्ड संहिता के प्रावधान पर आधारित सभी गर्भपातों को कानूनी मानना चाहिए जो महिला के स्वास्थ्य को बचाने के लिए गर्भपात की अनुमति देता है। वे अपने मरीजों को प्रत्यक्ष रूप से गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। परंतु उन अधिक स्पष्ट मामलों के बाद भी अनेक स्वास्थ्य पेशावरों ने मुझे साक्षात्कार के दौरान बताया कि वे माइसोप्रोस्टॉल सलाह बंद दरवाजों के पीछे उपलब्ध करवाते हैं, तथा कभी–कभी जब महिलाएं गोपनीयता बनाये रखने का वचन देती हैं तब दवा के लिए नुस्खा अथवा निर्धारित औषधि लिखकर देते हैं।

एक सटीक अनुमान लगाने का ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पता चल सके कि कितने चिकित्सक इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं, यद्यपि निश्चित रूप से वे पदानुक्रमिक पेशे में कम संख्या में ही हैं, जो अभी भी व्यापक स्तर पर एक सामाजिक–रूढ़िवादी, कैथोलिक भूतपूर्व छात्रों के नेटवर्क से नियंत्रित होते हैं। परंतु इन कार्यकर्त्ताओं की गतिविधियों का व्यापक प्रभाव स्पष्ट है क्योंकि कार्यकर्त्ताओं के समूह अपने ग्राहकों से जनसंख्या संबंधी तथा स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े एकत्र करते हैं, जो बाद में गैर–कानूनी गर्भपात के सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे को स्पष्ट बनाने के लिए प्रकाशित किये जाते हैं। रिपोर्ट को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है, चिकित्सकीय पेशेवरों के राष्ट्रीय कांफ्रेसों में उन पत्रों को प्रस्तुत किया जाता है, तथा 'महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन' (CEDAW) के साथ तैयार रिपोर्ट गर्भपात की परिपाटी को 'नारीवादी महामारी विज्ञान' की तुलना में अधिक स्पष्ट बनाती है।

अर्जेंटीना का आंदोलन चिकित्सकीय गर्भपात तक पहुँच को राज्य स्तर पर असफल प्रदर्शित करता है, देश में गर्भपात के कानूनों को आक्रामक ढंग से व्यवस्थित करता है जो परिपाटी को बदलने के बावजूद केवल किताबों में दर्ज है। वास्तव में, इस परिपाटी को सक्रिय रूप से लागू करने की राजनीतिक इच्छा कम स्पष्ट है जो व्यापक है–विशेष रूप से प्रवर्तन के प्रयासों के समय से असुरक्षित युवा महिलाओं के लिए सहानुभूति उत्पन्न कर सकती है, जो कट्टर पुलिस बल के द्वारा पीड़ित नजर आती है। कार्यकर्त्ताओं द्वारा एकत्र किये गये आँकड़ों के अनुसार, दस हजार महिलाओं ने बिना अपना जीवन खतरे में डाले गर्भावस्था को समाप्त करने हेतु सहायता प्राप्त की। इसी बीच अर्जेंटीना का वृहद् नारीवादी आंदोलन गर्भपात को वैधता देने की माँग को निरन्तरता प्रदान करता है।

अर्जेंटीना में हाल में ही हुआ राजनीतिक बदलाव ने नारीवादी कार्यकर्त्ताओं के लिए नई अनिश्चिंताओं को उत्पन्न कर दिया। 2015 के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नाडीज डी किचनर की केन्द्रीय वामपंथी सरकार को विस्थापित करके एक दक्षिण पंथी राजनीतिक दल सत्ता में आया, जो कि दूसरे तरीकों को देखकर खुश दिखता था जिससे इन कार्यकर्त्ताओं ने सुरक्षित प्रक्रियाओं तक पहुंच को विस्तार दे दिया।

हाल ही में, अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने तक्यूमन के रूढ़िवादी उत्तरी प्रांत में हत्या के लिए एक स्थानीय अस्पताल में गर्भपात के लिए सहायता मांगने के बाद एक युवा महिला को दण्डित करने के अर्जेंटीना के निर्णय की आलोचना की। क्योंकि माइसोप्रोस्टॉल का व्यापक तौर पर प्रयुक्त किया जाता है और क्योंकि तथ्यों के बाद इसके प्रयोग को साबित नहीं किया जा सकता, रूढ़िवादी चिकित्सक संदेह करते हैं कि जिस रोगी को गर्भपात होता है उसने दवा का प्रयोग किया है। इस मामले में बेलेन (मीडिया रिपोर्ट में प्रयुक्त एक छद्म नाम) को 8 साल के कारावास की सजा हुयी, वास्तव में एक भयभीत करने वाली स्थिति है–विशेष रूप से तब जब कोई साक्ष्य साबित नहीं कर सकता कि गर्भपात हुआ था। 2016 के प्रारम्भ तक वह पहले ही सुनवाई का इंतजार करते हुए 2 वर्ष जेल में रह चुकी थी। जब लंबी सजा सुनाई गयी, गर्भपात तथा नारीवादी आंदोलनों ने समग्र अर्जेंटीना में बेलेन को मुक्त करने के लिए प्रदर्शन उच्चतम न्यायालय ने बेलेन को छोड़ने की एक लंबित अपील पर आदेश दिया।

क्या अर्जेंटीना में हुआ व्यापक राजनीतिक परिवर्तन गर्भपात कार्यकर्त्ताओं पर और बेलेन पर कार्यवाही की माँग के साथ गर्भपात आंदोलन के विरूद्ध एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न करेगा? जबकि यह नया दक्षिणपंथी बदलाव निश्चित ही चिंताजनक है, यह स्पष्ट है कि इन कार्यकर्त्ताओं का वापस लौटने अथवा धमकाये जाने का इरादा नहीं है, पिछले 2 दशकों से, उनके प्रयासों ने गर्भपात के संबंध में लेटिन अमेरिका की राजनीतिक गतिशीलता को स्थायी रूप से बदल दिया तथा कार्यकर्त्ता उम्मीद करते हैं कि जिन्न को पुनः बोतल में बन्द नहीं किया जा सकता। ■

जूलिया मैक रेनाल्ड्स–पेरेज से पत्र व्यवहार हेतु पता
<julia.mcreynolds@gmail.com>

> मैक्सिको के गर्भपात अधिकारों में परिवर्तन

सुसान लर्नर, द कॉलेज ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको, **लूसिया मेलगर,** आटोनोमस टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको एवं **एग्नेस गिल्यूम,** रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट, फ्रांस

गर्भपात को वैध बनाने के लिए मेक्सिकन आंदोलन

वर्ष 2007 में मैक्सिको के संघीय जिले में (हाल ही में नाम बदलकर मैक्सिको सिटी कर दिया) गर्भावस्था के प्रारम्भिक 12 सप्ताह में गर्भपात करने को वैधता प्रदान कर दी गई – यह नागरिक समाज की एक जीत थे जो महिलाओं को 1990 से 'चुनने का अधिकार' देने के लिए लड़ी जा रही थी। हालांकि, अधिकांश मैक्सिको में गर्भपात पर प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया गया था।

वर्ष 2008 से 'गर्भाधान के समय से जीवन की सुरक्षा' की कोशिश हेतु नवीन कानून एवं संवैधानिक सुधारों को अभी हाल ही में वेराक्रूज में जुलाई 2016 में मैक्सिको के 18 राज्यों में पारित कर दिया। इन तथाकथित सुधारों को कौन और किन निहितार्थों के साथ संचालित करता है?

मैक्सिको में गर्भपात की चर्चा में सम्मिलित विवादों एवं मुख्य कर्त्ताओं को जनसंख्या राजनीति के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। 1970 के दशक में मैक्सिको की सरकार ने प्रजनन दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों एवं अन्य सम्बंधित पहलों को बढ़ावा दिया, जैसे परिवार के आकार को नियंत्रित करने तथा परिवार के स्वास्थ्य, जीवन एवं सुखों में सुधार लाने के लिए महिलाओं को विभिन्न विकल्प उपलब्ध करवाना। इसकी सफलता के बावजूद, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने के इनके प्रयासों का समर्थन करने वाली व्यापक सामाजिक और आर्थिक नीतियों की अनुपस्थिति में, जनसंख्या की भौतिक दशाओं में सुधार नहीं हुआ।

1990 में राष्ट्रीय नीति 'प्रजनन स्वास्थ्य पर बल' पर केन्द्रित हो गयी, मैक्सिको की सरकार के बाद 1994 में जनसंख्या एवं विकास पर अंतराष्ट्रीय कांफ्रेंस में कार्यवाही के कार्यक्रमों की पुनः पुष्टि की गई। 'यौनिक एवं प्रजनन अधिकारों को प्राथमिकता' के इस समझौते पर काहिरा में हस्ताक्षर हुये, जो यह तर्क देता है कि अनुचित स्थितियों में गर्भपात करवाना एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को उत्पन्न करता है, सुरक्षित गर्भपात तक महिलाओं की पहुँच की अनुमति के लिए, साथ ही कानूनी बाध्यताओं एवं गर्भपात–विरोधी कानूनों को सरल बनाने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं का आह्वान किया गया।

पिछले 20 वर्षों से नारीवादी एवं शिक्षाविद् मैक्सिको के संघीय जिले में गर्भपात को वैधता देने में व्यस्त हैं, परिणाम स्वरूप मैक्सिको सिटी में औसत एवं धीमी गति से सुधार हुआ। 2007 में, संघीय जिले के स्थानीय विधानमंडल ने 12 सप्ताह की गर्भावस्था तक गर्भपात की अनुमति के लिए वोट किया (यद्यपि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर गर्भावस्था के बाद के तिमाही में गर्भपात अवैध है)। आवश्यक रूप से, गर्भावस्था को 'मानव प्रजनन की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में परिभाषित करते हुए, जो गर्भकला में भ्रूण के अधिरोपण के साथ शुरू होती है', संघीय जिले के सुधार, कब और कैसे मानव जीवन प्रारम्भ होता है, पर किसी भी चर्चा की उपेक्षा करते हैं। 2007 के कानून के तहत, चिकित्सक 'कर्त्तव्यनिष्ठ विरोधकर्ता' के रूप में गर्भपात करने से मना कर सकते हैं, परंतु कानून द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों को ऐसे चिकित्सकों को सम्मिलित करना चाहिए जो अपने स्टॉक में विरोधकर्ता नहीं है। उदार दलों, सत्ता में विद्यमान PRI सहित, ने इसके पक्ष में मतदान किया जबकि दक्षिण पंथी PAN ने इसके विरूद्ध मतदान किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं शहर के विशिष्ट अधिकारियों को विवश करती हैं

> >

कि वे सुरक्षित एवं निःशुल्क गर्भपात सेवाएं उपलब्ध करवायें, कानून सभी महिलाओं की गर्भावस्था की वैधानिक समाप्ति तक पहुँच की गारंटी देता है। आवश्यक रूप से, कानूनी गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, का निर्णय करने की स्वतंत्रता देता है : महिला गर्भावस्था को जारी रख सकती है, बच्चे को किसी को गोद दे सकती है, अथवा गर्भावस्था को समाप्त कर सकती है, एक बार सूचित करके सहमति पर हस्ताक्षर कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, वे अतिरिक्त अनियोजित गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भनिरोधक विधियों तक पहुँच की गारंटी देते हैं, (इस प्रकार, बाद के गर्भपात से बचा जा सके)।

इस प्रकार, मैक्सिको शहर का सुधार असुरक्षित गर्भपात, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं भेदभाव को अपना मुद्दा बनाता है। इसके अतिरिक्त, यह मानवाधिकारों की रक्षा करत है, एक महिला के अपने शरीर, अपनी यौनिकता एवं प्रजनन स्वायत्तता के संदर्भ में अपने निर्णय लेने के अधिकार को स्वीकारता है। पिछले 9 वर्षों से इस सुधार ने 160,000 से अधिक महिलाओं–अन्य मेक्सिकन राज्यों की महिलाओं सहित जो इस प्रक्रिया के लिए मैक्सिको शहर की यात्रा कर सकती हैं–के सुरक्षित गर्भपात की सुविधा दी है।

कैथोलिक पदानुक्रम द्वारा संचालित तथा इवानजेलिकल एवं अन्य इसाई संप्रदायों द्वारा समर्थित–संकीर्णतावादी ताकतों ने लंबे समय तक प्रतिक्रिया नहीं की। विश्व के अधिकांश भाग में रूढ़िवादी जोर देते हैं कि 'जीवन की रक्षा' के लिए महिलाओं की स्वतंत्रता एवं जीवन की अधीनस्थता आवश्यक हैं, भ्रूण, जिसे एक 'व्यक्ति' माना जाता है, के तथाकथित अधिकारों में असुरक्षित गर्भपात के यथार्थ की स्वीकृति अथवा महिलाओं के स्वास्थ्य अथवा पारिवारिक जीवन पर उन गर्भपातों के प्रभाव से इनकार करते हैं। दूसरी तरफ, नारीवादी समूह महिलाओं के अधिकारों तथा स्वास्थ्य के सार्वभौमिक अधिकारों का प्रमुखता से बचाव करते हैं, यह मानते हुए कि मातृत्व में प्रवेश स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक होना चाहिए तथा मैक्सिको के लोकतंत्र में चर्च व राज्य के पृथक्करण का सिद्धांत केन्द्रीय विषय होना चाहिए।

जैसे ही मैक्सिको सिटी ने व्यापक पैमाने पर प्रथम–तिमाही में गर्भपात की स्वीकृति प्रारम्भ की, प्रोविडा (Provida) (पूर्व–जीवन), प्रोफेमिला (Profamila) (पूर्व–परिवार) जैसे संगठन एवं मैक्सिको के कैथोलिक बार एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि ''गर्भधारण के समय से ही जीवन प्रारम्भ हो जाता है तथा उस समय से ही मनुष्य के रूप में उसके अधिकार भी अस्तित्व में आ जाते हैं।'' गर्भपात विरोधी कार्यकर्त्ताओं ने अनेक प्रकार की रणनीतियों जैसे सड़कों पर निरंतर प्रदर्शन, विभिन्न शहरों में बिशप द्वारा कार्यवाही का आह्वान, गर्भपात करवाने से महिलाओं को रोकने की प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रचार करना तथा मुकदमेबाजी को अपनाया। उसी प्रकार, उन्होंने समान लिंग के एक–साथ होने का भी जोरदार विरोध किया जिसे पहले से ही वैधता प्राप्त थी तथा परिवार नियोजन एवं सार्वजनिक विद्यालयों में सेक्स एजुकेशन के विरूद्ध लड़े अथवा संघर्ष किया। अधिक सूक्ष्मता से उन्होंने 'यौनिक एवं प्रजनन अधिकार' शब्द को सफलतापूर्वक हटा दिया तथा अनेक सार्वजनिक – राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय दस्तावेजों से जेण्डर/लैंगिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भों को हटा दिया।

वर्ष 2008 में, रूढ़िवादी समूह उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुधारों को चुनौती देने के लिए उपस्थित हुए। यद्यपि न्यायालय ने गर्भपात की वैधता को संवैधानिक पाया, उनका निर्णय तीन अतिरिक्त निष्कर्षों पर आधारित था। पहला, न्यायालय ने एक महिला का उसके अपने शरीर पर अधिकार को स्थापित किया–ऐसा अधिकार जिसका अर्थ है कि राज्य महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण करेगी ताकि वे अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के विषय में तथा अपने जीवन के विषय में स्वयं निर्णय ले सकें। दूसरा, हालांकि, न्यायालय ने निर्णय दिया कि जीवन का अधिकार ना ही एक 'निरपेक्ष अधिकार' है ना ही अन्य अधिकारों से ऊपर 'सर्वोच्च अधिकार' जो संविधान एवं अंतराष्ट्रीय संधियों ने स्थापित किये हैं; इस प्रकार जब अधिकार एक–दूसरे से उलझने लगते हैं, विधानमंडल को विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अंततः न्यायालय ने, दूसरे निष्कर्ष पर आधारित, स्थानीय दण्ड संहिता में बदलव लाने के लिए स्थानीय विधानमंडलों की स्थापना की।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण, रूढ़िवादी समूह राज्य के संविधान अथवा दण्ड संहिताओं में संशोधन लाने के लिए राज्य के विधानमंडलों के साथ हो गये, ''गर्भाधान अथवा 'निषेचन' के समय से जीवन की सुरक्षा'' का दावा करने के लिए तथा महिला को दण्डित करने के लिए जिसने गर्भपात करवाया है।

2016 के मध्य तक, कैथोलिक चर्च के समर्थन तथा विधानमंडलों के सभी राजनीतिक दलों–जिसमें कुछ वामपंथी भी शामिल थे–के समर्थन से गर्भपात विरोधी ताकतों ने मैक्सिको के 18 राज्यों में अपने लक्ष्य को पूरा किया। इन नये कानूनों के कारण, मैक्सिकन महिलाएं वर्तमान में जेल में काम कर रही है, कभी–कभी 'नातेदारी द्वारा नरहत्या (अर्थात् शिशु हत्या सहित) को बढ़ावा' देने के कारण दोषी ठहराया गया, कभी 20 यो 30 वर्षों के लिए कारावास हुआ। अन्य मामले मनोचिकित्सक के हस्तक्षेप का विषय बने, जैसे कि अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करना एक मानसिक बीमारी थी। देश के वैधानिक नियमों की अनुपालना में अधिकांश मैक्सिको सिटी इन नये दण्डों को शीर्ष पर लाने में लगातार असफल रहे, जो कि कुछ स्थितियों में 'कानूनी एवं सुरक्षित गर्भपात की अनुमति देता है, जैसे बलात्कार के मामले में (एकमात्र संकेत जिसे संपूर्ण देश में कानूनी रूप से वैधता प्राप्त है), भ्रूण की असामान्यता के मामले में, अथवा जब महिला का जीवन अथवा स्वास्थ्य खतरे में हो।

2016 के मध्य से, अभी भी दो विरोधी स्थितियों पर विवाद जारी है। रूढ़िवादी समूह 'जीवन की रक्षा', अधीनस्थ महिलाओं के जीवन एवं जीवन की स्वतंत्रता तथा भ्रुण से सम्बद्ध अधिकार, जिसे एक कानूनी व्यक्ति माना जाता है, के लिए तर्क देते हैं। ये समूह असुरक्षित गर्भपात के परिणामों जैसे मातृ मृत्यु तथा रूग्णता अथवा परिवार पर इसका प्रभाव स्वीकारने में असफल रहे हैं। उदारवादी समूह, दूसरी तरफ, महिलाओं के अधिकारों की प्रमुखता, स्वतंत्र रूप से चुने गये मातृत्व, स्वास्थ्य का सार्वभौमिक अधिकार तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य के सम्मान की माँग, जो मैक्सिको के संविधान की मुख्य अवधारणा है, का समर्थन करते हैं।

मैक्सिको में महिलाओं के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष जारी है। प्रायः नारीवादी एवं महिलाओं के गैर–सरकारी संगठन (NGOs) अग्रसक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक हो गये। जब रूढ़िवादी ताकतें गर्भपात को गैरकानूनी बना रही थी। यह गतिशीलता बदलनी चाहिए। हमारे विचार में, नागरिक समाज को अपनी आवाज पुनः उठाना चाहिए तथा राष्ट्रीय स्तर पर गर्भपात के उदारीकरण एवं वैधकरण की मांग करनी चाहिए। ■

सभी से पत्र व्यवहार हेतु पता :
सुसान लर्नर <slerner@colmex.mx>
लूसिया मेलगर <lucia.melgar@gmail.com>
एग्नेस गिल्यूम <Agnes.Guillaume@ird.fr>

> हिंसा के रूप में गर्भपात : पेरू का संघर्ष

इरिका बूस, पेसीफिक विश्वविद्यालय, पेरू तथा ISA की माइग्रेशन (RC 31), वूमन एंड सोसायटी (RC 32), सोशल मूवमेंटस, कलेक्टिव एक्शन एंड सोशल चेंज (RC 48) तथा फेमिली रिसर्च (RC 06) शोध समितियों के सदस्य

लीमा, पेरू में 23 मार्च, 2013 को गर्भपात के विरूद्ध ''जीवन के लिए महान मार्च''।
चित्र : पाउलो एग्यूलर। इ.पी.ए.

अगस्त 2016 के मध्य में, हजारों पेरूवासी "Ni Una Menos" (कोई कम नहीं है) का नारा लगाते हुए लीमा की गलियों में लामबंद अथवा एकजुट हुए। प्रदर्शनकारियों के मध्य पेरू के हाल ही में चुने गये राष्ट्रपति, शारीरिक और यौनिक हिंसा से पीड़ित लोग, महिला एवं नारीवादी संगठनों के सदस्य, राजनीतिक दल से सम्बद्ध एवं मंत्रीगण एवं कांग्रेस के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की निंदा करने वाले इस प्रदर्शन को पिछले 40 सालों में पेरू के सबसे महत्व पूर्ण सामाजिक आंदोलनों में से एक के रूप में वर्णित किया गया, क्योंकि इसमें पुरूषों एवं महिलाओं, लड़कियों एवं लड़कों, अभिभावक एवं बच्चों, दादा–दादी व नाना–नानी एवं उनके पोते–पोतियों व नाते–नातिनों ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन किया।

एक महिला को एक होटल के स्वागत क्षेत्र (रिसेप्शन) में अपने पूर्व पुरूष–मित्र

> >

(बॉय फ्रेंड) द्वारा बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा है, से सम्बद्ध एक वीडियों ने इस प्रदर्शन के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया। हालांकि इस मामले को खारिज करते हुए जज ने निर्णय दिया कि महिला के घाव बलात्कार या हत्या के इरादे को व्यक्त नहीं करते।

''जब एक पर प्रहार होता है, तो हम सब पर प्रहार होता है'', सामूहिक रूप से 'कोई कम नहीं है' के नारों के तहत महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं भेदभाव का विरोध करने के लिए पेरूवासियों का आहवान किया गया। यहां तक कि आयोजक भी इस व्यापक प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थे क्योंकि इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं समग्र लेटिन अमेरिकी शहरों में महिलाओं के विरूद्ध प्रबल हिंसा और खंडित न्याय प्रणाली की समाप्ति की माँग से सम्बद्ध प्रदर्शनों को समानान्तर रूप से व्यक्त करती है। अनेक लेटिन अमेरिकियों के लिए ये प्रदर्शन उम्मीद के क्षण का प्रतीक थे : चीजे बदल रही हैं एवं महिलाओं के मुद्दे, विशेष रूप से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, जन चेतना में अग्रणी हुए हैं।

लेटिन अमेरिकी नारीवादियों के प्रजनन के अधिकारों की माँगों से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा–तथा आक्रमणकारियों को दण्ड से मुक्ति की ओर बल पर बदलाव को चिन्हित करता है। ''महिलाओं (एवं नाबालिगों) के विरूद्ध यौनिक हिंसा'' के संदर्भ में गर्भपात के विषय में बहस पर पुनः विचार करके तथा 'बाध्यतामूलक मातृत्व' (अथवा बाध्यतामूलक अवैध गर्भपात) पर प्रकाश डालते हुए नारीवादियों ने राज्य की हिंसा से शीर्ष पर स्थित यौनिक हिंसा पर बल देने वाली बहस को पुनः आकार दिया–इस मूल विचार के विपरीत जो प्रजनन के अधिकारों को व्यक्तिगत इच्छा का विषय मानते थे।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का विचार इस बात का विरोध करता है कि महिलाआं के विरूद्ध हिंसा को एक नैतिक मुद्दे के रूप में देखने की बजाय, गर्भपात को महिला के स्वच्छंद व्यवहार के बाद उसकी 'स्वार्थी' इच्छा के परिणाम के रूप में देखा जाये। अभियान का विरोध करके यह सुझाव दिया गया कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा अस्तित्व में नहीं है अथवा इसका कोई मतलब नहीं है। यह संभावित शक्तिशाली विचार पीड़ित के रूप में महिलाओं के चयन का नकारात्मक पहलु है जो लम्बे समय से चली आ रही जेण्डर रूढ़ियों और पदानुक्रमों को संभावित मजबूती देता है। फिर भी, गर्भपात तक पहुंच को महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में बदलना, इसे यौनिक हिंसा के उन्मूलन से जोड़ना, बलात्कार के मामले में गर्भपात को कानूनी रूप देने के प्रयास के लोकप्रिय समर्थन को विस्तार देता प्रतीत होता है।

गर्भपात को कानूनी रूप देने के लिए राज्य पर सहज रूप से बल देने के बजाय कार्यकर्त्ता नागरिक समाज से, पेशेवर लोगों जैसे चिकित्सकों एवं धार्मिक समूहों के सदस्यों से महिलाओं के अधिकारों तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के विषय में पेरूवासियों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए अपील कर रहे हैं। प्रजनन अधिकार के विचार से यौनिक हिंसा पर बल की तरफ हुये इस व्यापक बदलाव ने LGBT कार्यकर्त्ता महिलाओं के लोकतांत्रिक संगठन, कैथोलिक समूह, युवा तथा प्रसिद्ध हस्तियों सहित अन्य समूहों में एक वृहद् आंदोलन को उत्पन्न किया है। बलात्कार के मामले में गर्भपात को कानूनी रूप देना केवल 'कुछ' नारीवादियों के बीच समर्थन प्राप्त करने के बजाय वृहद पेरू समाज में समर्थन प्राप्त करता प्रतीत होता है। यह अभियान 'नीचे से ऊपर उपागम' (विशेष रूप से आम पेरूवासियों के हस्ताक्षर एकत्र करना) तथा 'ऊपर से नीचे उपागम' (एक टेलीविजन विज्ञापन में लोकप्रिय हस्तियों, कलाकारों तथा राजनीतिज्ञों के साथ–साथ आम नागरिकों को सम्मिलित करना) दोनों उपागमों को संयुक्त रूप से प्रयुक्त करता है। अभियान में सामूहिकताओं को एक साथ, जैसे लाल कालीन (Aifombra Roja), प्रदर्शनों एवं मेलों में समर्थकों का चयन किया। इस संदर्भ में जहाँ राज्य की संस्थाओं में कम विश्वास हो, अभियान नागरिकों की सहभागिता पर बल देकर लोकतंत्र को सक्रिय करने के लिए कार्यकर्त्ताओं की प्रतिबद्धताओं को जांचता है।

अब तक, विधायकों से एक मजबूत प्रत्युत्तर प्राप्त करने में यह नया विचार असफल रहा। उदाहरण के लिए, पेरू में बलात्कार के मामलों में गर्भपात की अनुमति देने हेतु पेरू के संविधान को बदलने का एक प्रयास असफल रहा, उसी प्रकार, कांग्रेस संबंधी एक बिल जिसने बलात्कार के मामले में गर्भपात को कानूनी रूप दिया था, को स्थगित कर दिया गया जबकि अधिकांश विधायक स्पष्ट रूप से शारीरिक हिंसा से पीड़ित व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखते हैं, जिसमें खरोंच और गंभीर चोटों को सम्मिलित किया जाता है, जब शारीरिक हिंसा (बलात्कार) का परिणाम गर्भधारण होता है, किसका अधिकार प्रबल रहना चाहिए का सवाल एक नैतिक मुद्दा बन जाता है।

फिर भी, जन वार्ता एवं नीति में हाल में कुछ महत्वहीन बदलाव ही देखे गये। 1924 में पेरूवियन दंड संहिता ने उन मामलों में जहाँ गर्भवती महिला का जीवन खतरे में था, उपचारात्मक गर्भपात को कानूनी रूप दे दिया, परंतु इन मामलों में गर्भपात करने हेतु चिकित्सीय कर्मियों को कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया–अर्थात् कोई चिकित्सक जो एक जोखिमपूर्ण गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय करता है, जेल में डाला जा सकता है। अगले 90 वर्षों के लिए अधिकांश चिकित्सक किसी भी परिस्थिति में गर्भपात करने के अनिच्छुक बने रहेंगे।

हालांकि 2014 में, विशेष रूप से कैथोलिकों एवं इवान–जेलिकलस् की व्यापक आलोचना के बावजूद पेरू ने अंततः एक प्रोटोकाल अपना लिया जिसके द्वारा चिकित्सक जोखिमपूर्ण गर्भावस्थाओं को समाप्त करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। बाधाएं पूरी तरह लागू रहेंगी : क्योंकि कुछ चिकित्सक नहीं जानते कि गर्भपात कैसे करते हैं, महिलाओं संबंधी सूचनाओं का अभाव तथा भय एवं शर्म प्रोटोकॉल के प्रयोग को हतोत्साहित करता है यहाँ तक कि जब गर्भवती महिला का जीवन खतरे में है।

इस नवीन प्रोटोकॉल को अपनाना इस बात का संकेत करता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में गर्भपात अधिकार को तैयार करना इसे प्रजनन अधिकार के रूप में प्रस्तुत करने की तुलना में अधिक सफल हो सकता है। 'कोई कम नहीं है' का व्यापक प्रदर्शन सुझाव देता है कि महिलाओं के मुद्दे पेरू की राजनीतिक बहस में अग्रणी हो सकते हैं, परंतु क्या यह अर्थपूर्ण परिवर्तन लायेंगे, विशेष रूप से गर्भपात के उपचार में, अभी देखना बाकी है। ■

इरिका बुस से पत्र व्यवहार हेतु पता
<e.busse@up.edu.pe>

> अरब जगत में समाज विज्ञान

मोहम्मद ए. बेमयेह, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय, यू.एस.ए., इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल रिवयूस् के संपादक, अलगाव सिद्धांत एवं रिसर्च की शोध समिति (RC 36), जीवी एवं समाज (RC 38) पर आई.एस.ए. शोध समिति (RC 38) के सदस्य

"नये काल के लिए नया ज्ञान'' हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट अरब दुनिया में समाज विज्ञान : उपस्थिति के स्वरूप की महत्वकांक्षा का सार प्रस्तुत करता है। (http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf).[1] अरब काउंसिल ऑफ सोशल साइंसिस (ACSS) द्वारा प्रायोजित, रिपोर्ट को तैयार करने में दो वर्ष का समय लगा, जिसमें शोधकर्ताओं की टीम ने अपना योगदान दिया। रिपोर्ट में प्रयोग लिये गये लगभग समस्त आंकड़े मौलिक हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट टीम ने प्रथम बार एकत्रित किया है।

एक तरफ जहाँ रिपोर्ट अरब विश्विद्यालयों, शोध केन्द्रों, व्यवसायिक संगठनों एवं विद्धतापूर्ण सामयिक पत्रों में समाज विज्ञानों के आकार एवं प्रकृति पर गणनात्मक एवं गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध कराती है, वहीं वह जन समाज विज्ञान पर भी व्यापक रूप से देखती है। नागरिक समाज सोसाइटी संगठन समाज विज्ञान को किस तरह अपने कार्य में प्रयोग करते हैं, के साथ ही अरब सार्वजनिक क्षेत्र (जैसे–अरब समाचारपत्र टीवी के कार्यक्रम, सांस्कृतिक सामयिक पत्र एवं प्रसिद्ध पत्रिकायें जैसे क्षेत्रों में) में किस प्रकार समाज विज्ञान के आंकड़ों का प्रयोग होता है, का अध्ययन करती हैं।

हमने पिछले दो–तीन दशकों में, अरब प्रदेश के 22 देशों में समाज विज्ञानों को आश्रय देने वाली संस्थाओं में घातांकी वृद्धि, को प्रलेखन किया है। अरब प्रदेश वर्तमान विश्वविद्यालयों में से 70 प्रतिशत प्रारम्भिक दशक 1990 के अस्तित्व में आये; 1980 के दशक के प्रारम्भ से अरब की विद्वतापूर्ण पत्रिकाओं की संख्या में चार गुना वृद्धि हुयी है, जबकि इसी अवधि के दौरान शोध केन्द्रों की संख्या में कम से कम छः गुना वृद्धि हुयी है। पिछले दो या तीन दशकों में अरब जगत में एक शांत ज्ञान की क्रांति ने अरब संसार मूक ज्ञान क्रांति आकारित हुई है, यद्यपि हमें अभी भी क्रांति के वास्तविक विषय वस्तु के संबंध में ज्यादा मालूम नहीं है।

दिलचस्प बात यह है कि, सान, की संस्थाओं का यह विस्तार राष्ट्रीय संपदा से स्वतन्त्र प्रतीत होता है; हम इसे धनी एवं गरीब देशों में समान रूप से देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि धन–संपदा से ज्यादा अन्य कारक जैसे–शोध के लिये स्वतंत्रता, अपेक्षाकृत मजबूत नागरिक समाज जो समाज विज्ञान के शोधको प्रोत्साहित करता है और लाभान्वित होता है, देश में अपेक्षाकृत बड़ा शिक्षित वर्ग, देश में स्थानीय विकास में अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी का स्तर एवं स्थानीय ज्ञान समुदाय का वैश्विक समाज विज्ञानों से संपर्क की शक्ति, आवश्यक है। इसी अवधि में नागरिक समाज के विकास को, समाज विज्ञान के विकास से संबंधित देखा जा रहा है और दोनों ही अरब विद्रोह, जो 2010 के अंत में प्रारंभ हुआ और अभी भी प्रकट हो रहा है, से सम्बन्धित कारकों के वृहद समूह का भाग हो सकते हैं।

रिपोर्ट अरब विश्वविद्यालयों के भीतर, काफी असंतुलन को प्रलेखित करती है। अरब विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण समाज विज्ञानों की फैकल्टी का एक चौथाई भाग अपने खाते में लिये हुये अर्थशास्त्र समाज विज्ञानों में सबसे आगे खड़ा है। 2% फैकल्टी के साथ मानवशास्त्र मुश्किल से ध्यान देने योग्य है और अन्य समाजविज्ञान इन दो चरम सीमाओं के मध्य में कहीं आते हैं।

मगर, ज्यादातर विश्वविद्यालय शिक्षण पर बहुत अधिक केन्द्रित रहते हैं, जिसका अर्थ है कि वो शोध और नागरिक कार्यों में संलग्न होने के प्रति आशावान समाज वैज्ञानिकों को कम समय और कम प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यह भूमिका अरब के शोध केन्द्र को निभानी होती है, जो क्योंकि, वे विषय के बजाय थीम पर आधारित होते हैं, अंतः वैषयिक अध्ययन के साथ नागरिक संलग्नता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। शोध केन्द्र, जिनमें से अधिकतर अभी हाल ही में अस्तित्व में आये, भी संतोषजनक विद्वतापूर्ण उत्पादन भी दिखाते है, साथ ही अरब संसार के विद्वतापूर्ण सामयिक नियत कालिक पत्र का प्रकाशन करते है। लेबानन, फिलीस्तीन एवं जॉरडन में उनकी जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक संख्या के शोध केन्द्र, स्थित हैं, यहाँ तक कि डजीबोयटी कतार एवं बाहरेन जैसे धनी देशों से भी आगे हैं।

दिलचस्प बात है, कुवैत एवं सउदी अरब जैसे धनी देश मध्यम स्तर की शोध उत्पादकता से ज्यादा कुछ नहीं दिखाते है। यह निष्कर्ष सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय रैकिंग सूचकांकों के विपरीत प्रतीत होता है, जो हमारे दृष्टिकोण से, अरब ज्ञान स्थल को सही ढंग से प्रस्तुत करने में असक्षम है–आंशिक रूप से इसलिये क्योंकि वो यूरोपीय भाषाओं में एवं विशिष्ट प्रतिष्ठानों में प्रकाशित करते हैं। यह रैंकिंग प्रथायें भी, ऐसा प्रतीत होता है कि पदसोपान के आधिपत्य की बजाय ज्ञान की विषय वस्तु से, उसके औचित्य एवं समाज जहाँ कि उसका उत्पादन हुआ है, में उसकी उपयोगिता में वास्तविक रूचि से, संचालित होती हैं। लगभग आधी रिपोर्ट जनक्षेत्र में समाज विज्ञानों को समर्पित है। नागरिक समाज संगठनों, समाचारपत्रों, लोकप्रिय पत्रिकाओं, टेलीविजन कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक नियतकालिक पत्र यह बताते हैं कि समाज विज्ञानों को अधिकतर संकुचित प्रारूप में, भिन्न दरों पर एवं विभिन्न रूपों में दर्शाया जाता है। रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि नागरिक समाज संगठन समाज विज्ञानों का इस्तेमाल और उत्पीड़न भी करते हैं, यद्यपि उन रूपों में जो उनके मिशन के लिये सही हो। यह ऐसा निष्कर्ष है जो बताता है कि अरब समाज

>>

> *"व्यापक सामाजिक परिवर्तन अरब समाज वैज्ञानिकों को लिए एक प्राथमिक चिंता का विषय रहा है"*

विज्ञानों की अभी हाल ही की वृद्धि में एवं अरब नागरिक समाज की बढ़ती हुयी दृश्यता में कुछ संबंध है। अन्य सभी जन क्षेत्र अभिव्यक्ति मार्गों में से, सांस्कृतिक नियतकालिक पत्र समाजशास्त्र शोध के लिये खुले रहते है। उनके लगभग 20% पृष्ठ समाजशास्त्र लेखों को समर्पित रहते हैं, हालाँकि उन तरीकों में जो यह प्रतिबिम्बित करते हैं कि वो सांस्कृतिक समुदाय के विषय में अकादमिक समाज विज्ञानों से अधिक चिंतित रहते है। समाचार पत्र, प्रसिद्ध पत्रिकायें एवं टेलीविजन कार्यक्रम समाज विज्ञान को कम समय एवं क्षेत्र देते है। उदाहरण स्वरूप फिलीस्तनी के समाचार पत्र अल–कूद्स या कुवैत की लोकप्रिय पत्रिका अल–अरबी में जन समाज विज्ञान के 'अनुकरणीय' रूपों को देख प्रतीत होता है कि गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है।

व्यापक सामाजिक परिवर्तन, चाहे वो क्रांतिकारी अथवा सुधारक प्रारूप में, थे, अरब समाज वैज्ञानिकों को लिए एक प्राथमिक चिंता का विषय रहा है, विशेषतः पिछले पाँच वर्षों में (जनवरी 2010 – दिसंबर 2014) । इस अवधि के दौरान हमारा सामग्री विश्लेषण दिखाता है कि अरब समाज वैज्ञानिकों के रूचि क्षेत्र में ''अरब बसंत'' अग्रणी रहा है। इसके साथ ही, संबंधित विषय जैसे ''प्रजातंत्र'', ''अधिकार'', ''तानाशाही'', ''सहभागीता'', ''नागरिक समाज'', जैसे अन्य सम्बन्धित विषय भी रूचि क्षेत्र रहे है। रिपोर्ट ने पाया कि महिला संबंधित मुद्दें विषय के रूप में हर जगह काफी प्रत्यक्ष रहे है। ये मुद्दें ''पारम्परिक'' मुद्दों के जैसे परिवार अथवा संतान के बजाय अधिकतर अधिकारों पर, नागरिकता पर एवं सहभागिता पर चर्चा से संबंधित है ''युवा'', ''शिक्षा'', यहाँ तक कि ''विकास'' जैसे सामाजिक परिवर्तन के विशिष्ट मार्गों पर शोधकर्ताओं ने कम ध्यान दिया है। दिलचस्प यह है, कि कुछ अपेक्षित विषय प्रत्यक्ष रूप से गायब थे, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक ''मुस्लिम दुनिया'' जैसे विषय का गायब होना। जहाँ एक तरफ पश्चिम में इस विषय को एक सार्थक विश्लेषणात्मक श्रेणी के रूप में देखा जाता है वहीं दूसरी तरफ अरब के समाज वैज्ञानिक इस विष्ज्ञय की पूर्णतया उपेक्षा करते हैं। यह शायद इसलिये कि वे ''मुसलिम दुनिया'' को एक संसक्त विश्लेषणात्मक श्रेणी के रूप में नहीं देखते हैं, यद्यपि वो ''इस्लाम'' एवं धार्मिक राजनीति का समाज विज्ञान परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करते हैं।

यह रिपोर्ट निष्कर्ष देती है कि अरब समाज विज्ञान समकालीन अरब ज्ञान स्थल के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में अपने आप को स्थापित करता जा रहा है, इसके बावजूद कि नीति निर्माणकर्ता शोध की उपेक्षा करते हैं। अरब समाज विज्ञानों पर भविष्य में रिपोर्ट, इस लक्ष्य के साथ कि यह निरीक्षण किया जा सके कि वैश्विक समाज विज्ञानों एवं प्रदेश के भविष्य में समाज विज्ञानों का क्या योगदान है, अब हर दो वर्षों में नियोजित की गयी हैं। ■

मोहम्मद बेमयेह से पत्र व्यवहार हेतु पता <mab205@pitt.edu>

[1] संपादक नोट : मोहम्मद बेमयेह यहाँ चर्चित रिपोर्ट के लेखक हैं।

> अरब क्षेत्र में
समाज विज्ञान की नई अवसंरचनायें

सेतेनी शमी, अरब समाज विज्ञान परिषद, लेबनान

अरब समाज विज्ञान परिषद द्वारा आयोजित द्वितीय संगोष्ठी, मार्च 2015

अरब प्रदेश सामाजिक–आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करता है। साथ ही, वह मजबूत शैक्षणिक अकादमिक एवं शोध क्षमताओं के अभाव से ग्रस्त है, जो इन चुनौतियों पर प्रकाश डाल सकती हैं, सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण, सार्वजनिक बहस का पोषण या लोक नीतियों को सूचित कर सकती हैं। जैसा कि कई संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि अरब राज्यों की ज्ञान की स्पष्ट आवश्यकता के लिये मजबूत क्षमता, गुणवत्तता, पहुँच, रेंज एवं क्षेत्र में शोध का प्रभाव–विशेषतः सामाजिक शोध का, की आवश्यकता है।

इस बढ़ती हुयी जागरूकता ने पिछले दशक में विभिन्न पहलों को प्रेरित किया है जिनका लक्ष्य इन में से कुछ चुनौतियों को संबोधित करना था। उच्च शिक्षा एवं शोध की नवीन संस्थाओं को स्थापित किया गया, साथ ही प्रदेश में स्नातक अध्ययन के लिये अधिक छात्रवृत्ति अवसरों को

> >

प्रदान किया गया। शैक्षणिक उपलब्धि के लिये बड़ी संख्या में पुरस्कारों का सृजन किया गया जबकि व्यावसायिक संगठनों की संख्या भी धीमी गति से बढ़ रही है। हालांकि, समाजविज्ञानों पर केन्द्रित कार्यक्रम एवं अवसर काफी सीमित संख्या में हैं एवं अवसर अभी भी अरब प्रदेश के सभी देशों के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।

इस संदर्भ में, चिंतित अरब सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अरब समाज विज्ञान परिषद का विकास किया गया, ये वैज्ञानिक प्रथम बार 2006 में मिले उन तरीकों पर चर्चा करने के लिये जो प्रदेश के समाज विज्ञान एवं समाज शोध की समस्याओं का सामना कर सके। योजना प्रक्रिया के अन्त तक पहुंचने तक, पूरे प्रदेश अरब बगावत से हिल गया था, जिनकी शुरूआत 2010 में हुयी। इन घटनाओं ने, अन्य वस्तुओं के साथ, सार्वजनिक स्थलों एवं वाद विवाद को खोलने में मदद की। जिसने बदलाव के लिये एक उम्मीद की किरण एवं नये अवसर का विकास किया। इसमें, यथास्थिति को प्रश्न करने की आवश्यकता एवं समाज के लिये नये दृष्टिकोण को विकसित करने की जरूरत – साथ ही अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का प्रतिनिधित्व करने के नवीन तरीके – प्रत्यक्ष हो गये। समाज विज्ञानों को महत्वपूर्ण बनाने का मुद्दा सड़कों पर निर्मित हुआ।

इसके परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र के कई देशों में नये सिरे से अधिनायकवाद, बढ़ती असुरक्षा और हिंसा के साथ युद्ध भी वृद्धि हुई। हालांकि बोये गये बीज वह लगातार पनप रहे थे, चाहे उनकी जड़ें अपने आपको निगरानी एवं दमन से बचाने के लिये मुड़ गयी। संस्थागत परिदृश्य का विस्तार हो रहा है एवं रूचिकर पहलें शोध–सक्रियावाद बंधन में संस्थागत साझा के लिये, शोध–जन क्षेत्र बंधन के लिये एवं समाज विज्ञानों में नवीन शैक्षणिक अवसर विकसित करने के लिये (उदाहरण–ऑनलाइन कोर्स, सामुहिक पाठन अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं में ''टीच–इनस्'') के नवीन अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश के भविष्य के लिये निशुल्क पूछ–ताछ एवं चर्चा का वातावरण विकसित करना एवं सुरक्षित करना अत्यावश्यक है।

> द ए.सी.एस.एस.

अरब समाज विज्ञान परिषद एक अलाभकारी सदस्यता वाली संस्था है जिसका मुख्यालय बेरूत, लेबनान में है। इसका कार्य समाज विज्ञानों को प्रदेश में एवं वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण करने के साथ अब ए. सी. एस. एस. के पास सात पूर्ण–कालिक एवं दो अंश–कालिक स्टाफ सदस्य हैं। उसने फिलीस्तीन में एक केन्द्र बिन्दु की स्थापना की है जिसमें एक अंश कालिक वरिष्ठ सलाहकार एवं अंशकालिक प्रशासनिक एवं वित्तीय कर्मचारी हैं। समान व्यवस्था के साथ एक दूसरा केन्द्र बिन्दु अल्जीरिया में, स्थापित करने की योजना है। ए. सी. एस. एस. ने चार नीधिकरण कार्यक्रम जो रिसर्च अनुदानों को, एक द्विवर्षीय संगोष्ठी, एक द्विवर्षीय रिसर्च फोरम (ग्रांट लेने वालों के लिये), एक वार्षिक व्याख्यान माला एवं सक्रिय वेबसाइट एवं सामाजिक मीडिया पहुँ, को प्रस्तावित करते है, चालू किये हैं। उसने तकरीबन 130 से ज्यादा अनुदान लेने वालों का नीधिकरण किया है। इसमें 270 से अधिक सदस्य है, एवं सदस्यों, अनुदानग्राहीयों एवं सामान्यतया समाज वैज्ञानिकों के लिये गतिकी अनुदान के साथ प्रशिक्षण एवं नैटवर्किंग अवसर भी प्रदान किये गये हैं।

अरब प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन के बावजूद भी, ए. सी. एस. एस. का मूल मिशन, उद्देश्य, मूल्य एवं दृष्टिकोण, जिसे 2008 की प्रथम संगोष्ठी में सूत्रबद्ध एवं दृढ़ किया गया था, आज भी उतने ही आवश्यक एवं ठोस है। (http://www.theacss.org/pages/mission देखें) ए. सी. एस. एस. का उद्देश्य, प्रदेश में सामाजिक शोध एवं विचार धारा की गुणवत्ता, लचीलापन, स्वतंत्रता एवं समाविष्टता को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार ए. सी. एस. एस. आवश्यकताओं का आकलन करने एवं प्रदेश के समाज विज्ञान समुदाय विशेषतः युवा विद्वान जो पी. एच. डी. अथवा पोस्ट डाक्टरेट स्तर पर है को अवसर प्रदान करने पर केन्द्रित रहता है।

ए.सी.एस.एस. का एक महत्पूर्ण प्रोजेक्ट है, अरब सोशल साइंस मॉनीटर प्रोजेक्ट (ए. एस. एस. एस.) जो प्रदेश की समाज विज्ञान की स्थिति का विश्लेषण करता है। डॉ. मोहम्मद बेमयेह द्वारा दी गयी प्रथम रिपोर्ट, ''सोशल साइंसिस इन अरब रीजन : फारमस् ऑफ प्रेसेनस्'' में उन्होंने सम्पूर्ण प्रदेश में संस्थागत एवं स्वतंत्र परिदृश्य का विश्लेषण किया है (http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf), जिसमें उन्होंने समाज विज्ञान विभागों एवं शोध केन्द्रों पर स्वतंत्र प्रादेशिक विकास का विवरण दिया है। यह रिपोर्ट, एम. ए. एवं पी. एच. डी. कार्यक्रमों, शोध पत्रिकायों, व्यवसायिक संगठनों एवं अन्य आधारभूत संरचना जो आलोचनात्मक एवं मजबूत विद्वता के उत्पादन के लिये आवश्यक है की कमी पर भी प्रकाश डालती है। सकारात्मक रूप में, यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसमें साहित्यिक कार्य, समाचार पत्र, प्रसिद्ध पत्रिकायें, टेलीविजन एवं अन्य मीडिया भी शामिल है, समाज विज्ञानों एवं विद्वता की न्यायसंगत स्वतंत्र उपस्थिति का भी विवरण देती है।

> अरब समाज विज्ञान : सीमांत या उभरता हुआ

अरब प्रदेश में समाज विज्ञानों की आधिकारिक उपेक्षा, विकास एवं आधुनिकता की ऐसी धारणा को प्रतिबिंबित करती है, जिसने लम्बे समय से शैक्षणिक एवं लोकोपकारी नियोजन पर शासन किया है। साथ ही पिछले कुछ दशकों से विज्ञान, चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग जैसे परम्परागत विषयों से वित्त, प्रबंधन एवं निजी क्षेत्र में विविधता की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव भी इस धारणा को प्रतिबिंबित करता है। समाज विज्ञान की दशा एवं स्थिति दोनों ही प्रदेश के शैक्षणिक व्यवस्था की कमी को उजागर करती है, विशेषतः उच्च शिक्षण संस्थाओं की कमियों पर प्रकाश डालते की हुए जहाँ बढ़ता हुआ नामांकन, गुणवत्ता के मूल्य पर आया है। निजी उच्च शिक्षा के विकास ने शैक्षणिक संस्थाओं में असंगति को बढ़ा दिया है एवं साथ ही समाज विज्ञानों का अधिक सीमांतीकरण किया है। इसी समय, सार्वजनिक नीति बहस में अकादमिक आवाज धीमी पड़ गयी, क्योंकि नीति निर्माता समाज वैज्ञानिकों पर दोषारोपण करते है, कि वो उन शोध प्रश्नों पर अनुसंधान करते हैं जो नीति के लिये अप्रासंगिक हैं, दूसरी तरफ समाज वैज्ञानिक शिकायत करते हैं कि नीति निर्माता उनके शोध निष्कर्षों को अनदेखा करते हैं।

यह तथ्य कि शैक्षणिक नीतियाँ, विकास की अवधारणा सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रतिबंध को चुनौतियाँ नहीं दी जाती है, इस प्रदेश के समाज विज्ञान समुदाय की कमजोरी और साथ ही एक स्वतन्त्र बौद्धिक क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न होने की उसकी असमर्थता को भी बताता है। ये कार्य हैं : आधिपत्य एवं सैद्धांतिक एजेंडा के स्पष्ट प्रमाण आधारित विकल्प देने की क्षमता, सार्वजनिक चर्चा एवं नीति निर्माण पर प्रभाव डालने की क्षमता, व्यावसायिक हित की रक्षा

>>

एवं प्रोत्साहित करने की क्षमता। समान रूप से महत्वपूर्ण हैं कि संस्थागत कमजोरियों के कारण, अरब के समाज वैज्ञानिक प्रादेशिक अथवा वैश्विक ज्ञान नेटवर्क में पूर्णतः सहभागी नहीं बन पाये है। अरब समाज विज्ञान समुदाय मुख्य अंतराष्ट्रीय समुदाय एवं जोशपूर्ण शोध नेटवर्क से अधिकतर अपवर्जित ही रहे है एवं वैश्विक स्तर पर ज्ञान के उत्पादान में प्रभावकारी रूप से अपना योगदान नहीं दे पाये है।

ये सभी मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करना ए. सी. एस. एस. का लक्ष्य है, इस तथ्य के बावजूद भी कि जब से इसकी नींव पड़ी है यह विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। इराक, लीबिया, सीरिया एवं यमन में उग्र होते संघर्ष के साथ ही मिस्र जैसी जगहों पर शोध वातावरण ज्यादा तनाव पूर्ण होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर विद्वानों एवं सक्रियतावादियों पर निगरानी एवं संत्रास बढ़ रहा है।

इसने ए. सी. एस. एस. की प्रादेशिक पहुँच को, उसकी विभिन्न देशों में गति–विधियों एवं कार्यक्रम आयोजित करने की क्षमता को सीमित कर प्रभावित किया है। इसके अलावा कुछ देशों में ए. सी. एस. एस. अनुदान ग्राहीयों पर दबाव डाला गया है कि वो अपनी योजनायें बदले और कभी कभी तो अपने प्रोजेक्ट के क्षेत्रकार्य घटक को भी कम करें। अंत में, वीसा के लिये नयी आवश्यक कार्यवाही एवं यात्राओं पर निषेध लागू होने से यात्रा करना और भी मुश्किल होता जा रहा है।

परन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद भी, या इनके कारण, अब यह ज्यादा जरूरी हो गया है कि ए. सी. एस. एस. प्रदेश के शोध कर्ताओं के लिये अपना समर्थन एवं अवसर प्रदान करना जारी रखे। साथ ही नेटवर्क का निर्माण करे एवं उसे ज्यादा मजबूत बनायें। हमें यह जानकर खुशी है कि अनुदानग्राही अपने शोध प्रोजेक्ट को करने के लिये दृढ़ है एवं उनमें प्रतिरोधक्षमता है। कार्यक्रम के लिये आवेदनों की संख्या एवं सहभागियों की संख्या में कमी नहीं आयी है एवं ए.सी.एस.एस. में रूचि निरंतर बढ़ रही है। लेबनान ऐसा स्थान है जहाँ आम तौर पर प्रादेशिक पारस्परिकता को सुगम एवं अकादमिक स्वतंत्रता भी जुटाई जाती है। ए. सी. एस. एस. अपने आधारभूत लक्ष्य एवं मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुये, बदलते हुये वातावरण में समायोजन के लिये जागरूक है। साथ ही अपने कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को नवीन तरीके से आयोजित करता है। हम प्रादेशिक एवं वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुये सहयोग एवं नेटवर्किंग का एवं साथ ही अरब समाज विज्ञान को पुनःर्जीवित करने के लिये प्रोत्साहन करने हेतु, एक माध्यम बनने का इंतजार कर रहे हैं। ■

सेतेनी शमी से पत्र व्यवहार हेतु पता
<shami@theacss.org>

> अरब समाज विज्ञान
बसन्त से पहले एवं परे

इदरिस जेबारी, अमेरिकन विश्वविद्यालय, बेरूत, लेबनान

अरब बगावत ने समाज विज्ञानों में क्या प्रभाव डाला है?

अरब जगत में समाज विज्ञान की स्थिति पर प्रथम रिपोर्ट में, समाज विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद बेमयेह ने वर्तमान अरब समाज विज्ञान की समस्या पर बात रखी : ज्ञान का ऐतिहासिक रूप से कमजोर एक क्षेत्र, जो संपन्न अशांत एवं जटिल सामाजिक वास्तविकताओं के साथ विद्यमान रहता है। अरब बसंत के पांच वर्ष्ज्ञ के उपरांत, काफी यह पूछने के लिये कि ज्ञान के क्षेत्र में इन परिवर्तनों को किस तरह पचाया के लिए काफी आलोचनात्मक अंतर है। यह रिपोर्ट किस प्रकार अरब समाज विज्ञानों द्वारा सामना की गयी चुनौतियों का चित्रण करती है? युवा अरब समाज वैज्ञानिक जन संलग्नता के संबंध में इस रिपोर्ट से क्या पाठ सीख सकते हैं?

> अरब समाज विज्ञानों की चुनौतियाँ

अरब ज्ञान के उत्पादन की अपेक्षाकृत कम सफल स्थिति को विद्वानों, कार्यकर्त्ताओं एवं छात्रों ने उचित रूप से प्रलेखबद्ध किया

> >

है। इस रिपोर्ट में बेमयेह ने सामान्य सामान्यकरण जैसे वैश्विक एकीकरण अथवा राजनीतिक अस्थिरता का अभाव से बच कर, उन संस्थागत संरचनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के जिन्होंने क्षेत्र को आकारित किया है।

पृथक्करण को चुनने की अपेक्षा, वो तर्क देते हैं, अरब समाज वैज्ञानिक ''कमजोर नेटवर्किंग क्षमता'' एवं ''अपनी रचनात्मक विरासत'' (साथ) से कटाव'' से ग्रस्त है। सामान्य रूप से, अरब के समाज वैज्ञानिकों का लक्ष्य वैश्विक मंच पर आवश्यक रूप से दृष्टिगोचर होना नहीं है, अपितु अपने शोध के उद्देश्य को समझाना एवं नीतियों को प्रभावित करना है। वर्तमान में सबसे जरूरी प्रश्न विषय का समाज एवं बाजार शक्तियों से अनबन जो उसके मूल्य एवं उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, के इर्द गिर्द घूमता है।

यह संस्थागत ध्यान अरब प्रदेश में समाज विज्ञान के लक्ष्य को सार्वभौमवाद एवं विशिष्टता के बीच तनाव के संबंध में स्थापित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बेमयेह का झुकाव सार्वभौमवाद की तरफ है। वे यह स्वीकार करते है कि इन विषयों का विकास पश्चिम के समाज विज्ञानों के साथ अंतक्रिया से हुआ है। यह एक विशिष्ट परम्परा का अनुसरण करते हुये हुआ है जिसे गत दशकों में स्थानीय अभिविन्यास एवं मूल टेक्सट के द्वारा पुनः खोजा गया है। बेमयेह ने अरब समाज विज्ञान के ''विशिष्टता'' और शोध पद्धतियों पर उसके प्रभाव के मुद्दे को टाला है, विशेषतः इसलिये क्योंकि वो अरब के समाज वैज्ञानिकों के लिये निरंतर सैद्धांतिक समस्या खड़ी कर रहा है (उदाहरण के लिये, गेल्नर के समर्थक एवं जनजातियों के उनके फ्रेमवर्क के विरूद्ध बोर्दिय का वर्ग केन्द्रित समाजशास्त्र) फिर भी, यह चुनाव वर्तमान के प्रदेश के समाज विज्ञान शोध को निरंतर आकार देता है। अरब के समाज वैज्ञानिक, विदेशी प्रकाशनों के माध्यम से दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो बदले में उनके शोध अभिविन्यास को चाहे वो विषय संबंधित हो अथवा प्रणाली संबंधित आकार देते हैं।

इस रिपोर्ट में बेमयेह स्वयं का प्रस्ताव ''विश्लेषण की ईकाई'' का पद्धति संबंधित मुद्दा उठाता है। क्या यह औचित्यपूर्ण है कि सामाजिक प्रघटना को अमूर्तता में अथवा सम्पूर्ण अरब प्रदेश के लिये अध्ययन किया जाय, फिर अपने निष्कर्षों का राष्ट्रीय एवं स्थानीय संदर्भों में देखा जाय ताकि पूर्ण एवं सामान्यकृत निष्कर्ष निकल कर आये? इसलिये वे 1980 के दशक में प्रदेश में समाज विज्ञानों के ''इस्लामीकरण'' का आह्वान करते हैं और सउदी अरब की विस्तृत चर्चा की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ ये तर्क विशेष रूप से दृष्टिगोचर हैं। यह वो सामाजिक संघर्ष, अथवा प्रवासी श्रम (जिसकी अभी देश में ज्यादा आवश्यकता है) पर शोध की अपेक्षा परिवार एवं अपराधशास्त्र पर प्रधानतः शोध होने पर टिप्पणी करने से पहले करते है। इसी प्रकार बेमयेह मुख्तार–अल हराच द्वारा अरबी की शोध पत्रिकाओं की अन्तर्वस्तु पर किये गये पृष्ठभूमि अध्ययन की भी चर्चा करते हैं। यह अध्ययन समाहित करता है एक क्रास राष्ट्रीय तुलना को, यह समझने के लिये कि किस प्रकार अरब के सांस्कृतिक शोध पत्रिकायें कार्य करती है, और यह पाया कि सैद्धांतिक अध्ययन शोध पत्रिका का 68% भाग बनाते है। फिर भी वो अपनी अंतिम टिप्पणी में कहते हैं कि उन्होंने यह पाया कि यह शोध पत्रिकाये विस्तृत अरब केन्द्र को अपनाने की अपेक्षा स्थानीय प्रदेश से मुख्य रूप से संबंधित है, बिना पर्याप्त रूप से यह समझाये कि इन विभिन्न निष्कर्षों को कैसे आकृति दी गयी है। इसी प्रकार ''शोध घनत्व'' (शोध केन्द्रों की संख्या का देश की जनसंख्या से विभाजन) शब्दावली का प्रयोग अरब प्रदेश का वर्गीकरण करने के लिये किया गया। परन्तु ''उनको पोषित करने वाले सामान्य वातावरण'' को विभिन्न संदर्भों में ''समाज विज्ञान में रूचि'' को समझाने वाले एक कारक के रूप में प्रदान किया। लेखक मानता है कि व्यापक परिदृश्य अकादमिक क्षेत्र पर तंत्र, प्रोत्साहन और दबाव, से आकारित होता है, परन्तु सूक्ष्म एवं विशिष्ट तत्वों की विस्तृत चर्चा नही हुयी है।

लेखक के स्वयं की स्वीकृति से, वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट के ''सर्वेक्षण'' का खाका इस प्रकार से तैयार किया गया कि वो आगामी प्रकाशनों के लिये प्रस्तावना का रूप ले जो विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा, 2010–15 काल से ज्यादा को कवर करेंगे, एवं शोध ग्रंथसूची प्रदान करेंगे। हालांकि यह रिपोर्ट इन सीमाओं के कारण अवरूद्ध हुयी, परन्तु यह क्षेत्र को चित्रित करने में एवं उन शक्तियों को पहचानने में जो उसे आकृति देती है सफल हुयी।

> समाज विज्ञान एवं अरब सामाजिक परिवर्तन

बेमयेह का समाज विज्ञान के संस्थागत संरचनाओं पर बेमयेह सर्वेक्षण रिपोर्ट का सबसे मजबूत योगदान में है। विशेषतः रूप से वह व्यावसायिकों के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है जो बदलते हुये जन अधिकार क्षेत्र को दिशा देने की चुनौती का सामना कर रहे हैं।

उनके आंकड़े अरब विश्वविद्यालयों को समाज विज्ञानों के ''प्राकृतिक गृह'' के रूप में चित्रित करते हैं (48% विश्वविद्यालय समाज विज्ञान के प्रोग्राम एवं डिग्री पाठ्यक्रम चलाते हैं)। विभागों का संतुलित वितरण–अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास–का कम से कम 436 शोध केन्द्रों के विस्तृत नेटवर्क, ज्यादातर देशों में पेशेवर समाजों एवं 217 अकादमिक शोध पत्रिकाओं ने समर्थन किया है। उनके आंकड़ों ने रूचिकर प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है : अरब के समाज वैज्ञानिकों को कई भाषाओं में महारत हासिल है एवं वे वैश्विक स्तर पर जुड़े हुये हैं : विश्वविद्यालय एवं शोध केन्द्रों के संदर्भ में अल्जीरिया एवं मिस्र प्रदेश के सबसे बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ये आंकड़े एक अन्य वास्तविकता को भी उजागर करते हैं : अरब के समाज वैज्ञानिक उत्पादन की अत्यावश्यकता एवं ज्ञान के संच के मध्य तनाव का सामना करते हैं साथ ही सामाजिक परिवर्तन को फैलाने का, संलग्न करने का एवं समर्थन करने का दबाव भी झेलते हैं। बेमयेह ने ''गैर–पारंपरिक कर्त्ताओं'' जैसे नागरिक समाज के बढ़ते महत्व की चर्चा करते हैं। ऐसा वे अन्य आकर्षक अनुभव पत्र में जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार स्वयंसेवी संस्थायें ''न केवल समाज विज्ञानों को रोजगार देती है अपितु वास्तविकता में उसे उत्पन्न भी करती है [.....] अपने उद्देश्यों की जांच करते हुये'' से निकाल कर सकते हैं। इसी प्रकार, जो अरब संदर्भ से परिचित है सम्पूर्ण – अरब संस्थायें जैसे बेरूत का अरब एकता अध्ययन केन्द्र या दोहा का अरब सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलीसी स्टडीज, जिनकी दृश्यता एवं पहुंच ने विश्वविद्यायलयों की दृश्यता एवं पहुँच को मात दी है, की महत्वता को समझते हैं। ये संस्थागत परिवर्तन, ज्ञान सामग्री के उत्पादन पर इस उद्विकास के प्रभाव पर तत्काल वाद विवाद की आवश्यकता की जरूरत पर जोर डालते हैं। अगर यह सही है, जैसा कि लेखक ने सुझाव दिया है, ये केन्द्र अकादमिक शोध के लिये विकल्प प्रदान नहीं कर सकते। क्या यह ''गैर–परम्परागत'' क्षेत्र एवं कर्त्ता ''औपचारिक'' समाज विज्ञानों के लिये संकट का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं?

नागरिक समाज एवं समाज विज्ञानों की भूमिका पर बेमयेह की टिप्पणी यह बताती है कि लेखक उनके योगदान को व्यवहारिक उद्देश्यों, प्रलेखबद्ध आंकड़ों को स्थापित करने में, यहाँ तक कि ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में भी मान्यता देते हैं, परन्तु स्पष्ट रूप से

>>

जिन्हें वो ''शैक्षणिक समुदाय'' कहते है को ''अर्द्ध शैक्षणिक समुदाय पर प्राथमिकता देते हैं।'' वो विद्वान और बुद्धिजीवी जो अपने कार्य पूरे करते हैं'' उनके अनुसार ये वे हैं जो विश्लेषणात्मक कठिन प्रणालियों में संलग्न रहते है, प्रगतिशील निष्कर्षों पर पहुँचते हैं एवं वैज्ञानिक विश्वसनीयता अर्जित करते हैं। ऐसा वे सामान्यतः ''कुछ दूरी से करते है [.....] अजाय इसके कि वे रोजमर्रा के संघर्षों के उतार–चढ़ाव में डूबे रहे और केवल राजनीतिक रूख का पुर्नउत्पादन करे जो हमें पहले से ज्ञात के सिवाय कुछ नहीं देते।'' इसी प्रकार उनके शोध पत्रिकाओं एवं समाचारपत्रों के अध्ययन में, यह उनकी निर्णय करने की कसौटी कि कौन सी लेख समाज विज्ञान लेबल के लिये उपयुक्त हैं, में ''गहराई'' जिसे ''जटिलता'' के रूप में समझा जाता है, समाहित है। उदाहरण के द्वारा बताते बेमलेह अपनी प्रणाली संबंधित चुनावों को न्यायसंगत दिखाने का, एक ऐसी शैली से जो नीति उन्मुख रिपोर्ट के बजाय अकादमिक शोध की शैली में ज्यादा स्मृतिपूर्ण है, में आगे रहते हैं।

ये प्राथमिकताएँ, अरब बगावत सहित ऐतिहासिक परिवर्तनों और अरब जगत में सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में बहस के प्रकाश में, विशेष तौर पर लेखक की क्रांतिकारी ज्ञानमीमांसीय परिवर्तन की दृष्टि का उदाहरण देती हैं। हम यह आपत्ति कर सकते हैं, कि लेखक अपने इस पुरातन विचारधारा के साथ लहरों के विरूद्ध तैर रहा है, जो कि ''क्रांति'' का निर्माण कर रहा है। विशेषतः उनका अरब के समाज वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी ''अरब बगावत पीढ़ी'' पर, अरब बगावत के परिवर्तन के प्रभाव को अपर्याप्त रूप से ध्यान में रखना। इसी पीढ़ी की सामाजिक संलग्नता ने उनकी आकांक्षाओं को परिवर्तन के लिये आकृति दी।

ऐसा भी नहीं है, कि बेमयेह के एकाकी, पृथक/अलग–थलग एवं दूरस्थ अरब समाज वैज्ञानिक का आदर्श रूप, अतीत में चुने हुए आसन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरब बगावत ज्ञान मीमांसा क्रांति के रूप में क्या ला सकता है? वह एक बदलाव ला सकता है, जहाँ वास्तविकता को विनाशकारी अप्रिय स्थान के रूप में देखने की जगह, प्रतिष्ठित जमीनी जैविकी से जुड़े हुये रूप में देखा जाय। यह शोध में मानक आकांक्षायें ला रहा है बजाय इसके कि समाजविज्ञान शोध को अनुशासित किया जाय। कठिन, अधिकतर ढीले फ्रेमवर्क के द्वारा।

> निष्कर्ष :

मोहम्मद बेमयेह के निष्कर्ष मेरे निष्कर्ष से भिन्न है। बेमयेह ने अरब के बगावत के आगे एवं पीछे देखते हुये एक वृहद क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, फिर भी रिपोर्ट में सिफारिशें देने के बजाय सिर्फ वृद्धि एवं चुनौतियाँ बतायी गयी हैं। उनके निष्कर्षों में, उन्होंने अरब के समाज वैज्ञानिकों की ''यह घोषणा करने से पहले कि उन्होंने समाज विज्ञानों को सुरक्षित आश्रय दिया है एवं उनके सभी विभिन्न रूपों में उपयोग किया है।'' और परिवर्तनों की मांग की है। यह अंतिम लक्ष्य है जो चक्रिय है। यह बताता है, कि अरब के समाज विज्ञानों को अभी भी यह पता लगाना है कि वर्तमान सामाजिक उथल–पुथल के प्रकाश में वे क्या अर्थ रखते हैं।

बजाय इसके कि हम समाज विज्ञानों की ''उपस्थिति'' पर ध्यान केन्द्रित करे, हमें ''स्थायित्व'', ''प्रतिरोध क्षमता'', ''संसक्तता'' अथवा ''जीवकिा'' से संबंधित ज्यादा गतिशील प्रश्न पूछने चाहिये। ''अरब बगावत पीढ़ी'' की दृष्टिकोण से बात करना, विषयों के संस्थागत हालात एवं पद्धति के बजाय, एक यह एक महत्वपूर्ण संकटकालीन स्थिति है जिसमें वे अपने आप को पाते हैं जो अरब जगत में समाज विज्ञानों को विशिष्ट बनाती हैं। अरब समाज वैज्ञानिकों द्वारा पहचान को खोजते समय हमारे पास एक अवसर है, कि कठिन शोध ऐजेंडा को डिजाइन करते समय हम कई समाज वैज्ञानिकों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। संभवतः यह रिपोर्ट एक ऐसे पथ पर हमें ले जायेगी जहाँ परिस्थिति की मांग के अनुसार सक्रिय वार्ता हो। ■

इदरिस जेबारी से पत्र व्यवहार हेतु पता <idrissjebari@gmail.com>

> मेकडानल्डाईजेशन और प्रोस्मपशन पर जार्ज रित्जर

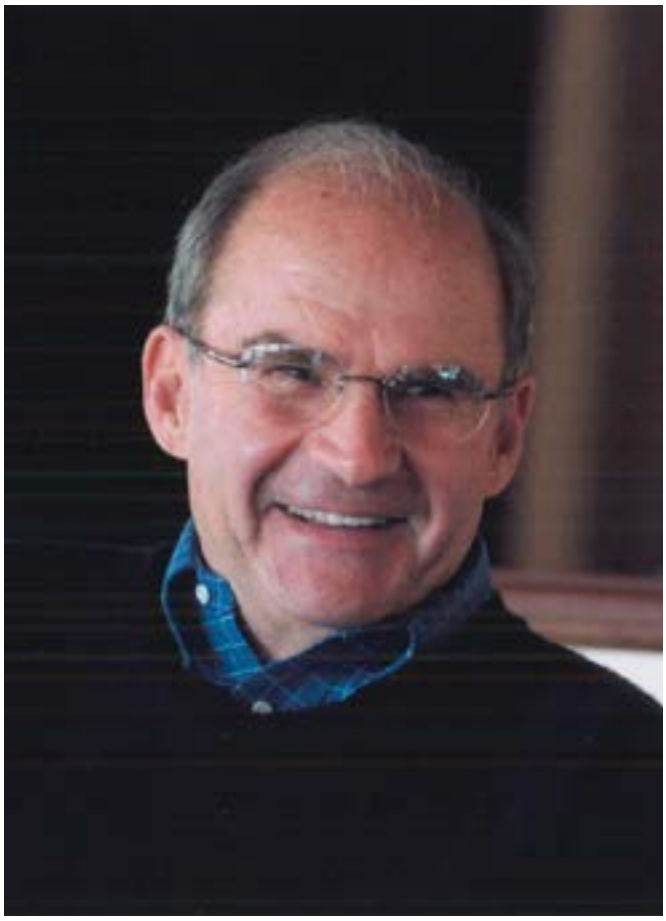

जार्ज रित्जर

जार्ज रित्जर वैश्वीकरण के सबसे अग्रणी विश्लेषणकर्ताओं में से एक है और मेरीलैण्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजशास्त्र के विख्यात प्रोफेसर हैं। **लेबिनोत कुनुशेव्की,** प्रिश्तीना विश्वविद्यालय, कोसोवो में एम. ए. समाजशास्त्र के एक छात्र, ने प्रभावशाली सामाजिक सिद्धांत पर एक प्रोजेक्ट के भाग के रूप में यह साक्षात्कार आयोजित किया। हम साक्षात्कार के अंश प्रकाशित कर रहे हैं।

एल. के. : प्रोफेसर रितजर आप ''मैक डोनल्डाइजेशन'' की अवधारणा के लिये प्रसिद्ध हैं; क्या आप इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के एक रूप में देखते हैं या सिर्फ बाजार में मुक्त प्रतिस्पर्धा के एक परिणाम की तरह?

जी. आर. : 1990 से ही मेरा बहुत सा काम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से संबंधित रहा है। द मैक डोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी (पहली बार 1993 में प्रकाशित) ''मैक डोनल्डाइजेशन'' को एक ऐसे बल के रूप में देखती है, जो अपने सिद्धांतों (दक्षता, पूर्वकथनीयता, परिकलनीयता और नियंत्रण, साथ ही इन तर्कसंगत प्रणालीयों से जुड़ी हुयी तर्कशून्यतायें भी) के साथ इसके अमरीकी आधार से दुनिया के कई देशों को निर्यात की जा रही हैं। ये मैक डोनाल्ड और अन्य अमेरिकन व्यापारों के वैश्वीकरण का आकार ले लेती है, परंतु और अधिक महत्वपूर्ण रूप से मैक डोनल्डाइजेशन के सिद्धांतों ने असंख्य स्थानीय व्यवसायों और कई दूसरे संगठनों (उदाहरण के लिये शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं) में अपना रास्ता बना लिया है।

मेरी पुस्तक एक्सप्रेसिंग अमेरिका : अ क्रिटिक ऑफ द ग्लोबल क्रेडिट कार्ड सोसाइटी (1995) में, मैंने अन्य प्रकार के सांस्कृतिक (और आर्थिक) साम्राज्यवाद की बात की है : अमेरिका के दूसरे सृजन, क्रेडिट कार्ड, का दुनिया भर में प्रसार। क्रेडिट कार्ड ने अमेरिकन–शैली के ऋण और उपभोक्ता संस्कृति के प्रसार में मदद की है, एक प्रघटना जिसके बारे में मैंने मेरी पुस्तक एनचांटिग अ डिसएंचाटेड वर्ल्ड : रेवोलूशानाइजिंग द मीन्स ऑफ कन्जम्पशन (1997) में और अधिक प्रत्यक्ष रूप से बात की है। उपभोग के साधनों का विचार मार्क्स के उत्पादन के साधनों के विचारों का ही विस्तार है। संयुक्त राज्य में उपभोग के प्रमुख स्थान फास्ट फूड रेस्तरां, शॉपिंग, मॉल, थीम पार्क (जैसे डिज्नी वर्ल्ड), लास वेगास–शैली के केसिनो, और विशाल जहाजों की विशेष क्रूजलाइनज्, हैं–ये सभी बाकी की दुनिया में निर्यात किये गये और साथ ही वांछित पर्यटक स्थल भी बन रहे हैं। उनके विशाल आकार और ''जादुई, लगभग धार्मिक, गुण मुझे अक्सर उन्हें ''उपभोग के गिरिजाघर'' कहने को कहते हैं। जैसे जैसे ये वैश्विक हुए उपभोग के गिरिजाघर अपने साथ एक प्रकार का हाइपर–कनज्यूमर समाज, जो कि संयुक्त राज्यों की विशेषता है, को ले कर आया है।

सबसे महत्वपूर्ण, कम से कम मेरे लिये, इस क्षेत्र में मेरी पुस्तक द ग्लोबलाईजेशन ऑफ नथिंग है। मैं ''नथिंग'' को ऐसे सामाजिक आकारों के रूप में जो कि केंद्रीय रूप से सोचे गये, नियंत्रित किये गये और विशिष्ट अर्न्तवस्तु में कमी लिये हुये है, के रूप में परिभाषित करता हूं। आमतौर पर, मैक डोनल्ड्स और इसके उत्पाद (उदाहरण के लिये बिग मैक) आदर्श उदाहरण हैं, लेकिन

> >

''नथिंग'' (विशेष रूप से, उपभोग के गिरिजाघरों के माध्यम से), अधिकाधिक वैश्विक हो रहा है। वैश्विक नथिंगनेस ने तेजी से ''समथिंग'' (स्थानीय रूप से सोचे गये, नियंत्रित किये गये और विशिष्टता से भरपूर) के स्थानीय रूपों का काफी हद तक हाशिये पर ला दिया है। इस प्रकार से, हमने अधिक से अधिक नथिंग से चिन्हित दुनिया विकसित कर ली है।

एल. के. : आपने वैश्विक उपभोग के विचारों का विश्वविद्यालय तक विस्तार कर दिया हैः आप आधुनिक विश्वविद्यालय के बारे में क्या कह सकते हैं?

जी. आर. : मैंने अक्सर आज के विश्वविद्यालय को मैक विशविद्यालय के रूप में उल्लेख किया है। अर्थात् इसने दक्षता, पूर्वकथनीयता, परिकलनीयता और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हुये शैक्षिक प्रक्रिया को मैक डोनल्डाइज्ड कर दिया है। इसने व्यापक शिक्षण प्रणाली के निर्माण में मदद की है परंतु इन प्रणालियों की तर्कसंगतता की तर्कहीनता यह है कि ये शिक्षा और शैक्षिक प्रणाली की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसमें, ये फास्ट फूड रेस्तरां के भोजन की गुणवत्ता से समानता रखती है (आपको बिग मैक मिल सकता है पर एक स्वादिष्ट मैक नहीं)। यह विश्वविद्यालयों में विरोध करने की बजाय यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में अधिक मदद करती है। मुझे लगता है कि मैक विश्वविद्यालय ज्ञान और साथ ही उसके प्रसार पर अधिकाधिक एकाधिकार कर रही हैं। मेरा सबसे नवीनतम काम ''प्रोसम्पशन'' पर है–''उत्पादन और उपभोग'' का एकीकरण। विद्यार्थी हमेशा ही ज्ञान के प्रोज्यूमरस रहे हैं–वे इसका उपभोग करते हैं और उन तरीकों में उत्पादन करते हैं जो उनमें से प्रत्येक के लिये अद्वितीय होते हैं। विद्यार्थी निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं होते हैं उसका जो इन प्रणालियों के पास देने के लिये होता हैं, परंतु उसके सक्रिय उत्पादक भी होते हैं जो उनमें रिसता है और ज्ञान जो उनसे बहता है।

एल. के. : आप इतने सफल लेखक रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सी नयी और दिलचस्प परियोजनायें मिली होंगी–क्या आप मुझे उनके बारे में संक्षेप में बता सकते हैं?

जी. आर. : पिछले दशक में मेरा अधिकांश कार्य प्रोसम्पशन पर रहा है। हम सदैव ही प्रोस्यूमरस रहे हैं–कभी भी सिर्फ उत्पादक और उपभोक्ता नहीं (आधुनिक ट्विचर का एक प्रकार जिसे हमें छोड़ने की जरूरत है)। हालांकि, आज प्रोस्यूमरस के लिये स्थान इंटरनेट है जहां हम साफ तौर पर ब्लॉगस में, फेसबुक पर, आदि पर प्रोस्यूम करते हैं। हम उपभोग के गिरिजाघर में अधिकाधिक प्रोस्यूमरस हैं, जहां हम ''उपभोक्ता'' के रूप में ज्यादा से ज्यादा ''काम'' करते हैं जो कि कभी सवेतन कर्मचारियों द्वारा किया जाता था (उस काम के बारे में सोचें जो हम फास्ट–फूड रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, IKEA आदि में करते हैं)। मैंने हाल ही में तर्क देना शुरू किया है कि हम ''प्रोस्यूमर पूंजीवाद'' के संसार में रह रहे हैं जहां पूंजीवादी सवेतन कर्मचारियों के जगह अवैतनिक या अपर्याप्त वेतन वाले प्रोस्यूमर्स को अधिक पसंद कर रहे हैं। उबर इसका एक अच्छा उदाहरण है : prosumers, जो उबर के लिये श्रम करते हैं, के उदय के साथ टैक्सी ड्राइवर गायब हो रहे हैं। जब हम Amazon.com पर किताबें मांगते हैं, हम सिर्फ किताबें (और अन्य उत्पाद) का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हमारे स्वयं के आर्डर का उत्पादन भी कर रहे होते हैं, वह भी बिना किसी वेतन के। नतीजतन, किताबघर और जो उनमें कार्य करते थे, खत्म हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, सवेतन कर्मचारियों को अवैतनिक prosumers से प्रतिस्थापित कर के नये पूंजीपतियों (मार्क जर्करबर्ग जेफ बेजोस) का उदय हुआ है और वे अरबपति बन गये हैं। ना सिर्फ प्रोस्यूमरस अवैतनिक हैं, बल्कि वे कर्मचारी नहीं है इसलिये उनको भत्तों, स्वास्थ्य बीमा और इसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। नयी तकनीकें (जैसे रोबोट्स) व्यापारों को अधिकाधिक प्रोस्यूमरस पर भरोसा करने के लिये सक्षम बना देंगे (या वे स्वयं प्रोस्यूमिंग मशीन की तरह प्रोस्यूम करने लगेंगे)। ■

जार्ज रित्जर से पत्र व्यवहार हेतु पता <gritzer@umd.edu>
लेबिनोत कुनुशेव्की से पत्र व्यवहार हेतु पता <labinotkunushevci@gmail.com>>

> अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र के साथ 40 वर्ष से अधिक

एडवर्ड. ए. तिरयाकियान, ड्यूक विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजशास्त्र का इतिहास (RC 08) समाजशास्त्रीय सिद्धांत (RC 16) और धर्म का समाजशास्त्र (RC 22) पर ISA की शोध समितियों के सदस्य

टोरोण्टो, कनाड़ा में आई. एस. ए. की कांग्रेस, 1974 का पोस्टर–प्रथम कांग्रेस जिसमें एडवर्ड तिरयाकियान ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परिषद् के साथ मेरे काफी लंबे जुडाव की कुछ यादें साझा करने के निमंत्रण का प्रति उत्तर देना एक प्रसन्नता की बात है। एक चेतावनी के रूप में अतीत की मेरी यादें ना तो पूर्ण हैं और ना ही समय से धूमिल होने के प्रति सुरक्षित है; पाठक निस्संदेह जेनिफर प्लाट के 'आइ. एस. ए. का संक्षिप्त इतिहास' 1948–1997 के उत्तम लेखों से लाभान्वित होंगे।

समाजशास्त्रीय सिद्धांत में मेरी समान रूप से प्रबल रूचि के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र ने मुझे हमेशा आकर्षित किया है। अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद से संबद्ध शिक्षक के रूप में, मैंने अध्यक्ष बनकर ASA की विश्वव्यापी सहयोग की समिति में सेवा दी है, जब पिछले अध्यक्ष रूरूबेन हिल, आई. एस. ए. के अध्यक्ष (1970–74) बन गये। रूयूबेन, जिन्हें बहुत आशा थी कि अमेरिकन समाजशास्त्र संयुक्त राज्यों के बाहर कार्य करेगा, ने मुझे आई. एस. ए. में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया। 1974 में मुझे पहला अवसर मिला, जहां रूयूबेन ने टोरंटों में आई. एस. ए. की आठवीं वर्ल्ड कांग्रेस के लिये रूसी समाजशास्त्रीयों को आमंत्रित किया था। आई. एस. ए. की बैठकों के तुरंत बाद, प्रतिनिधि ए. एस. ए. की बैठकों के लिये Montreal में आमंत्रित थे।

दोनों स्थितियों में, हमारी विश्वव्यापी सहयोग समिति ने विदेशी आगंतुकों के साथ एक कड़ी प्रदान की। मुझे विशेष रूप से रूसी समाजशास्त्रीयों के साथ बैठक याद है; शीत युद्ध के तनाव जल्द ही गायब हो गये, जैसे ही स्वागत का मैत्रीपूर्ण वातावरण सामूहिक सुगबुगाहट तक पहुंचा। रयूबेन हिल और ए. एस. ए. के अध्यक्ष पीटर ब्लाउ दोनों के लिये, संयुक्त बैठकें समाजशास्त्रीय कूटनीति की जीत साबित हुयी।

इसके बाद, मैंने आई. एस. ए. की आजीवन सदस्यता ले ली–सबसे अच्छे निवेशों में अब तक के किये गये निवेशों में से उपासला में नौवीं कांग्रेस में, मुझे याद है कि बैठकें कितनी विस्तृत थी और यह भी स्वीडन कैसे बहुत महंगा और बहुत आधुनिक दोनों था। और शायद क्योंकि उपासला (टोरंटो और स्टॉकहॉल्म के विपरीत) एक महानगर की बजाय एक विश्वविद्यालय कस्बा था, एक जगह जिसने बहुत थोड़े से भटकाव दिये पर जिसने विभिन्न देशों के विद्वानों से मिलने के कई मौके दिये–जो विद्वानों के

>>

अंतर्राष्ट्रीय समारोहों के लिये एक बड़ा आकर्षण था। उपासला के बाद, मैक्सिकों शहद में आई. एस. ए. की दसवीं कांग्रेस में बहुत सारे सत्र आई. एस. ए. की तीसरी आधिकारिक भाषा स्पेशिन में थे। ऐसा हमें लैटिन अमेरिकी विद्यार्थीयों के खुश होने के साथ एलेन टूरेन ने जोशपूर्ण तरीके से याद दिलाया गया। यह कहा जाना चाहिये कि टूरेन विभिन्न वर्ल्ड कांग्रेसों और फ्रांस में सेमिनारों के विकास दोनों में, विश्व समाजशास्त्र के एक प्रगतिशील चैंपियन रहे हैं।

हालांकि जब 1982 की बैठकें आयोजित हो रही थी, हमने वित्तीय अराजकता का अनुभव किया; मैक्सिकों के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि देश अपने ऋण भुगतान पूरा नहीं कर सका जिसने एक बड़े वित्तीय संकट को प्रोत्साहित किया। आई. एस. ए. प्रतिभागी मैक्सिकन बैंकों में डॉलर पाने में संघर्ष करने के लिये भाग दौड़ कर रहे थे, परंतु वित्तीय संचार टूट गया, जिसने विनिमय दरों पर व्यापक भ्रम पैदा किया गया। ना सिर्फ दरें रातोंरात बदल रही थी परंतु एक ही बैंक की शाखाओं में अक्सर नहीं पता था कि मैक्सिकों के केंद्रीय बैंक ने क्या दरें तय की है। आई. एस. ए. के कुछ सदस्य जो अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर पा रहे थे, ने पाया कि वे अपने होटल के स्टैंण्डर्ड कमरे को डीलक्स कमरे में पदोन्नत कर सकते थे क्योंकि पेसी गिर गया था और डॉलर बढ़ गया था। पर सभी को फायदा नहीं मिला और कई ने पहली उपलब्ध उड़ान से मैक्सिकों छोड़ दिया।

मेरी याददाश्त में ऐसे संकट के समय के दौरान होने वाली संभवतः यह एकेली ही बैठक थी। मुझे याद है। Madrid में बारहवीं कांग्रेस असाधारण गर्मी और एयर कंडीशनिंग के अभाव को छोड़कर अच्छी थी। वेलेफील्ड में तेरहवीं कांग्रेस (1994) में रिचर्ड ग्रेटहाफ ने कई पोलिश और अन्य पूर्वी यूरोपियन समाजशास्त्रीयों को आमंत्रित किया था जिन्होंने दमनकारी सोवियत शासन, जो कि 1991 में ध्वस्त हो गया था, के दौरान समाजशास्त्र को जीवित रखा था।

ग्रेटहॉफ जो कि गुणात्मक, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को समाजशास्त्रीय सैद्धांतिकरण के केंद्र में रखते थे, और मुझमें बहुत कुछ समान था, और मैं बहुत खुश था जब उन्होंने इन्टरनेशनल सोशियोलोजी के संपादक (1991–1996) का पदभार ग्रहण करते हुए, मुझसे संपादकीय मण्डल में बने रहने को कहा। मैं मण्डल में तब शामिल हुआ जब मार्टिन एल्ब्रो इसके पहले संपादक (1984–1990) बने और मैं एक ऐसी पत्रिका के लिये योगदानकर्ता और समीक्षक दोनों बनने में अत्यधिक प्रसन्न था, जो तुलनात्मक, अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र को प्राथमिकता देती है।

हालांकि आई. एस. ए. की सभी बैठकों में भाग लेना व्यवहारिक रूप से असंभव है (सेवानिवृत्ति के बाद यात्रा के खर्च के कारण और ए. एस. ए. के प्रति मेरी प्रतिबद्धताओं के कारण जो कि अक्सर उसी समय होती है जब आई. एस. ए. की) मैं हाल ही की कई कांग्रेसों में भाग ले पाने से खुश हूँ; मॉट्रियल (1998), ब्रिसबेन (2002), गोथेनबर्ग (2010), योकोहामा (2014) और हाल ही में वियना में आई. एस. ए. फोरम (2016)। दुनियाभार से पुराने दोस्तों से मिलने (दुर्भाग्य से घटती संख्या), नये वालों से मिलना और विभिन्न संस्कृतियों वाली जगहों पर नये समाजशास्त्रीय विचारों का सामना करना आज भी उतना ही ललचाने वाला है जितना तब था जब मैं अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परिषद में पहली बार शामिल हुआ था–और निश्चित रूप से यह मुझे 2018 में टोरंटों में उन्नीसवीं कांग्रेस में भाग लेने के लिये खींच लायेगा। ■

एडवर्ड तिरयाकियान से पत्र व्यवहार हेतु पता <durkhm@soc.duke.edu>

द्वितीय जापानी संपादकीय दल का परिचय

ग्लोबल डॉयलाग के पाठकों से द्वितीय जापानी संपादकीय टीम का परिचय कराना हमारे लिये बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे कार्य के दिसम्बर 2014 से शुरू होने से, 45 स्नातक विद्यार्थियों ने अनुवाद कार्य में भाग लिया था। ये सभी राष्ट्रीय मतस्य विश्वविद्यालय, जो कि 1941 में जापान में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त एक उच्च शिक्षा की सार्वजनिक संस्था के रूप में स्थापित की गयी थी, में पढ़ते हैं। संपादकीय बोर्ड में निम्नलिखित स्थायी सदस्य हैं–

सतोमी यमामोतो मत्स्य वितरण और प्रबंधन विभाग में अंग्रेजी और समाजशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने जापान महिला विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम. ए., शिकागो विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में एम. ए. और अर्बाना–चैम्पेन में इलियोनस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल की। उनका वर्तमान शोध संयुक्त राज्य अमेरिका में आक्रामक मछली प्रजातियों के समाजशास्त्रीय विवेचन पर केंद्रित है।

फूमा सेगिगुची खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में एक वरिष्ठ स्नातक विद्यार्थी हैं। वह यामागुची प्रीफेक्चर में पैदा हुये और चीबा प्रिफेक्चर में बड़े हुये। उन्होंने राष्ट्रीय मत्स्य विश्वविद्यालय से अवकाश ले रखा है और वर्तमान में केलिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिको एवं बुटे महाविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं। उनका फलसफा है कि असफलता सिखाती है। उन्हें तैरना, बेसबॉल खेलना और अंग्रेजी पढ़ना पसंद है।

युतारो शिमोकावा खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में स्नातक के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। वे वर्तमान में समुद्री उत्पादों के प्रभावी इस्तेमाल, प्रसंस्करण तकनीक और खाद्य घटकों को सीख रहे हैं। वे अनुवाद कार्य में भाग लेते हैं क्योंकि वे अंग्रेजी में अपनी पढ़ने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य खाद्य विज्ञान के बारे में अंग्रेजी में लिखे गये अकादमिक लेखों को पढ़ने में सक्षम होना है।

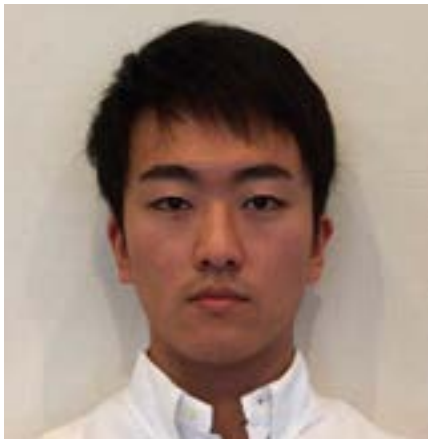

मसाकी योकोता खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में एक वरिष्ठ स्नातक विद्यार्थी है। उन्होंने 2014 और 2015 के बीच में ब्रिटेन में अंग्रेजी पढ़ी है और IELTS (International English Language Testing System) में 6.5 का स्कोर अर्जित किया। उन्हें बैडमिंटन खेलना और फुटबॉल देखना पसंद है। उनकी पसंदीदा फुटबॉल टीम लंदन की चेलसिया फुटबाल क्लब है। पूरी दुनिया की सैर पर जाना उनका सपना है।

तकाशी किताहारा खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में एक वरिष्ठ स्नातक विद्यार्थी हैं। वे अप्रैल 2017 में संसाधन प्रबंधन और खाद्य विज्ञान का स्नातक स्कूल, राष्ट्रीय मत्स्य विश्वविद्यालय में दाखिला लेंगे। उनकी आनर्स की थीसिस जापान में गैर–भक्षण मत्स्य पालन व्यापार उद्यमों के विकास का विश्लेषण करती है। वह अनुवाद कार्य में इसलिये भाग लेते हैं क्योंकि उन्हें मत्स्य पालन के अलावा नये विषयों को सीखने में आनंद मिलता है।

युकी नकानो प्रायोगिक जल–जीव विज्ञान विभाग में स्नातक की द्वितीय वर्ष की एक विद्यार्थी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय मत्स्य विश्वविद्यालय जाने का निर्णय लिया क्योंकि वे बचपन से ही जानवरों और मछलियों को पसंद करती थी। उनका भावी कैरियर अनिश्चित है, परंतु वह एक ऐसी नौकरी पाना चाहती है जो उनके प्रमुख विषय से करीब से जुड़ा हुआ हो। वह अंग्रेजी को प्राकृतिक जापानी में अनुवाद करने की चुनौतियों से कभी–कभी अभिभूत हैं, परतु फिर भी वह अनुवाद कार्य का हिस्सा बनने से खुश है क्योंकि यह कार्य उनकी अंग्रेजी दक्षता को सुधारने और जापानी भाषा पर बेहतर पकड़ बनाने में मदद करता है।